निदेशक मंडल
सितम्बर 12, 2008 को

BOARD OF DIRECTORS
As on September 12, 2008

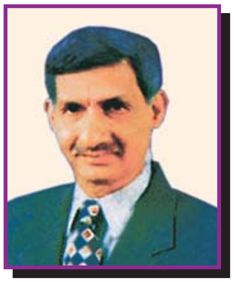

दया ष्ण भट्ट
D. K. Bhatt
अध्यक्ष/Chairman

बलविन्दर सिंह नकई
Balvinder Singh Nakai
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

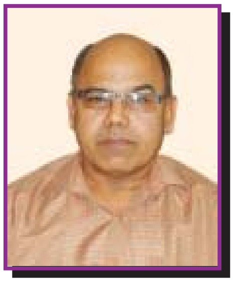

एच. पी. वर्मा
H.P. Verma
निदेशक/Director

एन. के. नगायच
N. K. Nagayaich
निदेशक/Director

जी. पी. त्रिपाठी
G. P. Tripathi
निदेशक/Director

नारायण लाल अहीर
N. L. Ahir
निदेशक/Director

प्रवीण अग्रवाल
Praveen Agarwal
कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी/
Acting Chief Executive

पंजीकृत कार्यालय / REGISTERED OFFICE

53–54, गोवर्धन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
53-54, Goverdhan, Nehru Place, New Delhi - 110 019

वर्तमान पता / PRESENT ADDRESS

401–402 लक्ष्मी भवन, 72 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
401-402 Laxmi Bhawan, 72 Nehru Place, New Delhi - 110 019

लेखा परीक्षक / AUDITORS

मैसर्स एस.पी. चौपड़ा एण्ड कम्पनी, 31–एफ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
M/s S.P. Chopra & Co., 31-F, Connaught Place, New Delhi - 110 001

निदेशक मंडल

सितम्बर 12, 2008 को

1.	श्री डी. के. भट्ट	अध्यक्ष
2.	श्री बलविन्दर सिंह नकई	उपाध्यक्ष
3.	श्री एच. पी. वर्मा	निदेशक
4.	श्री एन. के. नगायच	निदेशक
5.	श्री जी. पी. त्रिपाठी	निदेशक
6.	श्री नारायण लाल अहीर	निदेशक
7.	श्री प्रवीण अग्रवाल	मुख्य कार्यकारी

BOARD OF DIRECTORS

As on September 12, 2008

1.	Shri D. K. Bhatt	Chairman
2.	Shri B. S. Nakai	Director
3.	Shri H. P. Verma	Director
4.	Shri N. K. Nagayaich	Director
5.	Shri G. P. Tripathi	Director
6.	Shri Narayan Lal Ahir	Director
7.	Shri Praveen Agarwal	Chief Executive

सितम्बर 12, 2008 को

As on September 12, 2008

पूर्व अध्यक्ष/Ex-Chairman

डा. वी. कुमार
(अक्टूबर 22, 1993 – फरवरी 11, 2003)
Dr. V. Kumar
(Oct. 22, 1993 - Feb. 11, 2003)

पूर्व मुख्य कार्यकारी/Ex-Chief Executives

स्व. डा. ओ. पी. गौड़
(अक्टूबर 22, 1993 – अगस्त 31, 2000)
Late Dr. O. P. Gaur
(Oct. 22, 1993 - Aug. 31, 2000)

श्री अशोक आलम्बेन
(सितम्बर 01, 2000 – सितम्बर 03, 2002)
Sh. Ashok Alambain
(Sept. 01, 2000 - Sept. 03, 2002)

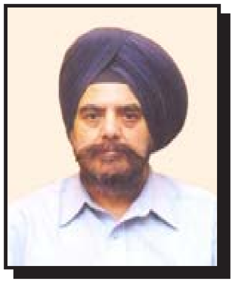

स्व. डा. पी. एस. मरवाहा
(सितम्बर 03, 20002 – सितम्बर 02, 2008)
Late Dr. P. S. Marwaha
(Sept. 03, 2002 - Sept. 02, 2008)

परियोजना क्षेत्र

IFFDC

PROJECT AREA

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड

संस्था

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा संवर्द्धित इण्डियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट को–ऑपरेटिव लिमिटेड़ (आई.एफ.एफ.डी.सी.) का पंजीकरण अक्टूबर 22, 1993 को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत किया गया। इफको की परिकल्पना के अनुसार यह वृहद स्तर पर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक प्रतिमान संस्था के रूप में उभर कर आयी है।

मिशन

"संगठित प्रयासों से चिरन्तर प्राकृतिक संसाधनों के विकास द्वारा लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का उत्थान"।

उद्देश्य

- परिस्थितिकीय संतुलन एवं अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने हेतु बंजर भूमि का विकास।
- एकीकृत खेती पद्धतियों द्वारा ग्रामीण समुदाय व बंजर भूमि का विकास।
- सहकारी समितियों व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों की सहभागिता बढाना व महिला सशक्तिकरण करना।
- पी.एफ.एफ.सी.एस. व एस.एफ.एफ.सी.एस. के सदस्यों को आर्थिक, तकनीकी व प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराना।

पंजीकृत कार्यालय

संस्था का पंजीकृत कार्यालय 53–54, गोवर्धन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 है।

IFFDC LTD.

The Organisation

Indian Farm Forestry Development Co-operative Ltd. (IFFDC) promoted by Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. (IFFCO) was registered on 22nd October 1993 under the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984. As visualized by Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited (IFFCO). it has become a model for large scale adoption in the field of afforestation on wasteland and rural development.

Mission

"To enhance the socio-economic status of the people through collective action by Sustainable Natural Resources Development"

Objectives

- Wasteland development for ecological balance and generate additional employment.
- Development of wasteland and rural community through Integrated Farming Systems approach.
- People's involvement including women empowerment through co-operatives/SHGs.
- To provide Financial, Technical & Extension services to the members of PFFCS and SFFCS.

Registered Office

Registered office of IFFDC is 53-54, Goverdhan, Nehru Place, New Delhi -110 019.

14वीं वार्षिक आम सभा बैठक प्रगति में।

14th Annual General Body Meeting in Progress.

सदस्यता

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस) आई.एफ.एफ.डी.सी. के सदस्य हैं। 31 मार्च, 2008 तक 163 समितियाँ आई.एफ.एफ.डी.सी. की सदस्य हैं।

शेयर पूंजी

100 करोड़ रू. की अधिकृत शेयर पूंजी के विपरीत 31.03.2008 तक इसकी अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी 9.28 करोड़ रू. है। इसमें से 8.60 करोड़ रुपये की अंशदान पूँजी इफको की 0.10 करोड़ रु. एन.सी.डी.सी. तथा 0.58 करोड़ रु. पी.एफ.एफ.सी.एस. तथा पी.एल.डी.सी.एस. की है।

Membership

Indian Farmers Fertiliser Co-operative Ltd. (IFFCO), National Co-operative Development Corporation (NCDC), Primary Farm Forestry Co-operative Societies (PFFCS), and Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS) are its members. As on March 31, 2008, 163 Societies are members of IFFDC.

Share Capital

The subscribed and paid-up capital as on 31.03.2008 is Rs. 9.28 crores against the authorized share capital of Rs.100 crores. Out of this, Rs. 8.60 crores have been contributed by IFFCO, 0.10 crore by NCDC and 0.58 crore by PFFCS and PLDCS.

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित महगांव प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति लि., जिला कौशाम्बी (उ.प्र.) का दृश्य।

View of IFFDC promoted Mahgaon Primary Farm Forestry Cooperative Society Ltd, Distt. Kaushambi (U.P.).

पुरस्कार

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने एक संस्था के रूप में निम्न प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं :

1. वृक्षारोपण तथा बंजरभूमि विकास में विशिष्ट कार्य करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, 1999"**। संस्था द्वारा संवर्द्धित पाँच प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (राजस्थान में सांगवा व रख्यावल, उत्तर प्रदेश में कटारी व मड़वा तथा मध्य प्रदेश में करैया) ने भी विभिन्न वर्षों में बंजर भूमि विकास व वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु यह पुरस्कार जीता है।
2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिये भारतीय व्यापार मंडल, मुंबई द्वारा **"पर्यावरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास पुरस्कार 2002"** शीर्षित आई.एम.सी. डायमण्ड जुबली एण्डोवमेण्ट ट्रस्ट अवार्ड।
3. **"उत्कृष्ट सामूहिक नागरिकता तथा स्थायित्व" योग्य पहलों हेतु किये गये प्रयत्नों के लिए टेरी (द एनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट)** द्वारा इसके सामूहिक सामाजिक दायित्व पुरस्कार 2004–05 एवं 2007 के अन्तर्गत दो बार प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है।
4. अध्यक्ष आई.एफ.एफ.डी.सी को अर्थ मैटर फाउंडेशन द्वारा देश में वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि का विकास करने हेतु **"अर्थ मैटर"** अवार्ड प्रदत्त किया गया।
5. एमिटी इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल (एमिटी यूनीवर्सिटी), नोएडा ने बंजर भूमि में वन रोपण के विशिष्ट योगदान, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के प्रोत्साहन एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में योगदान के लिए **"एमिटी कारपोरेट एक्सीलेन्ट अवार्ड 2008"** प्रदत्त किया गया।

Awards

IFFDC as an organization has won following prestigious awards:

1. **"Indira Priyadarshini Vrikashamitra Puraskar 1999"** conferred by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India for excellence in afforestation and wasteland development. Five of its promoted PFFCS (Sangwa & Rakhyawal in Rajasthan, Katari & Madwa in U.P. & Karaiya in M.P.) have also won this Puraskar for their outstanding work in afforestation & wasteland development in different years.
2. IMC Diamond Jubilee Endowment Trust Award, titled **"Environment, Agriculture and Rural Development Award 2002"** conferred by Indian Merchants' Chamber, Mumbai for outstanding contribution to the cause of promoting the growth of rural economy.
3. Twice the "Certificate of Appreciation" of **"Corporate Social Responsibility" Award 2004-05 and 2007** conferred by "The Energy and Resource Institute" (TERI), New Delhi for efforts made by IFFDC towards initiatives for Corporate Citizenship and sustainability.
4. **"Earth Matter"** award conferred on Chairman IFFDC by Earth Matters Foundation for integrated development of wastelands through afforestation in the country.
5. **"Amity Corporate Excellence Award 2008"** conferred by Amity International Business School (Amity University), Noida for its outstanding contribution towards afforestation on wasteland, environment conservation and promoting the growth of rural economy.

डॉ. पी.एस. मारवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी., नई दिल्ली "एमिटी कारपोरेट एक्सीलेन्ट अवार्ड 2008" प्राप्त करते हुए।

Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC, New Delhi receiving the "Amity Corporate Excellence Award 2008".

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय सहकारी बन्धुओं

इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेन्ट कोआपरेटिव लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से मुझे आपकी समिति की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। इस रिपोर्ट में आपकी समिति के वर्ष 2007–08 के कार्यनिष्पादन का लेखा–जोखा तथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित लेखे मय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2007–08 आपकी समिति के लिये उल्लेखनीय उपलब्धियों वाला रहा है। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को जारी रखते हुए समिति ने इस वर्ष भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र विशेषकर गरीबों, महिलाओं एवं संसाधन विहीन आदिवासियों के आजीविका विकास, पिछड़े समुदाय के क्षमता विकास तथा पर्यावरण सुधार लाने हेतु विभिन्न परियोजनाओं जैसे :– प्रक्षेत्र वानिकी परियोजनाऐं, उड़ीसा में इफको द्वारा सहयोग प्रदत्त "ग्रामीण विकास के माध्यम से आजीविका सुधार" (लिरड) तथा पश्चिमी बंगाल में "ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना" (आर.एल.डी.पी.); उत्तर प्रदेश में स्टेट इंनोवेशन्स इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेस (सिफ्पसा) के माध्यम से यू. एस.आई.डी. द्वारा वित्तपोषित "प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना" एवं आयडा के सहयोग से "उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना" (यू.पी.एच.एस.डी.पी.), झारखण्ड में "सहकारी विकास माध्यम से आजीविका सुधार"; मध्य प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के सहयोग से "इण्डस बाल श्रम परियोजना, राजस्थान ने विश्व बैंक के सहयोग से "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" (डी.पी.आई.पी.); उत्तराखण्ड में इफाड के सहयोग से "हिमालय हेतु उत्तरांचल आजीविका उत्थान परियोजना" तथा पर्यावरण व वन मन्त्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थतिकीय विकास बोर्ड के सहयोग से सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण; मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से नरेगा के अन्तर्गत समन्वित जलग्रहण विकास परियोजनाऐं, छत्तरपुर व श्योपुर (म.प्र.) के माध्यम से श्रेष्ठ कीर्तिमान के पथ पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को जारी रखा।

वर्ष के दौरान, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने सिफ्पसा के सहयोग से जिला इलाहाबाद, उ.प्र. के फूलपुर और बहेरिया

Directors' Report

Honourable cooperators

On behalf of the Board of Directors of Indian Farm Forestry Development Co-operative Ltd., it is my proud privilege to place before you the 15th Annual Report of your society. The report presents the performance of your society for the financial year 2007-2008 along with the Audited Statement of Accounts for the year ending March 31, 2008 and the Auditor's Report thereon.

It gives me immense sense of satisfaction that the year 2007-2008 has been a year of remarkable achievements for your society. In the line with its excellent track record, the society continued to maintain high standards of performance in the field of rural development with special emphasis towards livelihood enhancement of poor, women and resource less tribals, capacity building of underprivileged community and environment upgradation etc through its various ongoing projects viz; Farm Forestry Projects; "Livelihood Improvement through Integrated Rural Development" (LIIRD) in Orissa and "Rural Area Livelihood Development Project" (RLDP), West Bengal supported by IFFCO; "Reproductive & Child Health Project" funded by USAID through State Innovation in Family Planning Services Agency (SIFPSA) and "Uttar Pradesh Health Systems Development Project" (UPHSDP) by IDA in U.P.; "Livelihood Improvement through Cooperative Development" (LICD) in Jharkhand; "Indus Child Labour Project" supported by International Labour Organization (ILO) in M.P.; "District Poverty Initiative Projects" (DPIP) supported by World Bank in Rajasthan; "Uttaranchal Livelihood Improvement Project for Himalayas" (ULIPH) supported by International Fund for Agriculture Development (IFAD) in Uttrakhand; Afforestation on community land supported by National Afforestation and Eco Development Board (NAEB); Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, and Integrated Watershed Development Projects at Chhattarpur & Sheopur supported by Govt. of M.P. under NAREGA.

During the year, IFFDC diversified its activities further by undertaking projects on Clinic Based

खण्डों हेतु "चिकित्सालय आधारित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं; मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, प्रबंधन व क्षमता निर्माण; नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित करैया सुरखी जलग्रहण विकास परियोजना, सागर (म.प्र.), नाबार्ड, रायपुर (छ.ग.) के सहयोग से जल ग्रहण विकास परियोजना (छत्तीसगढ़); इफको छत्तीसगढ़ पावर लि. (आई.सी.पी.एल.) के सहयोग से वृक्षारोपण, औषधीय पौधों की खेती तथा सामाजिक विकास से आजीविका सुधार परियोजना; इफको के सहयोग से समग्र ग्रामीण विकास परियोजना, शिवगंगई (तमिलनाडु) एवं समग्र ग्रामीण विकास परियोजना, छिन्दवाड़ा (म.प्र.); नाबार्ड की वित्तिय सहायता से जलग्रहण विकास परियोजना, निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश); वाडी परियोजना, प्रतापगढ़ (राजस्थान) एवं कवर्धा (छत्तीसगढ़) का संचालन कर अपनी गतिविधियों में विविधीकरण किया।

समिति को आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली के माध्यम से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेशी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) के उदयपुर में क्रियान्वयन हेतु महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के साथ एक कन्सोर्शियम पार्टनर के रूप में चयनित होने पर गर्व है।

आपकी समिति के विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पीछे आई.एफ.एफ.डी.सी. की अति उत्साही, कर्मठ एवं प्रतिभावान कर्मचारियों की समर्पित टीम को मैं बधाई देता हूँ।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2007–08 में आई.एफ.एफ.डी.सी. संस्था द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत हैं।

Reproductive Health Service for Phulpur & Bahariya Block in Allahabad district of UP supported by SIFPSA; Formation, management and Capacity Building of SHGs under Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana of Govt. of M.P.; NABARD funded Karaiya-Surkhi Watershed Development Project Sagar (MP); Watershed Development Project, Chattishgarh supported by NABARD Raipur (Chattisgarh); Livelihood Improvement through Afforstation, Cultivation of Medicinal Plants and Social Development Project, supported by IFFCO-Chhattisgarh Power Ltd. (ICPL); Integrated Rural Development Project, Shivagangai (Tamil Nadu) and Integrated Rural Development Project, Chhindwara (M.P.) supported by IFFCO; Watershed Development Project, Nizamabad (Andhra Pradesh); Wadi Project Pratapgarh (Rajasthan) & Kuwardha (Chhattisgarh) with Financial support of NABARD.

The society is proud for being selected as a consortium partner with Maharana Pratap University of Agricultural & Technology, Udaipur for implementing the prestigious National Agricultural Innovation project (NAIP) at Udaipur (Rajasthan) through ICAR New Delhi.

I congratulate the highly motivated, talented and dedicated professional team of IFFDC, which has been the driving force behind successful implementation of various projects and programmes of your society.

The highlights of the achievements made by IFFDC in its various projects during the year 2007-2008 are being presented in this report.

समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनाऐं
INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECTS

I. समन्वित प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना

विकास व प्रसार गतिविधियों के लिए विख्यात इफको ने बंजर भूमि के सुधार, समुदाय के लिए रोजगार सृजन व ईंधन, चारा तथा लकड़ी की व्यवस्था करने हेतु 1986–87 में बंजर भूमि विकास पर एक पायलेट परियोजना शुरू की थी। आई.एफ.एफ. डी.सी. द्वारा इंडिया कनाडा एन्वायरमेंट फेसिलिटी (आई.सी.ई. एफ.) और इफको की वित्तिय सहायता से 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च, 2002 के दौरान प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों के संवर्द्धन के माध्यम से बंजर भूमि की उत्पादकता में सुधार तथा समन्वित प्रक्षेत्र वानिकी, कुशल जल प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण पद्धति को अपनाकर ग्रामीण गरीबों को लाभ प्रदत्त करने हेतु वृहद स्तर पर सहभागी प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना का भी क्रियान्वयन किया गया।

परियोजना का कार्य क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद व चित्तोड़गढ जिलों, मध्य प्रदेश के सागर, टीकमगढ़ और छत्तरपुर जिलों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, लखनऊ और उन्नाव जिलों तक विस्तारित था। इस परियोजना के लक्ष्य समूह लगभग 90 प्रतिशत में छोटे और सीमान्त कृषक और भूमिहीन शामिल थे। अप्रैल 1987 से मार्च 2002 तक आई.एफ. एफ.डी.सी. द्वारा (28,287 की सदस्यता के साथ) 145 प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियां (पी.एफ.एफ.सी.एस.) संवर्द्धित की गयीं, जिन्होंने 26,208 हैक्टे. बंजर भूमि (10,955 हैंक्टे. उ.प्र. में, 6,271 हैंक्ट. म.प्र. में एवं 8,982 हैक्ट. राज. में) पर विविध प्रजातियों जैसे शीशम, सुबबूल, बबूल, सफेदा, करंज, आंवला, अमरूद इत्यादि का वृक्षारोपण किया।

वर्ष के दौरान समितियों द्वारा 3.78 लाख वानिकी पौधे, मुख्यत: सफेदा, बिलायती बबूल, नीम, शीशम, बबूल (2.18 लाख उ.प्र. में, 0.85 लाख म.प्र. में एवं 0.75 लाख राज. में) रोपित किए गये। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की समितियों द्वारा 8,483

महाराज की नेतावल प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) में उपस्थित महिला सदस्याऐं।

Women members present at Maharaj Ki Netawal Primary Farm Forestry Cooperative Society, Dist. Chittorgarh (Raj.)

I. INTEGRATED FARM FORESTRY PROJECT

IFFCO, well known for its extension and rural development activities launched a Pilot Project on wasteland development in 1986-87 to improve the degraded land, generate employment and provide fuel, fodder and timber to the community. IFFDC also implemented participatory farm forestry development project at a large scale with the financial assistance of India Canada Environment Facility (ICEF) and IFFCO, during April 1995 to 31st March, 2002 to improve productivity of the degraded lands and provide benefits to the rural poor by adopting integrated farm forestry, efficient water management and energy conservation system by promoting PFFCS.

The area of operation of the project was spread over Udaipur, Rajsamand and Chittorgarh districts in Rajasthan state, Sagar, Tikamgarh and Chattarpur districts in Madhya Pradesh state and Sultanpur, Allahabad, Raibareily, Pratapgarh, Kaushambi, Lucknow and Unnao districts in Uttar Pradesh state. The target groups were of small and marginal farmers and the landless that comprised about 90 percent. Since April 1987 to March 2002, 145 Primary Farm Forestry Cooperative societies (PFFCS) were promoted by IFFDC (with the membership of 28,287) which have undertaken plantation on an area of 26,208 ha. wastelands (10,955 ha. in UP; 6,271 ha. in MP and 8,982 ha. in Rajasthan) with 93.54 lakh plants (U.P.- 33.57 lakh, M.P.- 39.01 lakh and Raj.- 20.96 lakh) of such diverse species as Shisham, Subabool, Accacia, Eucalyptus, Karanj, Aonla, Guava, etc.

During the year, 3.78 lakhs forestry plants (2.18 lakhs in UP, 0.85 lakhs in MP and 0.75 lakh in Rajasthan) mainly eucalyptus, prosopis, neem, shisham, babool. In addition 8483 horticulture plants

फलदार पौधों जिनमें मुख्यतः आंवला, आम, अमरूद, लीची इत्यादि का भी रोपण भी किया गया। 28 समितियों (26 उ.प्र., 1 म.प्र. व 1 राज. में) को नर्सरी उगाने के कार्य को एक उद्यम के रूप में लिये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इन समितियों द्वारा बहुउद्देशीय प्रजातियों की 11.93 लाख पौध (10.93 लाख उ.प्र. में, 0.90 लाख म.प्र. में एवं 0.10 लाख राज. में) तैयार की गयी जिन्हें वन विभाग, भूमि सुधार निगम, इफको, कोरडेट, सरकारी ऐजेन्सियों आदि को विक्रय किया जा रहा है। रोजगार के लिए 51.01 लाख कार्यदिवस सृजित किए गये, जिनमें से महिलाओं का योगदान 20.91 लाख (41%) कार्य दिवस रहा।

8,497 सदस्यों के साथ 840 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये। सदस्यों को आय अर्जन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु रिवाल्विंग फंड से आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान कर निरन्तर सहायता की जा रही है। इस प्रकार के ऋण से लाभान्वित 2,785 सदस्यों ने विभिन्न लघु–उद्यम जैसे सिलाई एवं हथकरघा, पंसारी की दुकान, आटा चक्की, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अनाज व्यवसाय, साईकिल मरम्मत दुकान, मधु मक्खी पालन इत्यादि शुरू कर दिये तथा नियमित आय अर्जन कर रहे हैं।

परियोजना गतिविधियों से परिस्थितिकीय संतुलन, समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से गरीब ग्रामीणों के लिए रोजगार उत्पन्न करने तथा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायता मिली है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने भारत सरकार के राष्ट्रीय तिलहन एवं वानस्पतिक तेल विकास बोर्ड (नोवोड) की वित्तिय सहायता से जैट्रोफा की कृषि को भी संवर्द्धित किया तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में पी.एफ.एफ.सी.एस. के माध्यम से किसानों के खेतों पर 60 हेक्टेयर बंजर जमीन पर 1.50 लाख जैट्रोफा (रतनजोत) पौधों का रोपण कर जैट्राफा वृक्षारोपण की उन्नत तकनीकी को प्रदर्शित किया। आई.एफ.एफ.डी.सी. की तकनीकी सहायता से इस वृक्षारोपण का अच्छी तरह से रख–रखाव किया जा रहा है। इन पौधों पर फल आना प्रारम्भ हो गया है जिससे समिति सदस्यों की आय में वृद्धि होगी। अतिरिक्त आय अर्जन करने के लिए समितियों द्वारा इफको की सहायता से 6.34 लाख जैट्रोफा पौधे लगाये गये। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने छत्तीसगढ़ जिले के राजनांदगांव तथा महासमुंद के इफको अंगीकृत गांवों में 40 हैक्टे. बंजर भूमि पर जैट्रोफा पौध रोपण एवं इसके

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बंजर भूमि पर विकसित सघन वन का दृश्य।

A view of Dense Forest Developed on Wasteland by IFFDC.

mainly aonla, mango, guava, Litchi etc. have also been planted by the PFFCS of U.P. 28 PFFCS (26 in U.P., 1 in M.P. and 1 in Rajasthan) have also been facilitated to take up nursery raising as an enterprise. These PFFCS have raised11.93 lakhs saplings (10.93 lakhs in U.P., 0.90 lakh in M.P. and 0.10 lakh in Raj.) of multipurpose species which are being sold to forest dept., Land Reclamation Corporation, IFFCO, CORDET, Govt agencies etc. Employment of 51.01 lakhs workdays were generated, out of which 20.91 lakhs (41%) workdays contributed by women.

840 Self Help Groups have been formed with 8,497 members. The revolving fund continues to help the members by providing need based loans to take up income generation activities. 2,785 members who benefited by availing such loans have started various micro-enterprises like Tailoring and Handloom, Grocery shop, Flour Mills, Goatry, Poultry, Grain trading, Cycle repairing shops, Bee keeping etc. and are earning regular income.

The project activities have helped to bring about ecological balance, generate employment for the rural poor through Integrated Farming Systems and improve their socio-economic status.

IFFDC has also promoted Jatropha cultivation with financial assistance of National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board (NOVOD), Govt. of India and planted 1.50 lakh jatropha (Ratanjot) saplings in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan through PFFCS on farmer's fields in an area of 60 hact. and demonstrated improved technology of Jatropha plantation. The plantations are being well maintained under the technical guidance of IFFDC. The plants have started bearing fruits, which shall add to the income of PFFCS members. So far 6.34 lakh Jatropha saplings have been planted by PFFCS with the support of IFFCO to generate additional income. IFFDC has provided technical inputs for jatropha plantation and its maintenance in 40 hectares of wasteland in IFFCO adopted villages in Rajnandagaon and

रखरखाव के लिए तकनीकी सेवाऐं प्रदान की तथा किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न समितियों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों व एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन भी किया।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने तहसील मुख्यालय सालोन (जिला रायबरेली) में कृषि–वानिकी को वृहद स्तर पर प्रोत्साहित करने तथा कृषक समुदाय में इसकी जागरूकता पैदा करने हेतु एक कृषि वानिकी सेवा केन्द्र आरम्भ किया, जो किसानों को वानिकी बीज, इफको उर्वरक एवं जैव–उर्वरक आदि आदानों के साथ–साथ कृषि–वानिकी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केन्द्रित निशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन व परामर्श सेवाऐं प्रदान कर रहा है। किसानों को फसल उत्पादन और वानिकी प्रबन्धन पर प्रतिष्ठित/विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए इस केन्द्र द्वारा समय–समय पर जागरूकता सभाऐं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि वानिकी सेवा केन्द्र, सालोन, जिला रायबरेली (उ.प्र.)

A view of IFFDC Agro-forestry Service Center, Salon, Dist. Raibarelly (U.P.)

पी.एफ.एफ.सी.एस. द्वारा इफको उर्वरकों की आपूर्तिः

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्म–निर्भर बनाने के लिये, इफको उर्वरकों का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस वर्ष कुल 41 पी.एफ.एफ.सी.एस (14 उत्तरप्रदेश, 18 मध्यप्रदेश तथा 19 राजस्थान में) द्वारा 2588 मेट्रिक टन इफको उर्वरकों (1664 मेट्रिक टन यूरिया, 489 मेट्रिक टन डी.ए.पी. तथा 330 मेट्रिक टन एन.पी.के.) तथा कोरडेट से खरीदी जैविक–खाद की आपूर्ति की गई।

देश के विभिन्न भागों से आये 200 प्रतिष्ठित वानिस्पतिज्ञ/वैज्ञानिक/अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए जैतपुर कछया पी.एफ.एफ.सी.एस., जिला सागर, (म.प्र.) में एक अनुभव आदान–प्रदान व एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया। उन्हें समिति के

जैतपुर–कछया पी.एफ.एफ.सी.एस., सागर (म.प्र.) में आयोजित एक्सपोजर भ्रमण के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा अनुभव आदान–प्रदान का एक दृश्य

A view of experience sharing during exposure visit by the scientists at Jaitpur-Kachhya PFFCS, Sagar (M.P.).

Mahasamund districts of Chhattisgarh and is also organizing specialized training programmes, seminars and exposure visits at various PFFCS to create awareness amongst the farmers.

To promote agro-forestry on larger scale and create its awareness amongst the farming community, IFFDC has started an agro-forestry service center at tehsil headquarter Salon (District Raibarelly) which is providing inputs like, forestry seeds, IFFCO fertilizers and bio-fertilizers along with free technical guidance and consultation to the farmers with main focus on various important aspects of agro-forestry. Awareness creation meetings and seminars are being organized at the center from time-to-time to impart technical know-how of crop production and forestry management to the farmers by the reputed scientists/experts.

Supply of IFFCO Fertilizers through PFFCS:

The PFFCS in UP, MP and Rajasthan were encouraged to take up the marketing of IFFCO fertilisers for economic self sufficiency. Total 41 PFFCS (14 in UP, 18 in MP and 9 in Rajasthan) supplied 2588 MTs IFFCO fertilizers (1664 MT Urea, 489 MT DAP, 330 MT NPK and 105 MT 20:20:00) and bio-fertilizers purchased from CORDET during the year.

An Experience Sharing cum Exposure visit of 200 distinguished Botanists/Scientists/Researchers from various parts of the country was organized at Jaitpur Kachhya PFFCS, dist Sagar (M.P.).They were briefed about various farm forestry activities being undertaken in the

अन्तर्गत संचालित की जा रही वानिकी की विभिन्न गतिविधियों, समिति में जैव विविधता संरक्षण केन्द्र विकास हेतु बंजर भूमि विकास तथा पर्यावरण सुधार में अन्तर्गत बहु–उद्देश्यीय प्रजाति से सहभागी वनीकरण की भूमिका से अवगत कराया। प्रतिभागियों ने वृक्षारोपण स्थल, औषधीय पौधों की कृषि क्षेत्रों तथा समितियों के अन्तर्गत विकसित द्वारा तैयार किये गये समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों तथा समिति सदस्यों से विस्तारपूर्वक वार्ता की तथा आई.एफ.एफ.डी.सी. के सहयोग एवं मार्गदर्शन से समितियों में संचालित गतिविधियों की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

प्रभाव : पी.एफ.एफ.सी.एस. पयार्वरण सुधार के लिये केन्द्रिक संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं, तथा समुदाय की जलाऊ लकड़ी व चारे की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। ग्रामीण स्तर पर लोगों की वैध संस्था के रूप में ये समितियाँ, समुदाय के लाभ के लिये विभिन्न बाहरी संसाधन जुटाने में सहायता कर रही हैं। पी.एफ.एफ.सी.एस. स्तर पर तथा सदस्य स्तर पर प्रारंभ की गई विभिन्न आय अर्जन गतिविधियाँ तथा लघु उद्योग इन संस्थाओं को स्वावलम्बन (स्व–स्थायित्व) की ओर ले जा रहे हैं तथा समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं।

II. पश्चिमी भारत बारानी खेती परियोजना

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अप्रैल 1999 में राजस्थान के चितौड़गढ जिले की प्रतापगढ तहसील में ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) द्वारा सहायता प्राप्त ''पश्चिमी भारत बारानी खेती परियोजना'' आंरभ की। पहले दो वर्षों के लिए इस परियोजना का कार्यक्षेत्र प्रतापगढ में 25 मुख्य ग्रामों तक सीमित था। जनवरी 2002 से इस परियोजना का मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के 50 अतिरिक्त मुख्य ग्रामों में विस्तार किया गया। यह परियोजना जिसका लक्ष्य 400 ग्रामों (75 मुख्य ग्रामों, 100 विस्तारित ग्रामों और 225 केन्द्रीभूत ग्रामों) में 1,50,000 अनुसूचित जनजाति प्रधानतापूर्ण गरीब आदिवासियों मुख्यतः भील व मीणा की आजीविका को बढ़ावा देना था, 31 मार्च, 2006 को सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।

परियोजना अपनी अवधि 31 मार्च, 2006 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर चुकी है, तथापि परियोजना की समाप्ति के पश्चात चिरन्तरता के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. परियोजना स्टॉफ के मार्गदर्शन में परियोजना गतिविधियों का लगातार अनुसरण किया जा रहा है। घटकवार विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

संस्थागत विकास

परियोजना अवधि के दौरान गठित किये गये 939 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। परियोजना गांवो में से पहचान किये

PFFCS, the role of participatory afforestation of multi-pupose species in wasteland development and environment up-gradation for developing bio-diversity conservation hub in the PFFCS. Participants visited the plantation sites, medicinal plants cultivation fields, and exhibition of SHG products produced developed in the PFFCS. They interacted with members of the SHGs and PFFCS at length and highly appreciated the ongoing activities in the PFFCS being undertaken with the support and guidance of IFFDC.

Impact: PFFCS are serving as nodal agencies for environment upgradation and catering to the fuel wood & fodder needs of the community. As people's organizations at village level with legal status, these are helping in mobilization of various outside resources for benefit of the community. Various income generating activities and micro-enterprises started at PFFCS & individual members level are leading towards self-sustainability of these organisations and improvement of socio-economic status of the community.

II. WESTERN INDIA RAINFED FARMING PROJECT

Hon'ble members are aware that in April 1999, IFFDC took up a project entitled "Western India Rainfed Farming Project (WIRFP)" in Pratapgarh tehsil of Chittorgarh district of Rajasthan supported by the Department for the International Development (DFID) UK Govt. For the first two years the scope of this project was limited to 25 core villages in Pratapgarh. The project was expanded to Ratlam district of M.P. in additional 50 core villages w.e.f. January 2002. The project with the aim to enhance the livelihood of 1,50,000 poor tribal people dominated by Scheduled Tribes (ST) mainly Bhils and Meenas in 400 villages (75 core, 100 dissemination villages and 225 proximal villages) has been successfully completed on 31st March,2006.

However, the follow up of project interventions after withdrawl are continuing for long term sustainability under the guidance of IFFDC project staff. Component wise details are given below:-

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

939 Self Help Groups formed during the project period are functional. 925 Jankars (para-

गये एवं प्रशिक्षित 925 (33% महिलाऐं) जानकार अपने संबंधित क्षेत्रों के लिये योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित 22 प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.) भी परियोजना क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्वयं सहायता समूह एवं पी.एल.डी.सी.एस. के सदस्यों, कार्यालय कर्मचारियों तथा जानकारों के ज्ञान एवं कुशलता उन्नयन हेतु उन्हें आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है।

मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी. जानकार क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, जानकारों को प्रोत्साहित करते हुए ।

Chief Executive, IFFDC encouringing Jankars during capacity building training programme.

प्रभावः

- स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें मुख्य धारा में लाने तथा बचत तथा उद्यमिता विकास की प्रवृत्ति विकसित करने में मदद की जा रही है।
- प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ समुदाय को अपने विचार, मत रखने तथा समुदाय सम्बधी अन्य समस्याओं एवं विकास की पहल करने हेतु एक समान मंच के रूप में कार्य कर रही हैं।

कृषि प्रणाली विकास

परियोजना अवधि में कृषकों के खेतों में उन्नत किस्म के मक्का, उडद, सोयाबीन, सरसों, गेहूँ, चना तथा कपास एवं सब्जियों के उन्नत बीजों व अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज प्रदान कर लगाये गये सहभागी प्रजाति परीक्षण प्रदर्शनों से कृषकों के उन्नत बीज का बहुलीकरण करने में मदद हुई। जिनका उन्होंने अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बुवाई हेतु उपयोग किया।

तैयार कम्पोस्ट तथा वर्मी कम्पोस्ट गड्ढे तथा कृषकों को प्रदत्त स्प्रे पम्प, हंसिया, मक्का शेलर, सोयवीडर, सीडड्रिल,

professional) identified from project villages itself (33% women) and trained are supporting the village community in their respective fields for planning, implementation and monitoring of the group activities.

22 Primary Livelihood Development Cooperative Society (PLDCS) promoted by IFFDC are also functioning in the project area. SHGS & PLDCS members, Office bearers and Jankars are being imparted need based trainings to upgrade their knowledge and skill.

Impact:

- SHGs are helping in addressing the fulfillment of immediate needs by bringing the women in the mainstream and developing a sense of savings & entrepreneurship.
- PLDCSs are acting as a common platform for the community to express their views, ideas and other community-related problems and take development initiatives.

FARMING SYSTEM DEVELOPMENT

Participatory Varietal Trials conducted on various crops at farmer's field during the project period by providing improved high yielding variety seeds of Maize, Urd, Soybean, Mustard, Wheat, Gram, Cotton and Vegetables seeds have helped the farmers in multiplying their own improved seed, which they use for sowing to obtain higher yields.

परियोजना क्षेत्र, प्रतागढ़ (राजस्थान) में अन्तः फसल खेती पर खण्ड प्रदर्शन।

Block demonstration on intercropping in the project area, Pratapgarh (Rajasthan).

Compost & vermi compost pits dug and farm Implements like spray pumps, sickles, Maize Shellers, Soyweeders, Seed Drills, Threshers and Hand/

थ्रेशर, हैन्ड/व्हील खुदाली इत्यादि उनके द्वारा श्रम में कमी लाने हेतु प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

फसल जानकार फसलों की नवीनतम कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

"गिरीराजा गिरीरानी" कुक्कुट पक्षी वाले परिवारों ने उनको बढ़ाया है तथा पशु जानकारों द्वारा भी गांवों में बचाव के साथ–साथ मौके पर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

Wheel Hoe etc. provided to the farmers are being used by them to overcome drudgery.

Crop jankars are guiding the farmers about latest package of practices of crops.

Households with 'Giri Raja Giri Rani' poultry birds have multiplied & Veterinary Para-Professionals (Jankars) are providing preventive as well as on the spot health services in the villages itself.

परियोजना अवधि में जल संसाधन विकास के लिए 230 संकन तालाब, निर्मित 515 फार्म तालाबों, लगाये गये 113 हैण्डपम्पों, गहरे एवं मरम्मत किये गये कुँए, निर्मित 104 एनीकटों (932 हेक्ट. क्षेत्र सिंचित), मरम्मत किए गये 35 एनीकटों तथा साफ किये गये 10 एनीकटों, निर्मित 49 बाँधों, 22 रपटों, गहरीकृत 31 तालाबों से प्रति इकाई औसत पैदावर में वृद्धि के लिए सिंचाई प्रदान करने में मदद मिल रही है।

परियोजना क्षेत्र में निर्मित बाँध का एक दृश्य।

A view of Check Dam constructed in the project area.

For water resource development, 230 sunken ponds, excavated 515 farm ponds, installed, 113 hand pumps, deepened and repaired wells, constructed 104 anicuts (irrigating 932 ha. land), repaired 35 anicuts, desiltated 10 anicuts, constructed 49 earthen dams, 22 Rapats and deepened 31 ponds during the project are helping by providing irrigation to obtain higher yield per unit area.

प्रभाव

- आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों को आवश्यक नई तकनीक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराकर उनकी मदद की गई।
- परियोजना के कई गांवों में फसल पद्धति बहुत ही शीघ्र बदल रही हैं। संग्रहित पानी से किसान अब नगदी फसलों, सब्जी एवं फलदार फसलों की बुवाई कर कर रहे हैं।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा शुरू की गई कृषि वानिकी आधारित खेती के अनुरूप कुछ फलोद्यानों के साथ – साथ खेतों के किनारों एवं बंधों पर जलाऊ लकड़ी तथा पशुओं के चारे की खेती तथा खाली जगह पर कृष्य फसलों को लगाया गया। कुछ परिवार जिन्होनें फलदार बाग लगाये उन्हें 15,000–20,000 रु. प्रति हेक्टेयर तक की आमदनी हो रही है।
- विशेषतः भमिहीन परिवारों की भागीदारी से उनकी और आय में वृद्धि हेतू आय–अर्जन गतिविधियों जैसे फलदार पौधे लगाना, वर्मी कम्पोस्ट, दस्तकारी से आमदनी बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ गांवो में किसानों ने अपनी आय बढ़ाने हेतु क्रास ब्रीड गायों, उन्नत नस्ल की भैंसें तथा बकरियाँ भी पालना प्रारंभ किया है।

Impact -

- IFFDC helped the farmers by providing need based skills and latest technical knowledge.
- In many project villages the cropping pattern is changing very quickly. Farmers have now started sowing cash crops, vegetables and fruit crops by irrigating with harvested water.
- Tree-based farming model launched by IFFDC has established some fruit orchards along-with cultivation of fuel, wood and fodder forestry trees on borders and bunds and arable crops in the inter-space. With the orchards bearing fruits, some families are earning Rs 15,000-20,000 per hectare.
- Income generation activities such as raising of fruit plants, vermi composting, handicrafts started to enhance their income particularly by involving the landless families are being carried out. In some villages farmers have also started rearing crossbred cows, improved breeds of buffaloes and goats to supplement their income.

- घरेलू उपयोग के लिए महिलाओं को भी महत्वपूर्ण लाभ पहुँचा है। अब वे घरेलू उपयोग के लिए पीने के पानी, चारा तथा जलाऊ लकड़ी के स्त्रोतों के प्रति आश्वस्त हुई हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्याओं ने उन्नत कृषि आधारित विषयों के साथ–साथ स्वास्थ्य, साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक शोषण एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों से सम्बंधित समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया तथा समस्याओं के उचित समाधान ढूढें।
- सिंचाई के साधन आने से भूमि के मूल्य में सार्थक वृद्धि हुई है।
- जल संचित टैंकों के बनाए जाने से आसानी से पीने के पानी, पर्याप्त चारा उपलब्ध हुआ, जिससे पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि व महिला श्रम में कमी आई है।
- सुदुर व अगम्य क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं है, पशुधन जानकर अपनी सेवाओं से आजीविका अर्जन कर रहे हैं।
- पशुओं में बीमारी की रोकथाम एवं उनके खुली चराई करने पर नियंत्रण करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। दुग्ध उत्पादन (डेयरी) के व्यवसाय ने महिलाओं को पर्याप्त आय अर्जन करने के अच्छे अवसर प्रदान किये।
- घर के अहाते में ''गिरिराजा–गिरिरानी'' नस्ल के कुक्कुट पालन से भूमिहीन ग्रामवासियों को स्थायी आय प्राप्त हो रही है।
- सभी गाँवों में किसानों द्वारा एकजुट होकर अधिकतर गाँवों में वर्षभर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम वर्षा जल संग्रहण हेतु कार्य कर रहे हैं।
- जलग्रहण संरचनाओं के बनने के पश्चात् 328 परिवारों में पलायन में कमी आई है।

परियोजना अवधि के दौरान, विद्यमान कर्मचारियों का सहभागी ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण घटकों पर क्षमता विकास किया गया था। सामुदायिक सम्पत्ति का निरन्तर रखरखाव और प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, जल उपयोग समितियों, जानकारों जैसी विभिन्न समुदाय आधारित संस्थाओं की निरन्तरता हेतु कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। परियोजना समाप्ति के पश्चात परियोजना कार्यालय प्रतापगढ़ (राज.) और रतलाम (म.प्र.) के लुघुकरण के उपरान्त सामुदायिक विकास हेतु वर्ष के दौरान सम्पन्न की गई गतिविधियों का विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है।

- Significant benefits have also reached to the women. Now they have assured source of water for drinking, fodder and fuel for domestic consumption. Members of the women's Self Help Groups in addition to issues related to improved farming also discuss their problems related to health, functional literacy, education of children, social exploitation and other social evilsand identified suitable solutions for their problems.
- Introduction of irrigation facilities has increased the land prices considerably.
- Construction of water storage structure lead to easier access to drinking water, increased fodder availability thereby increased productivity of animals and reduction in women's drudgery.
- Livestock Jankars are earning their livelihood by charging for services, in the remote and inaccessible areas where no veterinary services are available.
- Preventive health care and controlled grazing are being followed. Dairy husbandry has provided good opportunity for women to earn substantial income.
- Backyard poultry with 'Giriraja-Girirani' is providing substantial income to landless villagers.
- Farmers are working unitedly for harvesting maximum rain water for ensuring, water availability throughout the year.
- After construction of WRD structures, migration by 328 households has been reduced.

During the project period, capacity of the existing staff has been built on important components of participatory rural development. Field staff is facilitating for sustenance and maintenance of community assets and community based organisations like Primary Livelihood Development Cooperative Societies, Self Help Groups, Water User Associations and Jankars etc. Details of various activities carried out during the year for community development after completion of the project by downsizing the offices at Pratapgarh (Rajasthan) and Ratlam (MP) are given in the following Table.

तालिका : परियोजना कार्यालय और गतिविधिवार प्रगति (अप्रैल 07 से मार्च 08)

Table : Project office and activity wise progress (April 07 to March 08)

क्र.सं. S.No.	कार्यक्रम Programme	उपलब्धियाँ / Achievements		
		रतलाम Ratlam	प्रतापगढ़ Pratapgarh	योग Total
1.0	**गाम स्तरीय कार्यक्रम Villlage Level Programme**			
1.1	समिति बैठकें PLDCS Meeting (No.)	70	28	**98**
1.2	वार्षिक कार्य योजना (स्वयं सहायता समूहों की सं.) Annual work plan ((No.of SHG)	354	70	**424**
1.3	प्रा.आ.वि.स. समिति योजना (सं.) PLDCS Plan (No.)	14	7	**21**
1.4	दिवस/सप्ताह समारोह (सं.) Celebration of Days/ Weeks (No.)	52	18	**70**
1.5	सहकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/एस.ए.यू. तथा आई.सी.ए.आर. केन्द्रों से सम्पर्क (सं.) Liasion & Linkages with GOs/ NGOs/SAUs & ICAR centres (No.)	52	6	**58**
1.8	स्वास्थ्य शिविर/स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम (सं.) Health Camps/ Health Awareness Prog. (No.)	11	2	**13**
2.0	**फसल कार्यक्रम Crop Programme**			
2.1	फसल गोष्ठी (संख्या) Crop Seminar (No.)	2	2	**4**
3.0	**पशुधन कार्यक्रम Livestock Programme:**			
3.1	पशु चिकित्सा शिविर (ग्रामों की सं.) Vet. Camps (No. of Villages)	15	2	**17**
4.0	**समुदाय प्रशिक्षण (जानकार सहित) Community Training (including Jankar)**			
4.1	स्वयं सहायता समूह/आयवर्धन गतिविधियां (सं.) Self Help Group/ IGA (No.)	16	6	**22**
4.2	एस.डब्ल्यू.सी./डब्ल्यू.आर.डी./एफ.एस.डी. (सं.) SWC/WRD/FSD (No.)	11	0	**11**

सम्पर्क कार्यालय जयपुर (राज.) और भोपाल (म.प्र.)

भोपाल (म.प्र.) तथा जयपुर (राजस्थान) में स्थापित सम्पर्क कार्यालय सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं से संसाधन लाने, प्रभावित करने, जुड़ाव एवं नीति वकालत के कार्यों हेतु संचालित हैं। ये कार्यालय राज्य सरकारों, संस्थाओं से योजनाओं/नीतियों की सूचनाओं हेतु परियोजना की

Liaison offices Jaipur (Raj.) and Bhopal (M.P.)

Liaison offices established at Jaipur (Raj.) and Bhopal (M.P.) are operating to function for resources mobilization, influencing, networking and policy advocacy with GOs, NGOs. These offices are making regular contacts/linkages with State Govt., institutions for information of policies/schemes; effective policy

अंगीकृत/परीक्षित तकनीकों एवं दृष्टिकोणों का असरदार नीति से प्रभावीकरण/ समर्थन; सरकार की अपनायी गयी योजनाओं को समय रहते बताने और दाता संस्थाओं से नयी परियोजनाओं एवं योजनाओं के जुटाव हेतु कार्यरत है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी सहभागी दृष्टिकोणों, जांची परखी गई विधियों, विकसित की गई तकनीकियों तथा क्रियान्वित की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि प्रक्षेत्र वानिकी परियोजनाओं, पश्चिमी भारत बारानी खेती परियोजना की सीखों पर आधारित विभिन्न आजीविका विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया है।

पुरस्कार/सम्मानः

- डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) द्वारा डॉ. पी. एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी., नई दिल्ली को दिनांक 21 जनवरी, 2008 को आयोजित, राष्ट्रीय संगोष्ठी "करंट चैलेंज इन बायोलोजीकल साइंस विजन 2008" के समापन समारोह के अवसर पर बुंदेलखण्ड क्षेत्र में बंजर भूमि विकास और जैव-विविधता संरक्षण पर किए गये विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉ. डी.पी. सिंह, कुलपति, डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.) द्वारा की गई। डॉ. मरवाहा ने विदाई समारोह में देश के विभिन्न भागों से आये 175 वैज्ञानिकों/ भागीदारों को सम्बोधित किया।

डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी., सागर (म.प्र.) में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "करंट चैलेंज इन बायोलोजीकल साइंसेज़ विजन 2008" के समापन अवसर पर वानस्पतिक वैज्ञानिकों को सम्बोधित करते हुए।

Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC addressing the Botonists during valedictory session of National Seminar on "Vision 2008: Current Challenges in Biological Sciences" held at Sagar (M.P.).

- डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य अधिशाषी, श्री एच.सी. गेना, परियोजना अधिशाषी, आई.एफ.एफ.डी.सी. एवं नई दिल्ली एवं डॉ. जी.पी. तिवारी, वरिष्ठ परियोजना समन्वयक, आई. एफ.एफ.डी.सी., रतलाम को **"फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया"**, नई दिल्ली द्वारा जून 9, 2007 को प्रतिष्ठित **"आर्क ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड"** तथा **"इडियन गोल्डन एचीवर्स अवार्ड"** वर्ष 2007 के साथ **स्वर्ण पदकों एवं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस एवं फेसिलिटेशन प्रमाण पत्रों** से इनके द्वारा आजीविका संवर्द्धन के माध्यम से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भारतीय छवि को उभारने हेतु प्रदत्त उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरुस्कृत किया गया।

influencing/ advocacy about adopted/ tested project approaches and technologies; timely feed back to the Govt. regarding adopted schemes and access for new projects/schemes to the donor agencies etc.

IFFDC has started to implement various livelihood development project based on its participatory approaches, tested methodologies, evolved technologies and different learnings during the project implemented viz: Farm Forestry project and Western India Rainfed Farming Project.

AWARDS/ HONOURS

- Dr P. S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC, New Delhi was honoured by Dr Hari Singh Gour University, Sagar (M.P.) at the occasion of valedictory ceremony of National Seminar on "Vision 2008: Current Challenges in Biological Sciences" held during January 20-21, 2008 at Sagar (M.P.) for his outstanding contribution to Wasteland Development, Environment upgradation and Bio-diversity Conservation in Bundelkhand region. The function was chaired by Dr D. P. Singh, Vice Chancellor, Dr H. S. Gour University, Sagar (M.P.) wherein Dr. Marwaha delivered the Valedictory Address to 175 scientists/ participants from all over the country.

- Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive and Sh H. C. Gena, Project Executive, IFFDC, New Delhi, Dr.G.P. Tewari, Sr Project Coordinator, IFFDC, Ratlam were honored with the prestigious **"Arch of Excellence Award" and "Indian Golden achievers Award"** for the **year 2007** alongwith **Gold Medals and Certificates of Excellence and Falicitation** by **"Friendship Forum of India"**, New Delhi on June 9, 2007 for their outstanding contribution in enhancing the Indian image in the field of Rural Development through Livelihood promotion.

डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, श्री एच.सी. गेना, परियोजना अधिशाषी, आई.एफ.एफ.डी.सी., नई दिल्ली एवं डॉ. जी.पी. तिवारी, वरि. परियोजना समन्वयक, रतलाम को "अन्तर्राष्ट्रीय पेग्विंन पब्लिशिंग हाउस" के संरक्षण में "फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया", नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित **"आर्क ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड"** तथा **"इंडियन गोल्डन एचीवर्स अवार्ड"** वर्ष 2007 के साथ स्वर्ण पदकों एवं उत्कृष्टता व फेसिलिटेशन प्रमाण पत्रों से **सम्मानित किया गया।**

Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive, Sh H. C. Gena, Project Executive, IFFDC, New Delhi and Dr. G.P. Tewari Sr. Project Coordinator, Ratlam honored with the prestigious "Arch of Excellence Award" and "Indian Golden achievers Award" for the year 2007 alongwith Gold Medals and Certificates of Excellence and Facilitation by "Friendship Forum of India" under the aegis of "International Penguin Publishing House", New Delhi

- डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य अधिशाषी, आई.एफ.एफ.डी.सी., नई दिल्ली, को **"फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया"**, नई दिल्ली द्वारा जून 9, 2007 को प्रतिष्ठित **"लाईफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड"** वर्ष 2007 से इनके द्वारा भारत के निम्नतम, साधन रहित, वंचित तथा निर्धन आदिवासी समुदाय की गरीबी निवारण के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रदत्त उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरुस्कृत किया गया।

III. स्टेट इनोवेशनस इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेज (सिफ्पसा) परियोजना

माननीय सदस्यों को ज्ञात है आपकी समिति जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) के शाहगढ़ और भिटुआ खण्डों के 61 गाँवों के 21,744 परिवारों सहित कुल 1.25 लाख जनसंख्या हेतु एक परियोजना ''इनोवेटिव एक्शन ओन आर.सी.एच. सेवाएँ'' क्रियान्वित कर रही थी जो कि यू.एस.ए.आई.डी. द्वारा सिफ्पसा, लखनऊ के तहत वित्त पोषित थी। यह परियोजना जो दिसम्बर, 2002 को प्रारम्भ की गयी थी, वह मार्च, 2005 को सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।

परियोजना में परिवार नियोजन कार्यों को अपनाने हेतु कुल 1,53,734 (65,589 शाहगढ तथा भिटुआ ब्लाक) जनसंख्या को शामिल किया गया था।

इसी तरह से सिफ्पसा ने जिला इलाहाबाद के फूलपुर और बहेरिया खंडों, हेतु ''चिकित्साल्य आधारित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाए'' शिर्षित एक अन्य परियोजना प्रदान की है जो एक वर्ष (1 अक्टूबर 2006 से 30 सितम्बर 2007) की अवधि के लिए चलाई जा रही

- Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC, New Delhi was honored with the prestigious **"Life Time Achievement Award"** for the **year 2007** by **"Friendship Forum of India"**, New Delhi on June 9, 2007 for his outstanding contribution towards Socio-Economic Development through Natural Resources Management for Poverty Alleviation of the down-trodden, most disadvantaged, resource-less, poor tribal community of India.

III. STATE INNOVATIONS FOR FAMILY PLANNING SERVICES AGENCY (SIFPSA) PROJECT

Hon'ble members are aware that your Society had undertaken a project entitled "Innovative Action on RCH services for 61 villages covering the 21744 households involving a population of about 1.25 lakhs in Shahgarh and Bhituwa Blocks of Sultanpur district in Uttar Pradesh" funded by USAID through State Innovations for Family Planning Services Project Agency (SIFPSA), Lucknow. The project which was started during December 2002 was successfully completed in March 2005.

The project covered the total population of 153734 (65,589 Shahgarh and 88145 Bhitua blocks) for adopting family planning measures.

On the similar lines, SIFPSA awarded another project entitled "Clinic Based Reproductive Health Service for Phulpur & Bahariya Block in Allahabad district with one year duration (1st October 2006 to

है। इन विकास खण्डों में 4.19 लाख जनसंख्या के साथ 0.72 लाख योग्य दम्पत्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। परियोजना की अवधि अब सितम्बर 2008 तक बढ़ा दी गयी है।

परियोजना का लक्ष्य जीवन स्तर में सुधार हेतु गुणवान परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है तथा परियोजना के उद्देश्य :– क्षेत्र में गर्भ निरोधकों के प्रयोग में वृद्धि, संस्थागत प्रसव का संवर्द्धन तथा पूर्व प्रसव देखभाल और प्रतिरक्षण को बढ़ावा देना है।

परियोजना के मुख्य घटकों के अन्तर्गत चिकित्सालय विधियों तक पहुँच बढ़ाना और समुदाय को प्रदान की जाने वाले प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिक्रिया, उपलब्ध मूलभूत संरचनाओं जैसे कि संचार माध्यमों, प्रसार कार्यक्रमों, ग्राम स्तरीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निर्माण में महिलाओं का नेतृत्व विकास और उनको एम.सी.एच. सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करना है।

परियोजना की विशिष्ठ उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :–

171 परियोजना गांवों (फूलपुर खण्ड के 80 और बहेरिया खण्ड के 91 गांवों में) की सर्वेक्षण आधारित गतिविधियों की योजना बनाई गयी।

परियोजना क्षेत्र में 167 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये जिससे 10,636 लोग लाभान्वित हुये। इन शिविरों में परामर्श सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ, 9019 पूर्व प्रसव परीक्षण (एएनसी), 9799–टेटनस टीकाकरण, संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन, 24823–बाल प्रतिरक्षण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य पर सूचना शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) सामग्री का प्रदर्शन और वितरण, 1556–कॉपर टी का प्रबन्धन,

आई.एफ.एफ.डी.सी–सिफ्पसा परियोजना अन्तर्गत गांव कप्सा, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) में आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का दृश्य।

View of Community Health Awareness Programme organised at village Kapsa, Dist Allahabad (U.P.) under IFFDC-SIFPSA Project.

डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी., नई दिल्ली, डॉ. मीनाक्षी त्रिपाठी, संभागीय परियोजना प्रबन्धक, सिफ्पसा परियोजना, इलाहाबाद (उ.प्र.) को आई.एफ.एफ.डी.सी. परियोजनाओं की जानकारी देते हुए।

Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive IFFDC, New Delhi briefing about IFFDC Projects to Dr. Minakshi Tripathi, Divisional Project Manager, SIFPSA Project, Allahabad (U.P.).

30th September 2007 to cover a population of 4.19 lakhs with 0.72 lakh eligible couples in these blocks. The project has now been extended upto September 2008.

The project goal is to provide quality family planning and reproductive health services in order to improve quality of life. The project objectives are to increase contraceptive use in the area; promote institutional deliveries; increase complete Ante Natal Care (ANC) coverage and increase immunization.

Major components of the project are to increase access to clinical methods and respond to the quality RCH services to the community; utilisation of the available infrastructure i.e. communication channels, extension programmes, women's leadership to build a sustainable village-based family welfare programme and provide them assistance for available MCH service.

Salient achievements of the project are:

Activities were planned based on the base Line surveys conducted of 171 project villages (80 in Phulpur block and 91 in Baharia block).

167 Health camps were organised in the project area benefiting 10,636 persons, in which various activities related to counseling services, 9019 Anti Natal Checkups (ANC), 9799-TT vaccination, promotion of institutional delivery, 24823-immunization of children, display and distribution of Information, Education and Communication (IEC) material on RCH, 1556-administration of Copper-T, 1719-referral

1719–महिलाओं को नसबन्दी हेतू रेफरल सहायता, 4249–प्रसव पश्चात् निरीक्षण, (पी.एन.सी.), 2718–मरीजों को गोलियों का वितरण और 1719 बन्धयाकरण करवाया गया।

रेफरल सेवायें– 1725 महिला नसबन्दी के केसों को प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों (पी.एच.सी.) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) को रेफर किया गया।

परियोजना गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतू जिला इलाहाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.), चिकित्सक पीएचसी और सीएचसी, के साथ 22 बैठकें की गयी।

आशा कर्मियों द्वारा उनके क्षेत्र में 3822 ग्रामीण स्तरीय समूह बैठकें आयोजित की गयी जिसमें 75,293 समुदाय सदस्यों ने भागीदारी की।

IV. उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (यू.पी.एच.एस.डी.पी.)

आई.एफ.एफ.डी.सी. समुदाय के लाभवंचित विशेषतया महिलाओं एवं विषम व सुदूर क्षेत्रों के गरीबों को रोग रोधक एवं रोगनाशक स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदत्त करने हेतु द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन विकास खण्ड, ऊँचाहार, जिला रायबरेली (उ.प्र.) में भारत सरकार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आई.डी.ए.) विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है।

से आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जून 2006 पंजीकृत चिकित्सक (एक सप्ताह में 3 दिन), पंजीकृत महिला चिकित्सक (एक सप्ताह में 1 दिन), पंजीकृत नर्स (एक सप्ताह में 6 दिन) एवं प्रशिक्षित दाई (एक सप्ताह में 6 दिन) के माध्यम से मातृत्व व प्रसव मृत्यु दर कम करने हेतु विभिन्न आवश्यकता आधारित समुदाय स्वास्थ्य सेवाऐं जैसे :– प्रसव, प्रसव पश्चात् देखभाल, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सरकारी वृत से जुड़ाव व रेफरल सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं।

परियोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गये जिनमें 4,837 पुरुष, 2,286 महिला तथा 906 बच्चे लाभान्वित हुए; 206 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगाये गये; 213 संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन; प्रसव पश्चात् जांच (पी.एन.टी.) 180; 1256–बच्चों का प्रतिरक्षण एवं नसबन्दी हेतु 43–रेफरल सहायता प्रदान की गयी। अल्परक्त वाली 59 गर्भवती महिलाओं को आयरन व फोलिक गोलियाँ उपलब्ध कराई गयीं। इसके अतिरिक्त 1018 व्यक्तियों को परिवार कल्याण सेवाऐं भी उपलब्ध कराई गयीं।

V. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.)

माननीय प्रतिनिधिगण को ज्ञात है कि आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना झालावाड़ (राजस्थान) जिले के झालरापाटन विकासखण्ड के 75 गाँवों में जनवरी, 2004

support for sterilization, follow-up of 4249-Post Natal Checkup (PNC), 2718-Oral Client Pills (OCP) and 1719 sterilization was got conducted.

Referral services: 1725 cases of Tubectomy were referred to Primary Health Centres (PHC) and Community Health Centres (CHC).

For effective implementation of the project activities, 22 meetings were held with Chief Medical Officer (CMO), doctors of PHC and CHC, district Allahabad.

Village level 3822 group meetings have been organised by ASHA workers in their area which was participated by 75,293 community members.

IV. UTTAR PRADESH HEALTH SYSTEMS DEVELOPMENT PROJECT (UPHSDP)

To provide preventive and curative health care services to the disadvantaged section of the community specially the women and the poor in difficult and remote areas of poor access, IFFDC is implementing this project in block Unchahar; district Raibareilly (U.P.) with the support of International Development Association (IDA) World Bank through Government of India.

Various need based community health services which includes Natal, Post Natal Care, immunization, health education and linkage with Govt. sector and referral services to reduce the maternal and infant death rates are being provided by IFFDC through registered male doctor (3 days in a week), female doctor (1 day in a week), registered nurse (6 days in a week) and trained dai (6 days in a week) since June 2006.

Health check-up camps benefiting 4,837-Male, 2,286-Female and 906-Children; 235-TT vaccinations of pregnant womens; promotion of 213 institutional deliveries; 180 Post Natal Checkups (PNC); 1256-immunization of children and 43-referral supports for sterilization were conducted in the project area. Iron and folic tablets were provided to 59 anemic pregnant women. In addition, 1018 persons were also provided family welfare services.

V. DISTRICT POVERTY INITIATIVE PROJECT (DPIP)

Hon'ble delegates are aware that IFFDC had been implementing the District Poverty Initiative Project (DPIP) in 75 villages of Jhalarapatan block

से (डी.पी.आई.पी.) तथा बारां (राजस्थान) जिले के अटरू विकासखण्ड के 60 गाँवों में सितम्बर 2004 से प्रारम्भ की गई थी। इन परियोजनाओं का राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, राजस्थान के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है, जिसे मार्च 2008 में निम्नलिखित उपलब्धियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है।

इस परियोजना के अंतर्गत 526 समान रूचि समूह (300 झालावाड में तथा 226 बारां में) गठित किये गये जिनकी सदस्यता 5,382 (3,002 झालावाड में तथा 2,380 बारां में) तथा बचत 40.49 लाख रूपये (25.32 लाख झालावाड में तथा 15.17 लाख बारां में) है। इन समूहों ने 12.11 लाख (10.33 झालावाड़ और 1.78 लाख बारां में) सदस्यों को ऋण के रूप में वितरित किए गये हैं।

378 समान रूचि समूहों (242 झालावाड में तथा 136 बारां में) को बैंकों से जोड़ा गया है जिन्होंने बैंकों से 46.26 लाख रुपये (37.84 लाख झालावाड और 8.42 लाख बारां में) का ऋण लिया।

इन समान रूचि समूहों के माध्यम से जल संग्रहण, फसल प्रबंधन, पशुधन, वानिकी तथा अन्य सामाजिक पहलूओं के क्षेत्र में विभिन्न आजीविका विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किये गये हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बैंको से जोड़ने के लिए विशिष्ट योगदान देने हेतु नाबार्ड, जयपुर द्वारा राज्य स्तर पर द्वितीय पुरुस्कार से सम्मानित किया गया।

VI. ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात है कि आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा एस.जी.एस.वाई. – "ग्रामीण मुख्यधारा उत्पाद" के अन्तर्गत ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूड़ा) से अगस्त, 2004 से तथा डुंगरपुर एवं सागवाड़ा विकासखण्डों, जिला–डुंगरपुर (राजस्थान) में तथा जनवरी, 2005 से मावली व खेरवाड़ा विकासखण्डों, जिला–उदयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा वित्तपोषित एक विशेष परियोजना शुरू की। यह परियोजना सम्भवतया दिसम्बर 2008 तक पूरी हो जायेगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शिल्पकारों को सहयोग करना तथा उन्हें परम्परागत ग्रामीण शिल्प को आधुनिक रूपरेखा एवं तकनीकियों के साथ विकसित करने के अवसर प्रदान करना है, जिससे कि ये उत्पाद नये व उभरते हुए बाजारों की मुख्य धारा में जुड़े तथा उन्हें स्थायी आजीविका एवं सुनिश्चित आय प्रदान करें। 63 स्वयं सहायता समूह (31 डूंगरपुर में एवं 32 उदयुपर में) 813 (410 डूंगरपुर में एवं 403 उदयुपर में) सदस्यता के साथ गठित किये गये जिसमें 57 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता है। अब तक इन समूहों ने 5.67 लाख रूपये

of district Jhalawar (Rajasthan) since January 2004 and 60 villages of Attru block of Baran district, Rajasthan since September 2004. These projects funded by the World Bank through State Project Management Unit, Rajasthan have been successfully completed in March 2008 with following important achievements:

526 CIGs (300 in Jhalawar and 226 in Baran) have been formed with the total membership of 5382 (3002 in Jhalawar and 2380 in Baran) with savings of Rs. 40.49 lakhs (25.32 lakhs in Jhalawar and 15.17 lakhs in Baran). These groups have distributed Rs. 12.11 (Rs. 10.33 lakhs in Jhalawar and Rs. 1.78 lakhs in Baran) as loan to its members.

378 CIGs (242 in Jhalawar and 136 in Baran) have also been linked with the banks which have taken Rs. 46.26 (Rs. 37.84 lakhs in Jhalawar and Rs. 8.42 lakhs in Baran) as loan from the banks.

Various livelihood developmental initiatives in the field of water harvesting, crop management, livestock, forestry and other social aspects have also been undertaken through these CIGs.

IFFDC was awarded 2nd prize at state level by NABARD, Jaipur for its outstanding contribution in the field of SHG linkages with the banks.

VI. RURAL NON-FARM DEVELOPMENT AGENCY (RUDA) PROJECT

Hon'ble members are also aware that IFFDC has undertaken a special project under SGSY-Mainstreaming Rural Product' by Rural Non-farm Development Agency (RUDA) which is being funded by the Rajasthan Govt. in Dungarpur & Sagwara blocks of Dungarpur district (Rajasthan) since August 2004 and in Mavli & Kherwada blocks of Udaipur district since January 05. The Project is likely to be completed by December 2008.

The main objective of the project is to assist rural artisans and provide them opportunities to develop traditional rural crafts with modern design and technology inputs so as to mainstream these products in new and emerging markets and providing them sustainable livelihood and assured income. 63 SHGs (31 SHGs in Dungarpur and 32 SHGs in Udaipur) have been promoted with the total membership of 813 (410 in Dungarpur and 403 Udaipur) with 57% women membership. These groups have saved an amount of Rs. 5.67 lakhs (Rs.

(2.87 लाख रू. डूंगरपुर में एवं 2.80 लाख रू. उदयुपर में) की बचत की है एवं इनके सदस्यों को 10.78 लाख रु. (डूंगरपुर में 6.68 लाख रु. व उदयपुर में रु. 2.10 लाख) का ऋण वितरित किया।

17 समूहों (11 डूंगरपुर में और 6 उदयपुर में) को बैंकों से जोड़ा जा चुका है। जिन्होंने 3.64 लाख रु. (2.65 लाख डूंगरपुर में और 0.99 लाख उदयपुर में) का बैंकों से ऋण लिया।

आई.एफ.एफ.डी.सी. को खेरवाडा ब्लाक (जिला उदयपुर) में परियोजना के अन्तर्गत किये गये विशिष्ठ कार्यों हेतु जिला स्तर पर सम्मानित किया गया।

श्री खराडी लाल मीणा, खेरवाडा ब्लाक, जिला उदयपुर (राज.) में श्री जयकरण सिंह, संकुल समन्वयक, आई.एफ.एफ.डी.सी. को सम्मानित करते हुए।

Sh. Kharadi Lal Meena honouring Sh. Jaikaran Singh, Cluster Coordinator, IFFDC at Kherwada Block, Dist. Udaipur (Raj.).

2.87 lakhs in Dungarpur and Rs. 2.80 lakhs in Udaipur) and circulated Rs. 10.78 lakhs (Rs. 8.68 lakhs in Dungarpur and Rs. 2.10 lakhs in Udaipur) as long to its members.

17 CIGs (11 SHGs in Dungarpur and 6 SHGs in Udaipur) have also been linked with the banks which have taken Rs. 3.64 lakhs (Rs.2.65 lakhs in Dungarpur and Rs. 0.99 lakhs in Udaipur) as loan from banks.

IFFDC was hono-ured at district level for its outstanding work in Kherwada Block of Udaipur.

VII. राष्ट्रीय कृषि नवोन्वेशी परियोजना (एन.ए.आई.पी.)

आई.एफ.एफ.डी.सी. को महाराणा प्रताप कृषि व प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर (राज.) के साथ ''कृषि पद्धति एवं तकनीकी मॉडल के माध्यम से आदिवासी प्रभावित क्षेत्रों की आजीविका व पोषण सुरक्षा'' परियोजना का मावली विकास खण्ड, जिला उदयपुर में क्रियान्वयन करने हेतू कन्सोर्शियम पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन दो मॉडलों जैसेः– उद्यान आधारित समन्वित कृषि पद्धति तथा पशुधन आधारित समन्वित कृषि पद्धति के मॉडल में सिद्ध हुई, आवश्यकता आधारित तकनीकियों के उचित मिश्रण पर आधारित लघु व सीमांत किसानों के लिए दोहराने योग्य उचित मॉडल विकसित करने में उपयोगी साबित होगी। स्थान विशेष में प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता के आधार पर संकुल पहुँच का चयन किया गया है। उपयुक्त, सशक्त एवं प्रभावी तकनीकियों का सामूहिक लक्ष्य

VII. NATIONAL AGRICULTURAL INNOVATIVE PROJECT (NAIP)

IFFDC has been selected as partner in the consortium with Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur (Raj.) for implementation of "Livelihood and Nutritional Security of Tribal Dominated Areas through Integrated Farming System and Technology Model" in Mavali Block of Udaipur dist. It is being implemented based on two models ie Horticulture based IFS and Livestock based IFS model with judicious mix of proven, need assessed technologies appropriate for small and marginal farmers encompassing end to end approach for development of appropriate replicable model. The cluster approach in specific sites differing in natural resource base in project has been chosen. Appropriate, sound and effective basket of technologies are aimed at propelling agricultural

डॉ. एस.एल. मेहता, कुलपति एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर में **राष्ट्रीय कृषि नवोन्वेशी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) का** परियोजना गांव सांगवा में शुभारम्भ करते हुए।

Dr. S.L. Mehta, Vice-Chancellor MPUAT, Udaipur inaugurating National Agricultural Innovation Project (NAIP) at Project village Sangwa (Raj.).

कृषि के रूपांतरण को आगे बढ़ाना, कृषि रोजगार एवं पैदावार तथा लाभों में वृद्धि करना है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन, मूल्य वृद्धि तथा किसानों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए संघीकृत करना इस अनुसंधान की एक और रणनीति है।

परियोजना क्षेत्र में पहले से सिद्ध की हुई तकनीकियों, समन्वित और परिपूर्ण तरीकों से परीक्षित और बहुल तकनीकी विकल्पों को अपनाकर लक्षित परिवारों की आय को बढ़ाने और उनके जीवन में सुधार लाने हेतु रणनीति विकसित की गयी है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा यह परियोजना आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली की वित्तिय सहायता से सितम्बर 2007 से 4 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए सांगवा, गादोली, बिजनवास और रख्यावाल प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समितियों के 10 गांवो 1387 परिवारों (उद्यान एवं पशुधन अवधानों पर आधारित) के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं। कार्य आरंभ किया जा चुका है तथा आजीविका समीक्षा मिशन, राजस्थान से इसके क्रियान्वयन के बारे में विचार–विमर्श कर लिया गया है।

परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रम का आयोजन गांव सांगवा में किया गया जिसमें कुलाधिपति, एम.पी.यू.ए.टी. उदयपुर ने परियोजना गतिविधियों का उद्घाटन किया। 152 किसानों को विशेष गुणवत्ता वाले गेंहूँ के बीज प्रदान किये गये, तथा 18 किसान जल उपयोग क्षमता वृद्धि हेतु प्रदत्त सिंचन पाईप से लाभान्वित हुए। 50 किसानों को सब्जी उत्पादन हेतु प्रेरित किया गया। 5 पशु कृमिनाशन शिविरों का आयोजन किया गया। आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए 25 कुक्कुट इकाइयों की स्थापना भी की गयी।

VIII. नाबार्ड वाडी परियोजना प्रतापगढ़

आई.एफ.एफ.डी.सी. को नाबार्ड ने इसके आदिवासी विकास निधि (टी.डी.एफ.) के अन्तर्गत वाडी (लघु–उद्यान) परियोजना प्रतापगढ़ जिला (राजस्थान) के आदिवासी प्रभावित गांवों के 1000 आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) परिवारों के लिए क्रियान्वयन हेतू 7 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत कर दी है।

वाडी पहुँच का मुख्य लक्ष्य संसाधन विहीन गरीब आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतू समन्वित व व्यापक रूप से पर्यावरण को पुर्नःजीवित करना है। अतः आदिवासी समुदाय की आवश्यकताओं का प्रबन्धन इस प्रकार से करना कि वातावरण पुर्नःजन्म के साथ साथ उनकी पहुँच में उपलब्ध संसाधनों से उनकी मांग की पूर्ति की जा सके। अन्ततः इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि से भोजन, चारा, ईधन, इमारती लकड़ी व औषधियों की आपूर्ति बढ़ेगी। जिससे गरीबी ग्रसित पलायन में कमी होने से जीवन में सुधार होगा।

transformation leading to increased on farm employment, increased productivity and profitability. Better management of natural resources, processing and value addition and federating farmers for marketing of their produce is another strategy for research.

The strategy developed to adopt are based on the past proven technologies, testing them in integrated and holistic manner and having multiple technology options for increased income leading to better quality of life to the targeted families of the project area.

IFFDC is implementing the project for four years and six months since September 2007 with financial assistance by ICAR, New Delhi covering 1387 households (horticulture based and livestock based interventions) in 10 villages of Sangwa, Gadoli, Bijanwas and Rakhyawal PFFCS. The work has been started and discussions about implementation have been held with Livelihood Review Mission, Rajasthan.

Launching programme was organized at Sangwa village in which Vice Chancellor; MPUAT Udaipur inaugurated the implementation of project activities. 152 farmers were provided with quality wheat seeds and 18 farmers benefited with irrigation pipe to increase water use efficiency. 50 farmers were motivated to undertake vegetable production. 5 Animal deworming camps were organized. To ensure sustainable livelihoods 25 poultry units were also established.

VIII. NABARD-WADI PROJECT, PRATAPGARH

NABARD has sanctioned "**wadi**" (small orchard) project under its Tribal Development Fund (TDF) to IFFDC for implementation in tribal dominant villages of Pratapgarh district (Rajasthan) covering 1000 Scheduled Tribes (ST) families for 7 years duration.

Wadi approach aims at the rejuvenation of the environment in an integrated and comprehensive manner leading to improved quality of life of resource poor tribal families. Thus, it involves the management of needs of the tribal community in such a way that their demands match the resources available within their reach, besides regeneration of the environment. It ultimately will lead to increased agricultural production, augmenting food supply, fodder, fuel, timber and medicines. Thus, standard of living improves leading to reduction in poverty-induced migration.

वाड़ी पहुँच के माध्यम से व्यापक आदिवासी विकास के घटक जैसे (अ) उद्यान विकास (फलदार/वृक्षारोपण/ औषधीय फसलें व वानिकी पौधे) मुख्य घटक के रूप में (ब) वाड़ी में मृदा संरक्षण (स) जल स्त्रोत प्रबन्धन (संरक्षण एवं उपयोग) (द) चिरन्तर कृषि (य) मानव संसाधन विकास (समुदाय विकास) (र) महिला विकास-कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल देना है जिसमें महिला श्रम में कमी के उपाय, कृषि व गैर कृषि आय अर्जन गतिविधियाँ तथा बचत व ऋण की आदत डालने हेतू स्वयं सहायता समूह (ल) सामुदायिक स्वास्थ्य (व) भूमिहीन लोगों के लिए उद्यु-उद्योग विकास (श) प्रसंस्करण व विपणन तथा (स) उक्त गतिविधियों से मिलते-जुलते अन्य पूरक घटक सम्मिलित हैं। आदिवासी परिवारों का सर्वेक्षण तथा सहभागी परिवारों से सहमति-पत्र प्राप्त करने जैसी गतिविधियाँ प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

The comprehensive tribal development through "wadi" approach involves the components / sectors like (a) Orchard development (fruit/ plantation/herbal crops & forest plants) as the core component (b) Soil conservation in the wadi (c) Water resources management (conservation and use) (d) Sustainable agriculture (e) Human resource development (community development) (f) Women development - special emphasis is laid on involvement of women in all spheres of the programme which includes drudgery reduction measures, on-farm and nonfarm income generating activities and self help groups for inculcating thrift and credit habits (g) Community Health (h) Micro-enterprises development for landless people (i) Processing & marketing and (j) Other auxiliary components to dovetail with above activities. The activities like survey of the ST participant families have been started.

श्री आर. नारायण, मुख्य महा प्रबन्धक, नाबार्ड, जयपुर (राज.) वाडी परियोजना प्रतापगढ़ (राज.) का शुभारम्भ करते समय कृषि उपकरण वितरित करते हुए।

Sh. R. Narayan, Chief General Manager NABARD, Jaipur (Rajasthan) distributing agri-equipment at launching of WADI Project in Pratapgarh (Rajasthan).

शुभारम्भ कार्यक्रम का आयोजन गांव वीरपुर में किया गया जिसमें मुख्य महा-प्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर (राज.) ने मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी. नई दिल्ली की अध्यक्षता में परियोजना गतिविधियों का उद्घाटन किया। चिन्हित किये गये गांवों से 700 किसानों ने भाग लिया। किसानों को कृषि प्रदान किये गये तथा परियोजना गतिविधियों की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर लिए आम के पौधे रोपित किये गये।

Launching programme was organized at village Veerpur in which Chief General Manager, NABARD, Jaipur (Raj.) inaugurated the implementation of project activities under the chairmanship of Chief Executive IFFDC, New Delhi which was attended by 700 farmers from the identified project villages. Agricultural equipments were provided to the farmers and mango tree saplings were also planted as a token of start of the activities.

IX. हिमालय हेतू उत्तरांचल आजीविका उत्थान परियोजना

माननीय सदस्यों को जानकारी है कि मार्च 2005 के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. को उत्तरकाशी जिले के नौगांव खण्ड के 25 गांवों में उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से कृषि विकास हेतु अर्न्तराष्ट्रीय कोष द्वारा वित्तपोषित "हिमालय हेतु उत्तारांचल आजीविका उत्थान परियोजना मिली। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वंय सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय

IX. UTTARANCHAL LIVELIHOOD IMPROVEMENT PROJECT FOR HIMALAYAS (ULIPH)

Hon'ble members are aware that IFFDC was awarded a project titled "Uttaranchal Livelihood Improvement Project in Himalayas" funded by International Fund for Agriculture Development (IFAD) through Govt. of Uttrakhand during March 2005 in 25 villages of Naugaon Block of Uttarakashi district. The main objective is to improve the livelihood of vulnerable groups in a sustainable manner

संस्थाओं को मजबूत कर कमजोर समूहों की आजीविका में स्थायित्व लाना है। प्रारम्भिक तौर पर यह 3 वर्ष के लिए है तथा वर्ष 2012–13 तक बढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में 911 लक्षित परिवार हैं जिनमें 288 गरीब, 394 अति गरीब तथा 229 अत्यन्त गरीब हैं।

प्रवेश बिंदू गतिविधियों के तहत लक्षित परिवारों को गेहूँ बीज (680 क्विंटल) दिया गया, नेपियर घास रौपण (संख्या 16717), चूजे (संख्या 3574) तथा फलदार पौध (संख्या 2245) प्रदान किए तथा 25 वीडियो शो आयोजित किए गये हैं। अब तक कुल 883 सदस्यता (871 महिलांए, 12 पुरुष) जिनमें 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं के साथ 92 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। इन समूहों द्वारा 5.96 लाख रुपए की बचत की गई है और 487 सदस्यों को 1.80 लाख रु. का ऋण दिया जा चुका है। 227 (183 पुरुष और 44 महिला) के साथ 20 कृषक स्वयं सहायता समूह भी बनाये जा चुके हैं।

स्वयं सहायता समूहों को 39 विभिन्न मोड्यूल पर प्रशिक्षण करवाए गए, जिससे 6694 संभागी लाभान्वित हुए। क्षमता निर्माण व जागरूकता हेतु 17 भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 181 व्यक्ति (120 महिला तथा 61 पुरुष) लाभान्वित हुए।

गेंहूं के 640 कि.ग्रा., मटर के 60 कि.ग्रा. बीज एवं 10 कि. ग्रा. धान के बीज, 25 नांद, 60 धूम्र रहित चूल्हे एवं 251 कृषि उपकरण भी वितरित किए गए हैं। अब तक 737 वर्मी कम्पोस्ट के गड्ढे तैयार किए जा चुके हैं। 1311 परिवारों को 1905 चूजे वितरित किए गऐ हैं।

स्वास्थ्य विभाग, नौगांव के तत्वधान में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 2 टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 105 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया तथा आयरन गोलियां उपलब्ध कराई गई तथा बच्चों को प्रतिरक्षण चिकित्सा उपलब्ध

परियोजना क्षेत्र में आयोजित स्वयं सहायता समूह जागरूकता सम्मेलन का एक दृश्य।

A view of Self Help Group Awareness Conference organised in the project area

डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी. स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उन्नत नस्ल के कुक्कुट पक्षी वितरित करते हुए।

Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC, distributing, Poultry birds of improved breed to SHG Members.

through promotion of Self Help Groups and strengthening local institutions initially for 3 years and likely to be extended up to the year 2012-13. Total target families of this project are 911 comprising of 288 poor, 394 poorer and 229 poorest.

Entry Point Activities (EPA) like wheat seed distribution (680 quintals), sowing of the Napier grass clips (16717 no.), distribution of chicks (3574 no.) and fruit plant saplings (2245 no.) to the target families and 25 video shows have been organized. So far, 97SHGs with a total membership of 883 (871 women and 12 men) comprising 60% Schedule Caste (SC) have been formed. These groups have saved an amount of Rs.5.96 lakhs and given loan for 487 times amounting to Rs. 1.80 lakhs. 20 Krishak Self Help Group have also been formed with the total membership of 227 (183 men and 44 women)

SHGs have been imparted trainings on 39 different modules, which benefited 6694 participants. For building capacity and raising awareness, 17 exposure visits were organized, which benefited 181 SHG members (120 women and 61 men).

640 kgs. wheat, 60 kgs. pea,10 kgs. of paddy seeds, 25 feeding troughs, 60 smokeless chullaha and 251 agricultural implements have also been provided. 737 vermi compost pits have been prepared. 1905 chicks of improved breed have been distributed to 1311 households.

IFFDC has organized 2 vaccination programmes in collaboration with the Health Department, Naugaon, in which 105 pregnant women were vaccinated and provided the iron tablets. Children were also given

कराई। जागरूकता बढ़ाने हेतु महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया, जिसमें 600 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।

आई.एफ.एफ.डी.सी. तकनीकी सलाहकार के रूप में स्वयं सहायता समूहों हेतु सरल सूक्ष्म ऋण तंत्र हेतु राज्य स्तर पर इस परियोजना में परामर्श प्रदान कर रही है।

X. ग्रामीण विकास के माध्यम से आजीविका सुधार (लिरड) परियोजना

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने इफको की सहायता से पांच ज (विकास के पंचकोणिय घटक) जल, जंगल, जमीन, जानवर तथा जन पर सहभागी पहुँचों तथा परिक्षित कार्यप्रणालियों एवं तकनीकों पर आधारित ग्रामीण विकास के माध्यम से आजीविका सुधार (एल.आई.आई.आर.डी.) परियोजना अप्रैल, 2006 से उड़ीसा के पांच कलस्टर अस्तरंग (जिला पुरी), पुरषोत्तमपुर (जिला गंजाम), मकाकल पाडा (जिला केन्द्रपाडा) तथा रानपुर (जिला नयागढ़) के 30 ग्रामों में तीन वर्षों के क्रियान्वयन हेतु गतिविधियां प्रारम्भ की हैं।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य लोगों में आय जनित गतिविधियाँ संचालन हेतू उनकी कुशलता उन्नयन सुनिश्चित के लिए संस्थागत विकास जैसेः– स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्षमता व आत्मविश्वास निर्माण करना; ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत् सम्बन्धित राज्य विभागों/संस्थाओं की भागीदारी से अनुकूल प्रयत्न करना; चिरन्तरता के लिए स्वरोजगारियों को सहकारी समितियों में संघीकरण; सहकारिता में भरोसा व विश्वास का निर्माण एवं इफकों के संवर्द्धन कार्यक्रमों का सशक्तिकरण कर कृषक समुदाय को लाभान्वित करना है।

वर्ष के दौरान संचालित घटकवार गतिविधियाँ निम्नानुसार हैंः–

सहभागी योजना प्रक्रिया

ग्राम सभाएँ: वर्ष के दौरान, 785 ग्राम सभाएँ (संचयी–1359) आयोजित की गई, इसमें 35,251 समुदाय सदस्यों (संचयी–61107) ने भाग लिया। ग्राम सभाओं ने समस्याओं/उनके समाधानों/ संयुक्त निर्णयों आदि पर विचार करने हेतु एक मंच प्रदान किया। इन ग्राम सभाओं का प्रभाव समुदाय में अधिक आत्मविश्वास, जागरूकता तथा उत्साह के रूप में दिखाई देता है।

त्वरित ग्रामीण अध्ययन (आर.आर.ए.) एवं सहभागी ग्रामीण अध्ययन (पी.आर.ए.): वर्ष के दौरान, 10 त्वरित ग्रामीण अध्ययन (संचयी–36) और 45 सहभागी ग्रामीण अध्ययन (संचयी–75) आयोजित किये गये जिसमें क्रमशः 477 एवं 1575 सदस्यों ने भागीदारी की, जो समुदाय के साथ सशक्त संबंध निर्माण में सहायक सिद्ध हुये।

immunization treatment. For increasing awareness, Women Empowerment Day was celebrated, which was participated by more than 600 women.

IFFDC as Technical Consultant has also provided consultancy in this project at the state level for Simplified Micro Credit System for SHGs.

X. LIVELIHOODS IMPROVEMENT THROUGH INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT (LIIRD) PROJECT

IFFDC started its activities to implement this Project during April 2006 in 30 villages of 5 village clusters viz: Astarang (Dist. Puri), Puroshottampur (Dist. Ganjam), Jagatsingh Pur (Dist. Jagatsingh Pur), Makakal Pada (Dist. Kendrapada) and Ranapur (Dist. Nayagarh) of Orissa based on the participatory approaches and tested methodologies and technologies on 'Panch J' (pentagonal component of development) viz. Jal, Jangal, Jameen, Janwar & Jan for three years duration is supported by IFFCO.

Main objectives of the project are to build capacity and confidence of individuals through institutional development like self help groups to ensure the up gradation of their skills for undertaking IGAs; to optimize the efforts with involvement of the concerned state departments/agencies working in the area of rural development; to federate the Self employed endeavor into cooperative institution for sustainability; build up the trust and confidence in cooperative system and strengthen IFFCO field programmes to benefit the farming community.

Details of the component wise activities conducted during the year are given below:

PARTICIPATORY PLANNING PROCESS

Village meeting: During the year, 785 village meetings (Cum. - 1359) were organized, in which 35251 community members (Cum. - 61107) participated. The meetings provided a platform to discuss about the problems/ solutions/ combined decision etc. Impact is visible in more confident, award and enthusiastic community.

Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rural Appraisal (PRA): 10 Rapid Rural Appraisals (cum. – 36) and 45 Participatory Rural Appraisals (cum.- 75) were organized with the participation of 477 and 1575 community members respectively, which helped in building strong rapport with the community.

विवेचित समस्या विश्लेषण (सी.पी.ए.) : वर्ष के दौरान, 4 सी.पी.ए. (संचयी–20) 720 सदस्यों के साथ समस्या विश्लेषण स्वयं ग्रामीणों द्वारा समस्याओं का पता लगाने एवं उनका प्राथमिककरण तथा आजीविका विकल्पों के उत्थान हेतु स्वयं की कार्य–योजना तैयार करने हेतु किये।

वार्षिक कार्य योजना (ए.डब्ल्यू.पी.) : 4 स्वयं सहायता समूहों (संचयी–22) ने अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार की जिसमें आगामी वर्ष में क्रियान्वयन के लिये गतिविधियों को सम्मिलित किया गया। ग्राम आजीविका विकास योजना निर्माण हेतू ग्राम समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की वार्षिक कार्य योजनाओं का संकलन किया गया।

संस्थागत विकास:

280 नये स्वयं सहायता समूहों का 3,392 (3,238 महिलायें और 154 पुरूष) सदस्यों के साथ अंगीकरण किया गया और इस प्रकार वर्तमान में संचयी रूप से 553 स्वयं सहायता समूहों कुल 6,805 सदस्य (6,528 महिलायें और 227 पुरूष) 96% से अधिक महिला भागीदारी के साथ कार्यरत् है।

स्वयं सहायता समूहों के अंगीकरण के अलावा परियोजना द्वारा अभिलेखों के रखरखाव हेतू सहायता प्रदान करने के माध्यम से उनको संस्थागत रूप प्रदान कर रही है। वर्ष के दौरान स्वयं सहायता समूहों को 220 केश बाक्स प्रदान किये गये। स्वयं सहायता समूहों को नियमित ढंग से समूह की बैठकें आयोजन के क्रम में बैठक व्यवस्था के उद्देश्य से दरीयाँ वितरित की गयीं। परियोजना के अंगीकृत गांवों में 771 दरियाँ (संचयी–930) स्वयं सहायता समूह सदस्यों में वितरित की गयी।

प्रभाव:

- स्वयं सहायता समूहों (महिला एवं पुरूषों) का गठन प्राकृतिक स्त्रोतों को एक विशिष्ट ढांचे में उत्पन्न कर रहा है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं की शीघ्र आवश्यकताओं, उनकी महत्त्वपूर्ण रूचियों को पूरा करने तथा उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद मिली। परियोजना, बचत एवं उधमिता विकास की प्रवृत्ति विकसित करने में समर्थ हुई है। वर्तमान में परियोजना क्षेत्र के सभी गाँवों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत विकास हुआ, जिससे यह सुनिश्चित

श्री डी.के. भट्ट, अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी. एवं श्री सिमांचल पाधी, निदेशक, इफको, परियोजना क्षेत्र जिला गंजाम (उडीसा) में ग्रामीण समुदाय सदस्यों के साथ वार्तालाप करते हुए।

Sh. D.K. Bhatt, Chairman, IFFDC and Sh. Simanchal Padhi, Director, IFFCO interacting with village community members in project area, Distt. Ganjam (Orissa)

Critical Problem Analysis (CPA): During the year, 4 CPAs (cum.- 20) involving 720 community members were organized to find out and prioritise the problems of the villagers themselves and to prepare their own work plans to enhance their livelihood options.

Annual Work Plan (AWP): 4 SHGs prepared their Annual Work Plans (cum.- 22) comprising of different activities for implementation during the next year. AWPs of each SHG are consolidated with active participation of the village community to prepare Village Livelihood Development Plan.

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

280 new Self Help Groups with the total membership of 3392 (3238 women and 154 man) were adopted and at present cumulatively 553 SHGs with the total membership of 6805 (6528 women and 277 men) are functional with more than 96% of women participation.

Apart from adopting SHGs the project is making efforts in institutionalizing them by facilitating for maintenance of the records etc. During the year, 220 cash boxes were provided to the SHGs. Further, 771 durries (cum.- 930) were also being provided to individual SHGs for sitting purpose in order to organize the SHG meetings properly.

Impact

- Formation of Self Help Groups (both Women and Men) is engendering the natural resources in a specific framework. SHGs are helping in addressing the fulfillment of immediate needs and the strategic interests of women which is helping to bring them in the mainstream. The project has been able to develop a sense of savings & entrepreneurship. All project villages are at present institutionalized through SHGs which is ensuring that the women and

हुआ कि सभी सहभागी योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन गतिविधियों में महिलाऐं एवं सीमान्त समुदाय (गरीब) प्रभावी रूप से सम्मिलित है।

- स्वयं सहायता समूह उन्नत कृषि के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य, साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक शोषण तथा सामाजिक बुराईयां जैसे शराब की लत, जुआ, तम्बाकू का उपयोग इत्यादि से संबंधित समस्याओं पर विचार– विमर्श करने लगे तथा इन समस्याओं से निपटने के लिये उचित समाधानों का अभिनिर्धारण कर रहे है।
- स्वयं सहायता समूह, दीर्घकाल चिरन्तरता के लिये आंतरिक ऋण गतिविधि प्रारम्भ करने की प्रक्रिया में है। गतिशीलता से समुदाय में संलग्नशीलता, स्वामित्व और परस्पर संबंधों की अनुभूति का निर्माण हुआ।
- एनीमेटरस् (पैरा–प्रोफेशनल्स) महिला और पुरूषों दोनों की गांवो में से ही पहचान कर उनको प्रशिक्षित किया गया जो ग्राम विशेषज्ञों की भाँति कार्य कर रहे है और वह अपने समूहों या गांवों के प्रति उत्तरदायी है।
- सरकारी अभिकरणों, गैर–सरकारी संस्थाओं, सहकारी और अन्य सस्थाओं के साथ सम्बन्ध और समुदाय में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर जागरूकता बढ़ी है।

सामाजिक विकास

स्वास्थ्य शिविरः 74 स्वास्थ्य शिविर (संचयी–111) आयोजित किये गये, जिसमें 11,878 समुदाय सदस्य (संचयी–17800) लाभान्वित हुए। स्वास्थ्य शिविरों के अतिरिक्त समुदाय सदस्यों को 19 मैडिकल किट (संचयी–205) उपलब्ध कराई गयीं जिससे 3,994 समुदाय सदस्य (395 पुरुष तथा 3,599 महिलाएं) लाभान्वित हुए।

सिलाई मशीनों का वितरणः 134 सिलाई मशीनों (संचयी–204) का वितरण स्वयं सहायता समूहों को किया गया जिससे 1,666 महिला सदस्य (संचयी–2,507) लाभान्वित हुई।

कशीदाकारी केन्द्रः ऐसे 2 केन्द्र परियोजना ग्रामों में स्थापित किये गये है, जिनसे 21 महिला सदस्य लाभान्वित हो रही हैं।

लिरड परियोजना के सजीवकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि श्रीमती सूरमा पाधी, सहकारिता मंत्री, उड़ीसा का स्वागत करते हुए डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी आई.एफ.एफ.डी.सी., नई दिल्ली।

Dr. P.S. Marwaha, Chief Exeuctive, IFFDC, New Delhi welcoming Mrs. Surma Padhi, Co-operative Minister, Orissa, Chief Guest of Animators Training of LIIRD Project

marginalized communities are actively involved in the participatory planning and implementation exercises.

- Self Help Groups in addition to issues related to improved farming are also discussing their problems related to health, functional literacy, education of children, social exploitation and social evils like addiction to alcohol, gambling, tobacco consumption etc. and are identifying suitable solutions for their problems. Self-Help Groups are in the process of starting inter-loaning activities for long term sustainability. Mobilization of SHGs has created a sense of cohesiveness, ownership and belongingness among communities.
- Animators (para-professionals) both male and female identified and trained from project villages itself are working as Village specialists and are accountable to their groups or villages.
- Linkages with Government agencies, NGOs, Cooperatives and other institutions and awareness of the community about various development schemes has increased.

SOCIAL DEVELOPMENT

Health camps: 74 health camps (cum. - 111) were organized in which 11878 community members (cum.- 17800) were treated. In addition to health camps community members were also provided 19 medical kits (cum.- 205) which have benefited 3994 community members (395 male and 3599 female).

Sewing machine distribution: 134 sewing machines (cum.- 204) have been provided to SHGs which have benefited 1666 women members (cum.- 2507).

Embroidery centre: 2 such centers have been established in the project villages which are benefiting 21 women members.

आय जनित गतिविधियां: स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 17 प्रकार की आय जनित गतिविधियां (आई.जी.ए.), जैसे सिलाई/कशीदाकारी, रेडीमेड गारमेन्टस्, पापड/अचार/बड़िया/जैम एवं अवलेह बनाना, कुक्कुट/बकरी पालन, मछली पालन, सब्जी उत्पादन, डेरी उद्योग, माचिस की तिल्ली बनाना, थैला/चंदौवा बनाना, वर्मी कम्पोस्ट, मशरूम उत्पादन, सजावटी सामान, पंसारी की दुकान, मसाला बनाना, किराये पर पावर टिलर, पम्प सैट तथा धान थ्रैशर इत्यादि प्रारम्भ करने में सहायता प्रदान की। 2020 स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने रु. 34.19 लाख (रु. 5.36 लाख गैर–कृषि से तथा रु. 28.83 लाख कृषि आधारित) आयजनित गतिविधियों से आय अर्जित की। ग्रामीण समुदाय को वृहद स्तर पर लाभ के लिए परियोजना की गतिविधियों को कालाहांडी, बोलनगीर, बौध, नुवापाडा, रायगढ़ा, पुरी, नयागढ़, गंजाम तथा कोरापुत जिलों के और 47 गांवों में भी बढ़ाया जा रहा है।

Income Generation Activities: For economical self sustainability IFFDC has facilited to started the SHGs about 17 types of Income Generation Activities (IGA) like Sewing/Embroidery, Readymade Garments, Papad/Pickle/Badi/Jam & Jelly making, Poultry/Goatry, Pisciculture, Vegetable cultivation, Dairy farming, Incence stick Making, Bags making/chandua making, Vermi composting/composting, Mushroom cultivation, Decorative material, Grocery shops, Masala making, renting of power tiller, pump set and paddy thresher etc. 2020 SHG members have earned Rs. 34.19 lakhs (Rs. 5.36 lakhs from non-fram and Rs. 28.83 lakhs from farm based) IGAs. The activities of the project are also being disseminated in 47 more villages of Kalahandi, Bolangir, Boudh, Nuapada, Rayagada, Puri, Nayagarh, Ganjam and Koraput districts for benefiting the rural community at a large scale.

Types of IGA (No.)	17
SHGs Members Engaged (No.)	2020
Income from Farm Sector IGA (Rs. Lakh)	28.83
Income from Non-Farm Sector IGA (Rs. Lakh)	5.30
Total Income (Rs. Lakh)	34.19

स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित विभिन्न आय अर्जन गतिविधियों का दृश्य।

View of various income generation activities undertaken by SHGs.

गैस लाईट, ग्राईन्डर और छलनी वितरण: 52 गैस लाईटों का वितरण किया गया जिससे 701 सदस्य लाभान्वित हुये, 85 ग्राईन्डर और 1429 छलनियों को वितरण किया गया जिससे 941 तथा 441 लाभान्वित हुए।

Gas light, Grinder and Sieve distribution: 52 gas lights have been provided benefiting 701 members, 85 grinders and 1429 sieves have been distributed benefiting 941 and 441 members.

स्वास्थ्य एवं पोषाहार जानकारी: इस तरह के 111 शिविर आयोजित किये गये जिसमें 17,800 समुदाय सदस्य लाभान्वित हुये।

खेल सामग्री: खेल सामग्री के 29 सेट 29 स्वयं सहायता समूहों के 348 सदस्यों के लिए वांटे गये।

सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध अभियान: इस तरह के 5 अभियान आयोजित किये गये जिसमें 273 समुदाय सदस्यों (54 पुरूष और 219 महिलायें) ने भाग लिया।

प्रभाव

- लिंग संबंधों में सुधार से परियोजना में प्रभावशाली परिणाम आ रहे है। परियोजना में महिला और पुरूष दोनों की चिरन्तर आजीविका पर बल दिया गया। यह पुरूषों और महिलाओं की योजना निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी को सुनिश्चित करता है। लिंग समानता में वृद्धि हुई है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि तुलनात्मक रूप से पहले की अपेक्षा महिलाओं की विभिन्न कार्यकलापों में भागीदारी सार्थकता के साथ बढ़ी है।
- सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह स्तर पर प्रारम्भ विभिन्न आय जनित गतिविधियों तथा लघु उद्योग इन संस्थाओं के स्वःस्थायित्व तथा सामान्यतः ग्रामीण समुदाय व विशिष्ट रूप से भूमिहीन परिवारों के सामाजिक–आर्थिक स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

कृषि विकास

कम्पोस्ट पिट व वर्मी कम्पोस्ट: 205 कम्पोस्ट पिट (संचयी 245) और 53 वर्मी कम्पोस्ट पिट वर्ष के दौरान तैयार किये गये, जिससे क्रमशः 1,795 सदस्य (185 पुरूष और 1,610 महिलायें) और 713 सदस्य (153 पुरूष और 560 महिलायें) लाभान्वित हुए।

औजार : 59 धान गहाई–मशीन (लाभान्वित 623), 4,176 हंसिया (लाभान्वित 4,176), 8,881 फावड़े (लाभान्वित 3,881), 25 पावर युक्त टिलर (लाभान्वित 301), 11 विद्युत चलित ठेला (लाभान्वित 1494), 151 छिड़काव यंत्र (लाभान्वित 2423), 140 पम्प (लाभान्वित 2131) वितरित की गयी और 2 जल हौज (लाभान्वित संख्या 150) भी बनाये गये।

Health & Nutritional Awareness: 111 such camps have been organized in which 17800 community members were benefited.

Sports Items: 29 sets of the sports items have been distributed to 29 SHGs for 348 members.

Campaign on social evil: 5 such campaigns were organized in which 273 community members (54 male and 219 female) participated.

Impact

- Improvement in the gender relations is influencing the project outcomes. The project emphasized on sustainable livelihood both for men and women. It is ensuring active participation of both men & women in planning and decision making process. Gender equality has grown which is clear from the fact that women participation in different activities increased significantly as compared to the past.
- Various income generating activities and micro-enterprises started at member and self help group level are leading towards self-sustainability of these organizations and improvement of the socio-economic status of the rural community in general and landless families in particular.

AGRICULTURE DEVELOPMENT

Compost Pit and vermi compost: 205 compost pits (cum.245) and 53 vermi compost pits have been prepared during the year benefiting 1795 members (185 male and 1610 female) and 713 members (153 male and 560 female) respectively.

Implements: 49 Paddy threshers (beneficiaries 623), 4176 Hansia (beneficiaries 4176), 3881 Fawda (beneficiaries 3881), 25 Power tillers (beneficiaries 301), 11 Power trolleys (beneficiaries 1494), 151 Spray machine (beneficiaries 2423), 140 Pumps (beneficiaries 2131) were distributed and 2 water tanks (no. of beneficiaries 150) were prepared.

लिरड परियोजना द्वारा प्रदत्त उन्नत कृषि यंत्रों के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाऐं।

Women SHG members alongwith improved agriculture implements provided by LIIRD Project.

सब्जी बीज वितरणः 48 स्वयं सहायता समूहों को अच्छी किस्म के अधिक–उपज वाले बीज प्रदान किये गये, जिससे 619 स्वयं सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हुये।

धान, मूंगफली बीज का वितरणः 300 किलो. धान और 500 किलो. मूंगफली बीज का वितरण क्रमशः 60 और 70 समुदाय सदस्यों को किया।

18 सब्जी उत्पादन तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम इमेज में आयोजित किए गये जिसमें 581 सदस्यों (54 पुरूषों और 527 महिलाओं) ने भाग लिया।

प्रभाव

- परियोजना गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें पूरे वर्ष भर हेतु पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने में सहायता कर रही है। आई.एफ.एफ.डी.सी. किसानों को उन्नत किस्म के बीज, कृषि उपकरण, खाद, उर्वरक और कीटनाशक इत्यादि के साथ–साथ आवश्यकतानुसार कौशल और नवीन तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के माध्यम से सहायता कर रही हैं ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके।

पशुधन विकास

पशु चिकित्सा शिविरः इस वर्ष के दौरान राज्य पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान से 77 पशु चिकित्सा शिविरों (संचयी–113) का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 34,392 विभिन्न प्रकार के पशुओं का इलाज किया गया। 12 पशु–चिकित्सा कार्यशालाओं (संचयी–60) का आयोजन भी किया गया जिसमें 3,831 व्यक्तियों ने भाग लिया।

बकरियों का वितरणः 1194 परिवारों (संचयी–1863) को उन्नत नस्ल की बकरियां प्रदान की गयीं। बकरियों से संबंधित 21 जाकरूकता शिविर कम कार्यशालायें भी आयोजित की गयी जिसमें 1,329 लोगों ने भाग लिया।

मछली बीज का वितरणः वर्ष के दौरान 13399 ग्रामवासियों को 1,33,040 मछली के बीजों (संचयी–2,66,090) का वितरण किया गया।

18 पशुधन विकास तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम इमेज में आयोजित किए गये जिसमें 581 सदस्यों (54 पुरूषों और 527 महिलाओं) ने भाग लिया।

प्रभाव

- पशुओं में बीमारियों व मृत्यु में कमी से पशु उत्पादकता में वृद्धि। यह परियोजना गांवों में पशुचिकित्सा शिविरों के आयोजन के द्वारा समुदाय में बचाव विधियों को अपनाने व पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के प्रति जागरूकता उत्पन्न से संभव हो पाया।

Vegetable seed distribution: 48 SHGs were provided with good quality high yielding vegetable seeds, which have benefited 619 SHGs members.

Paddy, Groundnut seed distribution: 300 kgs. Paddy and 500 kgs. Groundnut seed have been distributed amongst 60 and 70 community members respectively.

18 trainings on Vegetable production Technology were organized at IMAGE in which 581 community members (54 male and 527 female) participated.

Impact

- The project is helping to make the poor self sufficient and provide them sufficient food for the whole year. IFFDC helped the farmers by providing them improved seeds, farm equipments, fertilizers, manures and pesticides etc. along with need based skills and latest technical knowledge so that the farmers can draw direct benefits, enhance their crop production and thereby improve their income.

ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT

Veterinary Camp: During this year, 77 Veterinary camps (Cum.-113) were organized in collaboration with State Veterinary Department. Total 34392 animals of different types were treated in these camps. 12 Veterinary workshops (cum.-60) were also organized which were participated by 3831 persons.

Goat distribution: 1194 house holds (cum.-1863) were provided with goats of improved breed. 21 Goatry awareness camps cum workshops were organized which were participated by 1329 persons.

Fingerlings distribution: 133040 fish Fingerlings (cum.-266090) were distributed to 13399 villagers.

18 animal husbandry trainings were organized at Institute on Management of Agriculture Extension (IMAGE) which were participated by 581 community members (54 male and 527 female).

Impact

- There is an increase in the productivity of animals due to reduction in diseases and casualties in the animals. This has been achieved by creating awareness amongst the community for adopting preventive methods and measures to improve the health of animals.

जल संसाधन विकास

लिफ्ट बोरवेल : कुंये सिचाई जल के मुख्य स्त्रोत हैं। ये घरेलू प्रायोजन और पशुओं के पानी पीने के लिये भी उपयोग किये जाते है। पिछले कुछ दशकों से जल स्तर में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष के दौरान, 2 लिफ्ट बोरवेलों का निमार्ण किया गया जिससे 147 परिवार लाभान्वित हुये और 71 हेक्ट. क्षेत्र की सिंचाई में मदद भी मिली।

1,940 मीटर सिंचन पाईप प्रदत्त किये गये जिससे 86 परिवार लाभान्वित हुये और 50 हेक्ट. क्षेत्र सिंचित हुआ।

अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी लिरड परियोजना उड़ीसा क्षेत्र में "लिफ्ट सिंचाई प्रणाली" के बारे में चर्चा करते हुए।

Chairman, IFFDC discussing about "Lift Irrigation System" in LIIRD project area (Orissa).

सिंचाई नाली: 3 नालियों का निमार्ण किया गया जिससे 100 परिवार लाभान्वित हुये, 60 हेक्ट. क्षेत्र सिंचित हुआ।

जलाशय गहरीकरण: वर्ष के दौरान, 5 जलाशयों का गहरीकरण किया गया जिससे 160 परिवार लाभान्वित हुये और 115 हेक्ट. क्षेत्र की सिचांई में सहायता मिली।

प्रभाव

- आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के पश्चात् मुख्यतः पीने के पानी की आसान उपलब्धता तथा चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप पशु उत्पादकता में वृद्धि तथा महिला श्रम में कमी आयी।
- जल संसाधन विकास कार्यक्रम के प्रभाव शीघ्र दिखे। सभी गांवों में किसानों ने प्राथमिक तौर पर अधिकतम वर्षा जल को संग्रहित और आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों का सूत्रपाद एकजुटता से किया।
- जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण ने किसानों को जल ग्रहण क्षेत्र में खाली पड़े खेतों को विकसित कर नकदी फसलों, सब्जियों और फलों की खेती करने के लिये प्रेरित किया।
- जल संसाधन संरचनाओं के निर्माण के दौरान, परियोजना समुदाय के लिये गांवों में ही रोजगार का सृजन हुआ।
- सिंचाई के लिए एकत्रित पानी की उपलब्धता का सीधा प्रभाव भूमि उत्पादकता व फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा नयी फसलों के नवागमन पर पड़ा है। भोजन की आत्मनिर्भरता व उपज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

WATER RESOURCE DEVELOPMENT

Lift bore well: Wells are the main source of irrigation water. These are also used for domestic purpose and drinking water for cattle. Water table is continuously decreasing for last few decades. During the year, 2 lift bore wells were constructed which benefited 147 H/Hs and also helped to irrigate 71 hectare area.

1940 meter irrigation pipes were provided which have benefited 86 H/Hs to irrigate 50 hectare area.

Irrigation channel: 3 channels have been constructed benefiting 100 H/Hs to irrigate 60 hectare area.

Pond deepening: During the year, 5 ponds were deepened which benefited 160 H/Hs. and also helped to irrigate 115 hectare area.

Impact

- Construction of water structures is leading to easier access to drinking water and increased fodder availability thereby resulting into increased productivity of animals as well as reduction in women's drudgery.
- The impacts of the Water Resources Development programme are immediate. Invariably in all the villages, the farmers worked unitedly primarily for harvesting maximum rain water and to initiate various economic development and social welfare activities.
- Construction of water harvesting structures has motivated the farmers in the watershed area to develop lands lying idle for cultivating cash crops, vegetables and fruit crops.
- Construction of the water resource structures, in the project generated employment for the community within the project villages itself.
- Availability of harvested water irrigation has a direct effect on productivity of land and Introduction of high yielding crop varieties and new crops Food self-sufficiency and quality of produce are improving.

वानिकी विकास

वर्ष के दौरान, 2,07,180 फलों के पौधे मुख्यतः आम, अमरूद, नारियल, केला, चीकू और नींबू (5,790 समुदाय सदस्य लाभान्वित), 21,758 वानिकी पौधे मुख्यतः सुबबूल, बबूल, बांस, सफेदा (2,097 समुदाय सदस्य लाभान्वित) और 66,500 रतनजोत पौधों (322 समुदाय सदस्य लाभान्वित) का रोपण किया गया।

प्रभाव

- वानिकी व अन्य वृक्षारोपण से पर्यावरणीय सुधार में सहायता तथा समुदाय की ईंधन लकड़ी, इमारती लकड़ी और चारे की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

श्री दया कृष्ण भट्ट, अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी., लिरड परियोजना क्षेत्र में फलदार पौध रोपित करते हुए।

Sh. D.K. Bhatt, Chairman, IFFDC planting fruit sapling in LIIRD project area.

FORESTRY DEVELOPMENT

During the year, 2,07,180 fruit plants mainly mango, Guava, coconut, banana, sapota and lemon (beneficiaries 5790 community members), 21,758 forestry plants mainly subabool, acacia, bamboo, eucalyptus (beneficiaries 2097 community members) and 66,500 jatropha plants (beneficiaries 322 community members) were planted.

Impact

- Forestry and other plantations are helping in environment upgradation and catering to the fuel wood, timber and fodder needs of the community.

क्षमता निर्माण उपाय

सजीवकत्ताओं तथा ग्रामीण समुदाय को परियोजना अवधानों से संबन्धित विभिन्न घटकों पर इमेज, भुवनेश्वर तथा आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा परियोजना गांवों में प्रारम्भ किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, 16 बाहरी एम्सपोजर भ्रमण (756 लाभान्वित) और 93 कार्यशालाओं (प्रतिभागी 14,407) आयोजित की गयी। 141 प्रशिक्षण सह एक्सपोजर भ्रमण, 18 दलों में (लाभान्वित 5,607 जिसमें 764– पुरूष और 4,843– महिलायें) आयोजन इमेज भुवनेश्वर में किया गया। बाहरी एक्सपोजर भ्रमण स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये विभिन्न मुख्य पहलूओं जैसे आधुनिक पशुपालन, सब्जी उत्पादन, आदि पर आयोजित किये गये। इमेज भुवनेश्वर में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्रशिक्षण किट भी दिए गये।

श्री डी.के. भट्ट, अध्यक्ष आई.एफ.एफ.डी.सी., डॉ. डी.पी. पात्रा, मण्डल प्रबन्धक, इफको, कोलकाता तथा श्री एस.के. सामन्त्रे, राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, भुवनेश्वर के साथ सजीवकर्त्ता प्रशिक्षण में सम्बोधित करते हुए

Sh. D.K. Bhatt, Chairman, IFFDC along with Dr. D.P. Patra, Journal Manager, IFFCO, Kolkata and Sh. S.K. Samantray, SMM, IFFCO, Bhubneshwar, addressing during animators training

CAPACITY BUILDING MEASURES

Regular trainings on various components related to the project interventions are being imparted to the animators and rural communities at IMAGE, Bhubneshwar and in the training centers started by IFFDC in the project villages.

During the year, 16 External Expository tour (beneficiaries 756) and 93 workshops (participants 14407) were organized 141 training cum expository tours in 18 batches (beneficiaries 5607 comprising 764 - Male and 4843-Female) were organized at IMAGE Bhubaneshwar. External Expository tours for SHGs members was organized on important aspects like advanced animal husbandry, vegetable production etc. During the training at IMAGE, Bhubaneshwar, training kits were also provided to the participants.

8 फसल गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें 816 समुदाय सदस्यों (272 पुरुष व 544 महिलाओं) ने भाग लिया। परियोजना क्षेत्र में 10 सहकारी सप्ताह, 14 महिला दिवस मनाये गये जिसमें क्रमशः 650 व 1365 समुदाय सदस्यों ने भाग लिया। मशरूम उत्पादन पर 54 प्रशिक्षण दिये गये जिसमें 1201 समुदाय सदस्यों (430 पुरुष तथा 771 महिलाओं) ने भाग लिया।

प्रभाव :

- किसानों को उनके उत्थान हेतू लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वे एक्सपोजर भ्रमण के माध्यम से नयी तकनीकियों को सीख रहे हैं तथा उनका अपने गांवों में प्रसार कर रहे हैं।
- समुदाय को आवश्यकता आधारित कौशल उन्नयन विभिन्न स्त्रोत केन्द्रों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। वृद्धित कौशलता गरीब लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अवसर प्रदान कर रही है तथा उनकी आय में संपूरक हैं।

श्री दया कृष्ण भट्ट, अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी. को अशुरकुमारी, जिला नयागढ़ (उड़ीसा) में सम्मानित करती हुई श्रीमती सूरमा पाधी, सहकारिता मंत्री, उड़ीसा।

Sh. D.K. Bhatt, Chairman, IFFDC being honoured by Smt. Surma Padhi, Cooperation Minister, Orissa at Ashrukumaril, Distt. Nayagarh (Orissa)

परिपूर्ण प्रभाव :

प्रारम्भिक अवस्था में परियोजना क्षेत्र के ग्रामों की स्थिति उपेक्षित, सीमान्त, निम्नवर्ति प्रदर्शित होती थी। परियोजना के लिए समुदाय की गरीब सामाजिक– आर्थिक स्थिति एक चुनौतिपूर्ण कार्य था।

कार्यक्रम जिसमें नवीनतम उन्नत तकनीकी, अच्छी शिक्षा, अनुत्पादक खर्चों में बचत आदि पर समुदाय की जागरूकता में वृद्धि से सामाजिक बुराईयों को कम करने में सहायता मिल रही है जिसमें अन्ततः उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है।

अब सदस्यों ने सूचना, तकनीकी, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा प्राकृतिक स्त्रोतों पर पहुँच के रूप में आजीविका के विभिन्न विकल्पों को विकसित करना प्रारम्भ कर दिया है। संक्षिप्त में, सहभागी दृष्टिकोणों के माध्यम से किये जा रहे अथक प्रयास से गरीब समुदाय अपनी आजीविका विकास हेतू आगे बढ़ रहा है।

8 crop seminars were organized in which 816 community members (272 male and 544 female) participated. 10 Cooperative Week and 14 Women's Days were celebrated in the project area which were participated by 650 and 1365 community members respectively. 54 trainings on mushroom cultivation were imparted in which 1201 community members (430 male and 771 female) participated.

Impact

- Farmers are being made aware of various ongoing government schemes for their uptliftment. They are learning the new techniques through exposure visits and disseminating them in their respective villages.
- Various resource centers are providing need-based skill enhancement to the communities. The augmented skills are providing opportunities for the poor people to supplement their incomes to improve their economic condition.

Overall Impact:

At the initial stage, the project villages area exhibited an ignorant, marginalized, down-trodden picture. The poor socio-economic conditions of the community were a challenging task for the project.

The programmes which are increasing awareness of the community about benefits of latest improved technology, better education, saving on unproductive expenditure are helping in reducing the social evils, which ultimately is improving their livelihood

Now members have started developing various livelihoods options in the form of access to information, technologies, common property and natural resources. In nutshell, strenuous efforts being made through participatory approaches are enabling the poor community to move ahead to enhance their livelihood.

आई.एफ.एफ.डी.सी. को डॉ. हरेकृष्णा मेहताब ट्रस्ट, उड़ीसा द्वारा **"डॉ. हरेकृष्णा मेहताब अवार्ड–2007"** तथा **"सुर तरंग अवार्ड"** से राज्य में गरीब ग्रामीण समुदाय की आजीविका संवर्द्धन हेतु श्रेष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। माननीय श्री अरविन्द धाली, भूतपूर्व सहकारिता मंत्री, उड़ीसा, ने आई.एफ.एफ.डी. सी., के समन्वयक (उ.–पू.) को "डॉ. हरेकृष्णा मेहताब सम्मान–2007" प्रदान किया।

माननीय श्री अरविन्द धाली, भूतपूर्व सहकारिता मंत्री, उड़ीसा, आई.एफ.एफ.डी.सी., के समन्वयक (उ.–पू.) को "डॉ. हरेकृष्णा मेहताब सम्मान–2007" प्रदान करते हुए।

Hon'ble Arvind Dhali, Ex. Cooperation Minister, Govt. of Orissa honouring Coordinator (N.E.) IFFDC with the prestigious "DR. HAREKRUSHNA MAHATAB Award -2007".

IFFDC has also been awarded with **"DR. HAREKRUSHNA MAHATAB Award - 2007"** by Dr. Hare Krishna Mahatab Trust, Orissa and **"SUR TARANG AWARD"** for its excellent contribution towards livelihood enhancement of poor rural community in the state. Sh. Arvind Dhali, Hon'ble Ex. Cooperative Minister, Govt. of Orissa presented Dr. Mehtab Award to IFFDC Coordinator (N.E.) Bhubaneshwar.

XI. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) परियोजना

एक गौरवपूर्ण जीवन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। एक गौरवपूर्ण जीवन शैली के लिये, गरीबी एक विघ्न है। चिरन्तर आय और गरीबी की रूकावटों नष्ट करने में, स्व–रोजगार एक सार्थक कदम है। भारत सरकार ने प्रभावी स्व–रोजगार कार्यक्रम 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार' (एस.जी.एस.वाई.) का सूत्रपाद किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को स्व–रोजगार हेतु आय अर्जन गतिविधियों में सहायता दी जाती है। वह व्यक्ति जो आय अर्जन गतिविधियों में संलिप्त रहकर स्व–रोजगार करता है, को स्वरोजगारी कहते है। वे व्यक्तिगत रूप से या समूहों में इस गतिविधि को संचालित करते है उन्हें स्वयं सहायता समूहों के नाम से जाना जाता है। सरकारी, गैर–सरकारी और बैंकों की मदद से इसके अंतगर्त, 4 या 5 गतिविधियां प्रत्येक खण्ड में चुनी जाती है। इन्हें मुख्य गतिविधियाँ कहा जाता है, जिससे स्वरोजगारियों को प्रतिमाह आमदनी होती है। प्रायः गांवों में लोग प्रतिभावान होते है।

XI. SWARNJAYANTI GRAM SWAROJGAR YOJANA (SGSY) PROJECT

A life of dignity is the right of every citizen. Poverty is an obstruction to a dignified life. Self- employment is a significant step to have sustained incomes and remove the shackles of poverty. Government of India has introduced Self-Employment programme 'Swarnajayanti Gram Swarozgar' (SGSY). Under the SGSY, assistance is provided to the poor families living below the poverty line in rural areas for taking up self employment. The persons taking up Self-Employment are called swarozgaris. They take up the activity either individually or in Groups, called the Self-Help Groups. For this purpose, 4 to 5 activities are selected in each Block with the help of officials, non-officials and the Bankers. These are called 'Key Activities' which can give the Swarozgaris regular income every month. Quite often, in villages, people have skills.

डा. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी., नई दिल्ली, डॉ. जी.पी. तिवारी, वरि. परियोजना समन्वयक, रतलाम, जिला मन्दसौर (म.प्र.) के परिदृश्य योजना निर्माण के अवसर पर श्री एम.एल. राठौर, जिला प्रमुख, मन्दसौर, जिला प्रशासन के अधिकारियों व आई.एफ.एफ. डी.सी. दल के साथ।

Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC, New Delhi, Dr. G.P. Tewari, Sr. Project Coordinator, Ratlam alongwith Sh. M.L. Rathore, Zila Pramukh, Dist. Govt. officials and IFFDC team at Mandsaur (MP) during preparation of District Perspective Plan.

परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार की वित्तिय सहायता से जिला पंचायत के द्वारा केन्द्र सरकार की एस.जी.एस. वाई. परियोजना के तहत अप्रैल, 2006 से गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के अन्तर्गत संगठित करने तथा आजीविका वर्धन के लिए स्वरोजगार संवर्द्धन हेतू उन्हें विभिन्न संस्थानों से जोड़ने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना में स्वयं सहायता समूहों का गठन और इसका प्रबंधन तथा स्वयं सहायता समूहों का क्षमता निर्माण सम्मिलित है।

जिला रायसेन, रतलाम, मन्दसौर, नीमच विदिशा, देवास तथा श्योपुर जिलों में कार्य प्रगति पर है। रायसेन जिले की सांची और बेगमगंज ब्लॉक में 527 सदस्यों (451 महिलाऐं तथा 76 पुरुष) के साथ 45 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा 148 सदस्यों को एम.ई.डी. पर 4 प्रशिक्षण प्रदान किये गये। रतलाम जिले के 3 ब्लॉकों सैलाना, पिपलौदा एवं रतलाम में 1446 सदस्यों (1034 महिलाऐं तथा 412 पुरुष सहित) 120 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा 812 सदस्यों के लिए 20 प्रशिक्षण आयोजित किए गये।

मन्दसौर जिले में 38 स्वयं सहायता समूह 428 सदस्यता (408 महिला एवं 20 पुरुष) के साथ गठित किये गये। 26 प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 2162 सदस्यों को समूह प्रबन्धन पर प्रशिक्षण व मध्यान्ह भोजन स्कीम की जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त मन्दसौर में नाबार्ड के लिए 20 प्रशिक्षणों (1940 संभागी) व नीमच जिले में एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत 10 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

सामुदायिक संगठक, आई.एफ.एफ.डी.सी., मन्दसौर (म.प्र.) को विकास परियोजनाओं में उनके विशिष्ठ योगदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया गया।

विदिशा तथा देवास जिलों में क्रमशः 176 सदस्यों (140 महिला व 36 पुरुष) के साथ 16 व 532 सदस्यों (506 महिला व 26 पुरुष) के साथ 52 समूहों का गठन किया गया है। इसी प्रकार से, जिला श्योपुर में 49 समूह गठित किये गये जिसकी सदस्यता 539 हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विकासखण्ड गोरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) में भी इस परियोजना का क्रियान्वयन जनवरी 2006 से किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी.

The project is being implemented with financial assistance of govt. of M.P. through Zila Panchayats since April 2006 under the SGSY scheme of Central Government to bring rural poor into the fold of SHGs and link them with various institutions to promote self employment for generation of livelihood. The project includes formation and Management/ Capacity Building of SHGs.

Work is under progress in Raisen, Ratlam, Mandsaur, Neemuch, Vidisha, Dewas and Sheopur districts. 45 SHGs with total membership of 527 (female 451 & male 76) have been formed in Sanchi and Begumganj blocks of Raisen district and imparted 4 trainings on MED to 148 members. 120 SHGs have been formed in 3 blocks of Ratlam district i.e. Sailana, Piploda & Ratlam with 1446 members (female 1034 & male 412) were formed and organized 20 trainings in which 812 members participated.

In Mandsaur district, 38 SHGs with membership base of 428 (female 408 and male 20) have been formed. 26 trainings have been organized in which 2162 members were imparted inputs regarding SHG management and awareness creation on mid day meal scheme. In addition, 20 trainings (1940 participants) with financial support of NABARD in Mandsaur district and 10 trainings under SGSY have also been imparted in Neemuch district.

Community organizer of IFFDC Mandsaur (M.P.) was honored by District Administration Mandsaur at Republic day function for their outstanding contribution made towards development projects.

उप–खण्ड न्यायधीश, मन्दसौर, कु. निधि शर्मा, सामुदायिक संगठक, आई.एफ.एफ.डी.सी., मन्दसौर को गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर सम्मानित करते हुए।

Ms. Nidhi Sharma, Community Organiser, IFFDC, Mandsaur (M.P.) being honoured by SDM, Mandsaur at the occassion of Republic Day function.

In Vidisha and Dewas districts (M.P.) 16 and 52 SHGs with 176 (female 140, male 36) and 532 (female 506, male 26) members respectively have been formed. Similarly in Sheopur district (M.P.), 49 SHGs have been formed with 539 members.

IFFDC has also been implementing this scheme in 23 villages of Gorihar block of district Chattarpur (MP) since January 2006. 17 SHGs formed by IFFDC have

द्वारा 17 स्वयं सहायता समूहों का गठन करके उन्हें आंचलिक ग्रामीण बैंकों के साथ जोड़ा जा चुका है।

XII. सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एसजीआरवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (नरेगा)

भारत सरकार ने सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना का सूत्रपाद, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की सुरक्षा आपूर्ति और पोषाहार स्तर में सुधार और स्थायी समुदाय का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक और वित्तीय सम्पत्तियों और बुनियादी संरचनाओं के विकास के मुख्य उद्देश्यों से किया।

इस योजना अंतर्गत लक्षित समूह वह सभी ग्रामीण गरीब हैं जिन्हें मजदूरी की आवश्यकता है और अपने गांवों/ निवास में आस–पास शारीरिक व अकुशल कार्य करने की इच्छा रखते है। मजदूरी प्रदान करने में गैर कृषिगत अप्रवीणतायुक्त मजदूरों, सीमान्त किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सदस्यों और बाल श्रमिकों जो जोखिमपूर्ण धन्धों में कार्यरत् है के माता–पिता, विकलांग बच्चों के माता–पिता अथवा विकलांग माता–पिता के जवान बच्चों जो मजदूरी करने की इच्छा रखते है, को प्राथमिकता दी जा रही है। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. इस परियोजना का क्रियान्वयन अप्रेल 2006 से कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना जैसे सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तगर्त आई.एफ.एफ.डी.सी. को मध्यप्रदेश के रायसेन, सिहोर, मंदसौर और नीमच जिलों में पंचवर्षीय परिदृश्य योजना निर्माण का कार्य सौंपा गया। ये योजनाऐं सर्वे व ग्रामीण सहभागी आंकलन (पी.आर.ए.) के निर्णयों के आधार पर विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम खण्ड व जिला के अधिकारियों की भागीदारी से तैयार किये गये।

मध्यप्रदेश राज्य में आई.एफ. एफ.डी.सी. द्वारा किये गये 1,873

एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा सांची, जिला रायसेन (म.प्र.) में आयोजित स्वयं सहायता समूह सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक दृश्य।

A view of SHG members training programme organised by IFFDC at Sanchi, Dist. Raisen (M.P.) under SGSY.

also been linked with Regional Rural Banks.

XII. SAMPOORNA GRAM ROJGAR YOJANA (SGRY) / NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE PROGRAMME (NREGA)

Govt of India has introduced the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) with main objectives to provide additional wage employment in all rural areas and thereby provide food security and improve nutritional levels for creation of durable community, social and economic assets and infrastructural development in to the rural areas.

Target group of this scheme are all rural poor who are in need of wage employment and desire to do manual and unskilled work in and around his village/habitat. While providing wage employment, preference is being given to agricultural wage earners, non-agricultural unskilled wage earners, marginal farmers, women, members of Schedule Castes/ Schedule Tribes and parents of child labour withdrawn from hazardous occupations, parents of handicapped children or adult children of handicapped parents who are desirous of working for wage employment. The Programme is being implemented through the Panchayati Raj Institutions (PRIs).

IFFDC is implementing this project since April 2006. IFFDC was assigned the task of preparation of five years perspective plans of Raisen, Sehore, Mandsore and Neemuch districts of MP under national rural development schemes viz. Sampoorna Gram Rojgar Yojana and National Rural Employment Guarantee Programme. These plans have been prepared based on the survey and findings of Participatory Rural Appraisals (PRA) by involving the officials at various levels i.e. village, block & district.

IFFDC submitted the five years

गांवों के गहन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार इन जिलों की पंचवर्षीय परिदृश्य योजनायें मध्य प्रदेश शासन को सम्बंधित जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। समूहों के गठन तथा उनके क्षमता निर्माण और दूसरी आजीविका अवधानों का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. को मन्दसौर और नीमच जिलों में नरेगा के अन्तर्गत जलग्रहण विकास परियोजना के लिए क्रियान्वयन सहयोगी एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।

जिला पंचायत मन्दसौर द्वारा भानपुर विकासखण्ड के 45 पंचायतों (100 गांव) प्रत्येक गांव में 25 गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए जलग्रहण विकास (कपिल धारा योजना के तहत), भू–जल संरक्षण उपायों (भूमि शिल्प योजना के तहत) और उद्यान विकास (नन्दन फलोद्यान के तहत) हेतु प्रदत्त सर्वे कार्य को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

perspective plans of Raisen, Sehore, Mandsaur and Neemuch districts of MP (based on the extensive surveys of 1873 villages) which have been approved by the state govt.. The work of SHG formation & their Capacity building and other livelihood interventions has also been started.

IFFDC has been appointed as partner Implementing agency for Watershed Development Project under NAREGA in Mandsaur and Neemuch dists.

Survey work assigned in Bhanpura block by Zila Panchayat, Mandsore for 45 panchayats (100 villages) covering 25 BPL families in each village for Water Resources Development (under Kapil Dhara Yojana), Soil & Water Conservation Measures (under Bhoomi Shilp Yojana) and Horticulture Development (under Nandan Falodhyan Yojana) was also completed successfully.

XIII. समग्र जलग्रहण विकास परियोजना, श्योपुर

आई.एफ.एफ.डी.सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत् श्योपुर जिले में भागीदारी संस्था के रूप में कार्यरत हैं तथा जलग्रहण विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतू इसे जिला ग्रहण कमेटी में एक सदस्य के बतौर नामित किया गया है।

जिले के 10 गांवों में जलग्रहण निर्माण व क्रियान्वयन हेतु 5000 हैक्टेयर क्षेत्र का आवंटन कर दिया गया है। पी.आर.ए. तथा ग्राम योजना निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 3909 हैक्टेयर क्षेत्र की नेट प्लानिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

XIII. INTEGRATED WATERSHED DEVELOPMENT PROJECT, SHEOPUR

IFFDC is working as Partner organization in Sheopur district under National Rural Employment Guarantee Scheme and nominated as a member in the District Watershed Committee to monitor and implement watershed developmental activities.

An area of 5000 ha has been allotted for formulation & implementation of Watershed in 10 villages in the district. PRAs and preparation of village plans have been completed. Net planning has been completed on 3909 ha. area.

समग्र जलग्रहण विकास परियोजना श्योपुर (म.प्र.) अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की बैठक में भाग लेती हुई महिला सदस्याऐं।

Women members participating in meeting of SHG formed under Integrated Watershed Development Project, Sheopur (M.P.).

XIV. समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा यह परियोजना इफको की सहायता से छिन्दवाड़ा जिले के छिन्दवाड़ा व मोहखेड़ा विकास खण्डों के 10 गांवों में समग्र कृषि व जल श्रोत विकास के माध्यम से ग्रामीण

XIV. INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT, CHHINDWARA

The project is being implemented by IFFDC in 10 villages of Chhindwara and Mohkhed blocks in Chhindwara district with support of IFFCO since Dec. 07 to enhance livelihood of the rural community

आई.एफ.एफ.डी.सी.–आई.आर.डी.पी. परियोजना, छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) का गांव बदनूर में भूमि पूजन से शुभारंभ।

Launching of IFFDC-IRDP Project by Bhoomi Poojan at Village Badnoor, Distt. Chindwara (M.P.).

आई.एफ.एफ.डी.सी. एवं इफको के अधिकारी समुदाय के साथ आई.आर.डी.पी. परियोजना छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के अन्तर्गत कुंआ जीर्णोद्धार स्थल का अवलोकन करते हुए।

IFFDC and IFFCO officials along with community observing the well renovation site in IRDP project, Chhindwara (M.P.).

समुदाय की आजीविका उत्थान हेतु दिसंबर, 2007 से क्रियान्वित की जा रही है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने कृषि प्रणाली तकनीकी तथा जल संसाधन विकास के क्षेत्र में अपनी बहुआयामी गतिविधियां प्रारम्भ की हैं। जिनके तहत सामाजिक गतिविधियों के साथ राजदा गांव में एक रिसाव टैंक, बदनूर एवं थुनिया उडना गांव में 2 टैंकों का गहरीकरण एवं मरम्मत का कार्य किया चुका है। गांव गुरिया और भैसाडॉड में 2 कूओं की मरम्मत का कार्य किया जा चुका है। कृषि प्रणाली विकास के तहत 95 कृषकों को सब्जियों के किट (फूलगोभी एवं टमाटर), मसाले (मिर्ची), दाल (मूंग) प्रदान किये, 4 कृषक गोष्ठियाँ, 2 फसल विचार गोष्ठियाँ, 1 पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। किसानों को 10 स्प्रिंगक्लर सिस्टम भी उपलब्ध कराये गये। मिट्टी जांच के नमूने (691) लिए जा चुके हैं तथा सन्तुलित उर्वरक प्रयोग अपनाने के लिए किसानों से स्वास्थ्य कार्ड के बारे में चर्चा की गयी।

सामाजिक विकास गतिविधियों के अन्तर्गत 7 समूहों का गठन तथा 4 समुदाय प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों का प्रभाव समुदाय पर परिलक्षित होना प्रारम्भ हो गया है कि वे परियोजना गतिविधियों में सहभागिता व योगदान करने हेतु आगे आ रहे हैं।

XV. इण्डस बाल श्रम परियोजना

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संस्था की सहायता से यह परियोजना दो वर्ष के लिए शुरू की थी जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस परियोजना का मुख्य अवधान जोखिम में फंसे बच्चों को पहचानना

through integrated agriculture and water resources developmental activities.

IFFDC started its multidimensional interventions in the area of Farming system technologies and development of water resources along with social activities under which a percolation tank in village Razada, 2 Tank deepening & renovation in the villages of Badnoor & Thunia udna, 2 Well renovations in village Guriya and Bhaisa Dand has been completed. Under Farming System development, 95 farmers provided with kits for vegetable (cauliflower, tomato), spices (chilies) and pulses (moong), 4 farmers meeting, 2 crop seminar, 1 vet. Camp has been organized. 10 sprinkler system has been also provided to the farmers. Soil testing samples (691) have been taken and health card has been discussed with farmers for adoption of balance fertilization.

Under Social Development activities, 7 SHGs have been formed and 4 Community Trainings have been organized. As impact of the activities, community is now coming forward for participation and contribution in the project activities.

XV. INDUS CHILD LABOUR PROJECT

IFFDC has successfully implemented this project in district Sagar (MP) supported by International Labour Organization (ILO) for two years. The main interventions of this project were Identification of the children at risks and provision of transitional education to children in the age group of 9-13 years;

तथा 9–13 वर्ष की आयु के बच्चों को सेतु शिक्षा उपलब्ध कराना; 14–17 वर्ष की आयु के किशोरों का व्यवसाय जनित कराना; बाल मजदूर परिवार को वैकल्पिक आय अर्जित कराना; सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत कराना; लाभान्वितों तथा मजदूरों की बदलती दशा का अनुश्रवण करना, सामाजिक लामबन्धन तथा बाल मजदूरी रोकने के प्रति जागरूकता लाना तथा सरकारी संस्थाओं और समाज संस्थाओं की भागीदारी में बाल मजदूरी पर प्रशिक्षण देना व क्षमता निर्माण करना है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने सेतु शिक्षा केन्द्रों के कार्यक्रम के अर्न्तगत 2 विद्यालय बरकोटी खुर्द तथा सहजपुर, जिला सागर में खोले। इन केन्द्रों में 146 पढ़ाई छोड़ चुके तथा बीडी उद्योग में कार्यरत 9–13 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई जिनमें से 131 बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने ऐसे दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहेरिया तथा देवरी प्रत्येक में एक खोले गये। इन केन्द्रों में 100 बाल श्रमिकों (50 बहेरिया तथा 50 देवरी में) को बहेरिया में दो पहिया वाहन मरम्मत तथा देवरी में लोहे की जालियाँ निर्माण पर प्रशिक्षण दिये गए। इन 100 बच्चों में से 58 को जिस व्यवसाय में प्रशिक्षित किया गया है उससे नियमित रोजगार पाने की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

आई.एल.ओ. मूल्यांकन मिशन ने सितम्बर 2007 में कार्यक्रम का अवलोकन किया, इसकी उलपब्धियों की भरपूर सराहना की तथा बाल श्रमिकों के बच्चों के अभिभावकों को गतिशील कर समूहों में संगठित करने हेतु फेज–II की स्वीकृति प्रदान की। इन समूहों को उनके आर्थिक विकास हेतू आय अर्जन गतिविधियों से जोड़ा जाना है। परियोजना क्षेत्र में ऐसे 25 समूहों का गठन किया जा चुका है। इन समूहों के लिए उत्प्रेरण एवं नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए गये।

अब इण्डस परियोजना एन.सी.एल.पी. में परिवर्तित हो रही हैं आई.एफ.एफ.डी.सी. का जिले में एन.सी.एल.पी. विद्यालय संचालन हेतू बतौर भागीदार चयन कर लिया गया है।

डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी., डॉ. एस.सी. वर्मा, निदेशक, इण्डस परियोजना, सागर (म.प्र.) के साथ सेतू शिक्षा केन्द्र बरकोटी खुर्द, जिला सागर (म.प्र.) में अध्ययनरत् बाल श्रमिकों को गणवेश वितरित करते हुए।

Dr P.S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC, alongwith Dr. S.C. Verma, Director, INDUS Project, Sagar (M.P.) distributing uniforms to the Child labours studying in IFFDC-Transitional Education Center, Berkoti Khurd, dist Sagar (MP).

Vocation generating for adolescent in the age group of 14-17 years; Income generating alternatives for families of child labour; Strengthening public education; Monitoring and tracking the beneficiaries and the changing labour situation; Social mobilization and awareness raising on the child labour and capacity building and training in partnership with government agencies and civil society partner on child labour.

Under Transitional Education Center (TECs) of this programme, IFFDC established 2 schools one each at Barkoti Khurd and Sahajpur district Sagar. In these centres 146 dropout students and those working in bidi industry between the age group of 9-13 years are being provided elementary education. 131 children have been mainstreamed in the education for higher study.

IFFDC has also established two such vocational training centers one each at Baheriya and Deory in Sagar district (MP). In these centers, trainings were imparted to 100 children (50 in Baheriya and 50 in Deory) on two wheeler repairing at Baheriya and iron fabrication at Deory. Out of these 100 children, 58 have been mainstreamed for regular employment through the trade in which they were trained.

ILO Evaluation Mission visited the programme in Sept 2007 and highly appreciated its achievements and accorded approval for Phase – II to mobilise and organize the parents of such child labours in to SHGs. These SHGs are to be linked with income generating activities for their economic development. 25 such SHGs have been formed in the project area. 2 Capacity building programmes on motivation & leadership development of these SHG have been conducted.

Now the INDUS Project is being converted into NCLP and IFFDC has been selected as partner for running NCLP schools in the district.

XVI. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.), रतलाम

जिला रतलाम में बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतू जिला श्रम विभाग के माध्यम से आई.एल.ओ. की वित्तिय सहायता से ये परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। एन.सी.एल.पी. ने सितम्बर 2007 से एक वर्ष के लिए जिला रतलाम में 2 विद्यालयों (पिपलोदा व सरवन) के माध्यम से 100 बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किया है। उक्त विद्यालयों से शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के 100 बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकन के माध्यम से पहले ही शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है।

XVII. करैया–सुरखी जल ग्रहण विकास परियोजना (म.प्र.)

आई.एफ.एफ.डी.सी. को नाबार्ड द्वारा इसकी ''जलग्रहण विकास निधि'' के तहत् जिला सागर (म.प्र.) में यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की गयी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबन्धन के लिए ग्रामीण समुदाय की ग्रामस्तरीय चिरन्तरित संस्थाओं जैसे :– जल उपयोग कमैटी (डब्ल्यू.यू.सी.) आदि को स्थापित कर ग्रामीण समुदाय की क्षमता निर्माण करना; परियोजना चक्र की सभी अवस्थाओं व पहुँचों में लिंग समानता सुनिश्चित करना; जलग्रहण विकास व प्रबन्धन के विशिष्ट उद्देश्यों में एक जलग्रहण क्षेत्र उपलब्ध सभी स्त्रोतों का प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम हानि के साथ उचित उत्पादन के लिए समुचित उपयोग; कुशल व निरन्तर उत्पादन के लिए जल बहाव हानि नियन्त्रण, सुरक्षा, संरक्षण एवं भू स्त्रोतों का सुधार करना; निम्न धारा क्षेत्रों में बाढ़ को कम करना। जल स्त्रोतों की सुरक्षा व उत्थान, तालाबों के गाद भराव में कमी व वर्षा जल संरक्षण; जल संग्रहण संरचनाओं व अन्तः क्षेत्र संरक्षण उपायों द्वारा भूमिगत जल के पुर्नःभरण में वृद्धि; उन्नत कृषि व सम्बन्धित धन्धों के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

XVI. NATIONAL CHILD LABOUR PROJECT (NCLP), RATLAM

The project is being implemented with financial assistance of ILO through District Labour Department for mainstreaming the child labour into regular education. NCLP provided grant-in-aid for the literacy of 100 child labourers through 2 schools (Piploda and Sarwan) in Ratlam district for one year from Sept 2007. 100 Students (age group of 6-14 years) have already been mainstreamed through enrollment in Govt. schools after completing education from above schools.

XVII. KARAIYA-SURKHI WATERSHED PROJECT (MP)

IFFDC has been awarded this watershed Project by NABARD Bhopal under its Watershed Development Fund for 3 years in district Sagar (MP). The main objectives of the project are to build the capacity of rural community by establishing sustainable village level institutions like Water User Committee (WUC) etc.; ensure gender equity in all approaches and stages of project cycle; The specific objectives of the watershed development and management are proper use of all the available resources of a watershed for optimum production with minimum hazards to natural resources; to control damaging run-off, protect, conserve and improve the land resources for efficient and sustained production; to moderate flood in the down-stream area; to protect and enhance water resources, reduce silting of tanks and conserve rain water; to increase the ground water recharge through in-situ conservation measures and water harvesting structures; to utilize the

डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी., व श्री सुधीर सुले, डी.डी.एम. नाबार्ड संयुक्त रूप से नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित आई.डब्ल्यू.डी.पी. अन्तर्गत भूमि कार्य प्रारम्भ कर मृदा–जल संरक्षण उपायों का उद्घाटन करते हुए

Dr P. S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC and Sh. Sudhir Sule DDM, NABARD jointly inaugurating the Soil & Water Conservation measures by initiating the earth work under NABARD funded IWDP at Karaiya, dist Sagar (MP)

जिससे समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा चिरन्तर ग्रामीण आजीविका विकास हेतु कई प्राकृतिक उत्पादों का जो किसी एक विशिष्ट जलग्रहण से प्राप्ती योग्य उसी क्षेत्र में कई सामग्री व सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता हो रही हैं का समवर्ती व संचेतन उपयोग करना है।

अप्रेल 2006 से प्रारम्भ परियोजना का पूर्व क्षमता निर्माण चरण में क्षमता निर्माण चरण की नेट–प्लानिंग फरवरी 2007 में पूर्ण हो गयी जिसे नाबार्ड भोपाल (म.प्र.) ने स्वीकृत कर दिया है। परियोजना के पूर्व क्षमता निर्माण चरण की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है :

1 जल उपयोग कमेटी का 11 सदस्यों के साथ गठन किया गया, 8 जल उपयोग कमेटी की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें 86 सदस्यों ने भाग लिया। 47 सदस्यों के लिए 2 एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन किया गया तथा 80 किसानों के लिए रवी फसल पर 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

74 हेक्टे. की नेट प्लानिंग पूर्ण की जा चुकी है, 56.43 घन मीटर स्टेगर्ड ट्रेन्च, 50.56 घन मीटर कन्टूर ट्रेंच, 58.59 घन मीटर लूज स्टोन मेडबंदी बनाये जा चुके हैं।

यह जलग्रणह परियोजना राज्य स्तर पर प्रथम (उत्कृष्ट) आंकी गयी जिसके के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. सागर को नाबार्ड, भोपाल ने पुरुष्कृत किया तथा माननीय श्री राघव जी, वित्त मन्त्री, म.प्र. सरकार द्वारा भोपाल में ट्राफी प्रदान की गयी।

नाबार्ड के अधिकारीगण करैया–सुरखी जलग्रहण विकास परियोजना क्षेत्र में निर्मित पत्थर की मैड़बन्दी का अवलोकन करते हुए।

NABARD officials observing stone bunding constructed in Karaiya-Surkhi Watershed Development Project Area.

माननीय श्री राघवजी, वित्त मंत्री, म.प्र. सरकार से सुश्री किरण दुबे, वरि. प्रसारक, आई.एफ.एफ.डी.सी., सागर राज्य स्तरीय प्रथम पुरुस्कार प्राप्त करते हुए।

Ms. Kiran Dubey, Sr. Community Organiser, IFFDC, Sagar receiving State level First Prize from Hon'ble Sh. Raghav Ji, Finance Minister Govt. of M.P.

natural local resources for improving agriculture and allied occupation so as to improve the socio-economic condition of the community and Concurrent and conscious use of several natural resource products obtainable on a particular watershed requiring the production of several goods & services from the same area for sustainable rural livelihood development.

Pre Capacity Building Phase of the project alongwith net planning for Capacity Building Phase which was started in April 2006 was completed in February 2007 has been sanctioned by the NABARD Bhopal (MP). Salient achievements of the pre capacity building phase of the project are as under:

One Water User Committee has been formed with 11 members; 8 meetings of Water User Committee were organized which was participated by 86 members; 2 exposure visit were organized participated by 47 persons and 1 training of farmers was organized on Rabi crops benefitting 80 persons.

Net planning of 74 ha. has been completed, 56.43 Meter^3 Staggered Trench, 50.56 Meter^3 Contour Trench, 58.59 Meter^3 Loose Stone Check Dam have been formed.

This Watershed project ranked first (excellent) in the state of M.P for which IFFDC, Sagar has been awarded by NABARD Bhopal and the trophy was given by Sh Raghavji Hon'ble finance minister Govt. of M.P. at Bhopal.

XVIII. समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना, छत्तरपुर (म.प्र.)

आई.एफ.एफ.डी.सी. को राज्य सरकार ने ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत जिला छत्तरपुर, (म.प्र.) में समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु अग्रणी संस्था के रूप में चयनित किया है। गांव बिच्छौन, खण्ड–लौडी, जिला–छत्तरपुर (म.प्र) में 5 वर्षों की अवधि (जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2012) के लिए 2700 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गयी है। हाल ही में, आई.एफ.एफ.डी.सी. गोरीहार खण्ड, जिला–छत्तरपुर (म.प्र.) में जलग्रहण विकास हेतु अतिरिक्त 5000 हैक्टेयर भूमि का भी आवंटन किया गया है। इस परियोजना के मुख्य उदेश्य परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को एक वित्तिय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सृजित करना; जलग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्धन; जल बहाव हानि का नियन्त्रण; समुचित व चिरन्तर उत्पादन हेतु भू व जल स्त्रोतों की सुरक्षा संरक्षण व सुधार; सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु समुदाय की क्षमता निर्माण; परियोजना चक्र के सभी चरणों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चत करना तथा चारागाह विकास व जेट्रोफा वृक्षारोपण करना है। परियोजना की विकासात्मक गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:–

12 परियोजना परिचयात्मक बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 1265 सदस्यों ने भाग लिया, 18 जल उपयोग कमेटियों तथा 5 जल ग्रहण प्रबंधन कमेटियों का गठन क्रमशः 165 और 45 सदस्यों के साथ किया गया।

परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत गांव बिच्छौन, जिला छत्तरपुर (म.प्र.) में लगाये गये जैट्रोफा वृक्षारोपण का एक दृश्य।

A view of Jatropha plantation in Project village Bichhon, Dist. Chhattarpur (M.P.).

बिच्छौन जलग्रहण विकास समिति (जिला छत्तरपुर) के सदस्य एक्सपोजर भ्रमण के दौरान श्री एन.के. नगायच, निदेशक आई.एफ.एफ.डी.सी. के साथ करैया वानिकी समिति, जिला सागर (म.प्र.) के वृक्षारोपण क्षेत्र का अवलोकन करते हुऐ।

Members of Bichhon Watershed Development Committee (Dist. Chhattarpur) along with Sh. N.K. Nagayaich, Director, IFFDC observing plantation area of Karaiya PFFCS, Dist. Sagar (M.P.) during exposure visit

XVIII. INTEGRATED WATERSHED DEVELOPMENT PROJECT, CHHATTARPUR (MP)

IFFDC has been selected as lead agency in Chhattarpur district. by State Govt. to implement and monitor this project under "National Rural Employment Guarantee' Scheme. 2700 ha area has been allotted in village Bichhon, Block Lori, dist Chhattarpur (MP) for implementation of the project for 5 years duration (January 2007 to December 2012) as per prevailing watershed guidelines of MP Govt. Additional 5000 ha area for watershed development has also been allotted recently in Gorihar block of Chhatarpur to IFFDC. The objectives of the project are to generate 100 days employment in a financial year to each of the BPL family of the project area; to manage properly the available natural resources of the watershed area; to control damaging run-off, protect, conserve and improve the land and water resources for efficient and sustained production; to improve land for efficient and sustainable production; to build capacity of the community for socio-economic development; to ensure women participation at all the staged of the project cycle and to develop pasture and jatropha plantation. The progress of the project activities are given as follows:

12 Project Introductory Meetings were organized which was participated by 1265 members, 18 Water User Committees and 5 Watershed Management Committees have been formed with 165 and 45 members respectively.

Net planning of 6700 ha has been completed,

छत्तरपुर जिले में 6700 हेक्ट. की नेट प्लानिंग पूर्ण की जा चुकी है, 14 परियोजना गांवों का पी.आर.ए. तथा 29 गांवों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है।

संग्रहित जल से फसल उगाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त बुवाई के अन्तर्गत आने वाले नियत्रित क्षेत्र में वानिकी व जेट्रोफा प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा।

समुदाय लामबन्दी व सम्बन्ध निर्माण सम्बन्धी प्रवेश बिन्दु गतिविधि प्रगति पर है। भूमि आधारित भौतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है।

XIX. नाबार्ड–जलग्रहण विकास परियोजना, छत्तीसगढ़

नाबार्ड रायपुर द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. को जिला कवर्धा में 3 वर्षो (जनवरी, 2007 से मार्च, 2010) की अवधि की 3 जलग्रहण विकास परियोजनाऐं (कुई, कुकदर व खुरुभाटा) प्रदान की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का प्राकृतिक स्त्रोतों को न्यूनतम नुकसान के साथ अधिकतम उत्पादन के लिए समुचित उपयोग करना है। कुशल व निरन्तर उत्पादन के लिए जल बहाव हानि नियन्त्रण, सुरक्षा, संरक्षण एवं भू स्त्रोतों का सुधार करना; निम्न धारा क्षेत्रों में बाढ़ को कम करना। जल स्त्रोतों की सुरक्षा व उत्थान, तालाबों के गाद भराव में कमी व वर्षा जल संरक्षण; जल संग्रहण संरचनाओं व अन्तः क्षेत्र संरक्षण उपायों द्वारा भूमिगत जल के पुर्नःभरण में वृद्धि; उन्नत कृषि व सम्बन्धित धन्धों के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग चिरन्तर ग्रामीण आजीविका विकास हेतु करना है।

परियोजना की पूर्व क्षमता निर्माण चरण के साथ क्षमता निर्माण चरण (सी.बी.पी.) हेतू नेट प्लानिंग को पूर्ण किया गया जिसे नाबार्ड रायपुर द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

PRA in 14 project villages and Survey in 29 villages of dist Chhattarpur have been completed.

It is proposed to grow crops with the harvested water. In addition plantation of forestry and jatropha species shall also be undertaken in the command area to be brought under cultivation.

The entry point activities related to community mobilization and rapport building are under progress. Land based physical activities have been started.

XIX. NABARD-WATERSHED DEVELOPMENT PROJECT, CHHATTISGARH

IFFDC has been sanctioned 3 Watershed Development Projects ie at Kui, Kukdar and Khurubhata in dist Kawardha (Chhatisgarh) by NABARD, Raipur under its Watershed Development Fund for 3 years. The main objectives of the project are the proper use of all the available resources of a watershed for optimum production with minimum hazards to natural resources; Concurrent and conscious use of several natural resource products obtainable on a particular watershed requiring the production of several goods and services from the same area for sustainable rural livelihood development.

Pre Capacity Building Phase of the project alongwith net planning for Capacity Building Phase (CBP) was completed which has been sanctioned by the NABARD Raipur.

कुई जल ग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की बैठक का एक दृश्य।
A view of meeting of SHG formed under Kui Watershed Development Project.

कुकदर जल ग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत गठित जलग्रहण समिति की बैठक का एक दृश्य।
A view of meeting of Watershed committee formed under Kukdar Watershed Development Project.

सी.बी.पी. के क्रियान्वयन के दौरान, जलग्रहण विकास समितियों का गठन किया गया तथा समुदाय की क्षमता निर्माण हेतु 86 सदस्यों की भागीदारी से 3 एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन किया गया। 81 हैक्टेयर में मेडबंदी की गयी जिस पर 45 किग्रा. उन्नत किस्म की घास की बुवाई की गयी। 564 फलदार पौधे भी लगाये गये।

During implementation of CBP, 3 Watershed Development Committees have been formed and 3 exposure visits with 86 members were organised for capacity building community. Construction of farm bunding on 81 ha. have been completed on which 45 kgs. grass seed of improved variety has been sawen, 564 fruit saplints have also been planted.

XX. नाबार्ड वाडी परियोजना, कवर्धा (छ.ग.)

आई.एफ.एफ.डी.सी. को नाबार्ड ने इसकी आदिवासी विकास निधि (टी.डी.एफ.) के अन्तर्गत वाडी (लघु उद्यान) परियोजना कवर्धा (छत्तीसगढ) में पडरिया विकास खण्ड के आदिवासी प्रभावित 25 गावों के 1000 आदिवासी परिवारों के लिए क्रियान्वयन हेतु रू. 339 लाख की वित्तिय सहायता व 7 वर्षों की अवधि के साथ स्वीकृत कर दी गयी है। परियोजना की पहुँचें व घटक नाबार्ड वाडी परियोजना – प्रतापगढ़ (राज.) में उल्लेखित अनुसार ही है।

आदिवासी परिवारों का सर्वेक्षण तथा सहभागी परिवारों से सहमति पत्र प्राप्त करने जैसी गतिविधियाँ पूर्ण कर ली गयी है।

आई.एफ.एफ.डी.सी.–वाडी परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत अपने खेत पर फलदार पौध रोपित करता हुआ एक आदिवासी परिवार।

A Tribal Family planting fruit sapling on its own field under IFFDC-Wadi project.

XX. NABARD-WADI PROJECT, KAWARDHA (CHHATTISGARH)

The **"wadi"** (small orchard) project is being implemented by IFFDC in tribal dominant 25 villages of Pandariya block in Kawardha (Chhattisgarh) covering 1000 Scheduled Tribes (ST) families for 7 years duration with financial assistance NABARD under its Tribal Development Fund (TDF). The approaches and components of the project are as per the concept and guidelines as discussed in the wadi project in Pratapgarh district in Rajasthan.

Survey and selection of the ST families have been completed.

XXI. सहकारी विकास के माध्यम से आजीविका सुधार (लिस्ड) परियोजना

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने पांच 'ज' (विकास के पंचआयामी घटकों) जल, जंगल, जमीन, जानवर व जन की सहभागी दृष्टिकोणों, जांची परखी विधियों और तकनीकियों पर आधारित इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड के पाँच जिलों चायबासा, गूमला, पलामू, हजारी बाग और दुमका में तीन वर्षों के लिए गतिविधियां प्रारम्भ की हैं। यह परियोजना 50 गांवों (उक्त प्रत्येक जिले के 10 गांवों) में क्रियान्वित की जा रही है। पाँचों जिलों के गाँवों में 50 ग्राम स्तरीय (प्रत्येक गांव में एक) ''प्राथमिक आजीविका विकास स्वायत्त सहकारी समितियों'' का संवर्द्धन किया गया। परियोजना की लागत झारखण्ड सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समितियों (पी.एल.डी.ए.सी.एस.) के माध्यम से प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

XXI. LIVELIHOOD IMPROVEMENT THROUGH COOPERATIVE DEVELOPMENT (LICD) PROJECT

IFFDC has started its activities to implement this Project in 5 districts of Jharkhand viz: Chaibasa, Gumla, Plamu, Hazaribag and Dumka based on the participatory approaches and tested methodologies and technologies on pentagonal components of development (Jal, Jangal, Jameen, Janwar and Jan) for three years. The project is being implemented in 50 villages i.e. 10 each in above five districts. A total of 50 village level Primary Livelihood Development Autonomous Cooperative Society (PLDACS) (one in each village) have been promoted. The project is to be supported by Govt. of Jharkhand under it's various development schemes through the village level cooperatives.

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा प्रारम्भ की गयी मुख्य गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है :–

41 समूहों का गठन 483 सदस्यों के साथ (128 पुरुष, 355 महिलाऐं) किया गया तथा 50 पी.एल.डी.ए.सी.एस. का गठन 1170 सदस्यों (817 पुरुष, 353 महिलाऐं) के साथ किया गया।

पी.एल.डी.ए.सी.एस. की कार्यकारिणी कमेटियों की 64 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 646 सदस्यों ने भाग लिया तथा परियोजना क्षेत्र के 50 गांवों का सहभागी ग्रामीण आंकलन सम्पन्न किया गया।

सदस्यों तथा समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने और समिति की अवधारणा की जानकारी प्रदान करने हेतु समितियों की कार्यकारिणी कमेंटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। नये समूहों के गठन और विद्यमान समूहों के क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्षों में आजीविका विकास की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. वार्षिक योजना तैयार करने के लिए पंजीकृत समितियों को सहायता प्रदान कर रही है। नाबार्ड तथा झारखण्ड सरकार के सहकारिता विभाग की सहायता से आजीविका अर्जित करने के अवधानों के लिए प्रयास आरम्भ किए गये हैं।

लिस्ड परियोजना, झारखण्ड में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह सदस्यों की बैठक का दृश्य।

View of meeting of members of SHGs formed by IFFDC under LICD Project Jhakhand.

Details of the major activities started by IFFDC are given below:

41 SHGs have been formed with total membership of 483 (Male – 128, Female – 355) and 50 PLDACS have been formed with total membership of 1170 (Male – 817, Female – 353).

64 Meetings of PLDACS Executive Committees were organized which was participated by 646 members and PRA in 50 villages of project area has been completed.

Regular meetings of the executive committees are being organised to create awareness and sharing the concept of PLDACS amongst the members. Formation of new SHGs and capacity building of the existing SHGs are under progress. IFFDC is facilitating the registered PLDACS for preparation of their annual plans for undertaking livelihood development activities in the coming years. Efforts are being made to start various interventions for livelihood enhancements with the support of NABARD and Dept. of Corporation Govt. of Jharkhand.

XXII. औषधीय पौधों की खेती, वृक्षारोपण एवं सामाजिक विकास के माध्यम से आजीविका सुधार'' (लिम्कास)

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन जिला सरगुजा में आई.सी.पी.एल. परियोजना प्रेमनगर के निकट 4 वर्षों (अप्रेल, 2007 से मार्च, 2011) के लिए इफको–छत्तीसगढ़ पावर लि. (आई.सी.पी.एल.) की सहायता से क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के पुर्नवास हेतु किया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण सम्बन्धित मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतू अम्बीकापुर में पुर्नवास कमेटी की बैठक आयोजित की जा चुकी है। इस बैठक में डॉ. कृष्णामूर्ति बांधी, स्वास्थ्य मन्त्री; श्रीमती रेणुका सिंह, विधायिका, प्रेमनगर; श्री एम.के. पिंगवा, जिलाधीश; सी.ई.ओ., आई.सी.पी.एल, परियोजना अधिशाषी, आई.एफ.एफ.डी.सी. तथा जिला पंचायत अध्यक्ष सहित प्रभावित गांवों के सरपंचों ने भाग लिया।

XXII. LIVELIHOOD IMPROVEMENT THROUGH CULTIVATION OF MEDICINAL PLANTS, AFFORESTATION AND SOCIAL DEVELOPMENT (LIMCAS)

IFFDC is implementing this project near ICPL Project Premnagar, dist Sarguja for 4 years (April 07 to March 11) with financial assistance of ICPL to rehabilite the affected families of the area.

Meeting of the Rehablitatiion Committee has been held at Ambikapur to discuss the issues related to the land acquisition. In this meeting, Dr. Krishnamurti Bandhi Health Minister; Ms Renuka Singh MLA.Premnagar; Sh M.K. Pingwa District Collector; CEO, ICPL; Project Executive, IFFDC; and Chairman Zila Panchayat along with Sarpanchs of the affected villages participated.

समुदाय लामबन्दी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

21 स्वयं सहायता समूह 231 सदस्यता के साथ गठित किये गये तथा समह सदस्यों को उत्प्रेरण व समूह प्रबन्धन पर 5 प्रशिक्षण प्रदान किये जा चुके हैं।

समूहों को सामग्री जैसे दरी, कैश बाक्स आदि प्रदान कर दिये गये हैं।

1 पशु चिकित्सालय एवं 3 सामुदायिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया गया।

श्री रविन्दर प्रताप सिंह, निदेशक, इफको लिम्कास परियोजना जिला सरगुजा (छ.ग.) में एक्सपोजर भ्रमण व प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान टपरकेला में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सम्बोधित करते हुए।

Sh. Ravinder Pratap Singh, Director, IFFCO addressing SHG members from LIMCAS project at Taparkela, Distt. Sarguja (C.G.) during Exposure Visit cum Training Programme.

Community mobilisation work has been initiated.

21 SHGs with membership base of 231 have been formed and 5 trainings on motivation and SHG management have been imparted to the SHGs members.

The SHGs have been provided items like carpets, cash boxes etc.

1 Veterinary and 3 Community Health Checkup Camps have been organised.

बाल दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर 4 दिवस समारोह मनाये गये।

रघुनाथपुर में एक सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया गया जिसमें 15 महिलाओं को वस्त्र सिलाई पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण के लिए राजस्व एवं वन विभाग से नियमित अनुसरण किया जा रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी, जे.एफ.एम. तथा राज्य वन विकास अभिकरण के मध्य एम.ओ.यू. के मसौदे को राज्य वन विभाग, अम्बीकापुर द्वारा अन्तिम रूप देकर स्वीकृति हेतू प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को प्रेषित कर दिया गया है।

श्री गिरीश अग्रवाल, पी.सी.सी. एवं सी.ई.ओ. औषधीय पौध, बोर्ड रायपुर के साथ एक बैठक आयोजित की जाकर भूमि अधिग्रहण तथा औशधीय पौधों की खेती आदि को तय किये जाने हेतू विचार–विमर्श किया गया।

2000 हैक्टेयर पर वक्षारोपण करने हेतू प्रेमनगर के आस–पास 31 जे.एफ.एम. की पहचान कर ली गयी है।

छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव, अम्बिकापुर में आई.एफ.एफ.डी.सी. प्रदर्शनी स्टाल पर लिम्कास परियोजना, प्रेमनगर से आये स्वयं सहायता समूहों के सदस्य

Group of women SHG Members from LIMCAS Project, Premnagar at IFFDC exhibition stall in “Chhattisgarh Rajyomahotsava” at Ambikapur (C.G.)

4 special Days on the occasion of Children Day and Indepedence Day have been celebrated.

One Tailoring Center at Raghunathpur has been started in which 15 women are being imparted training on sewing of cloths.

Regular follow-up is being made with Revenue and Fortest departments for land acquisition.

Draft MoU amongst IFFDC, JFM and State Forest Development Authority has been finalised by State Forest Department, Ambikapur which has been recently recommended to PCCF, Raipur for seeking its approval.

A Meeting with Mr Shirish Agrawal, PCCF and CEO Medicinal Plant Board, Raipur has also been organised to discuss and finalise the land acquisition and cultivation of medicinal plants etc.

31 JFMs near Premnagar have been identified for land acquisition to undertake plantation on 2000 ha.

रघुनाथपुर व नमना गांवों में 4 आटा चक्कियाँ एवं 80 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयाँ स्थापित की गयी।

टपरकेला (इफको ग्राम) से समूह सदस्यों के प्रेमनगर एवं विपर्ययेण में एक्सपोजर भ्रमण आयोजित किये गये जिनका उद्घाट्न जिलाधीश, सरगुजा द्वारा किया गया।

XXIII. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना, (आर.एल.डी.पी.) पश्चिमी बंगाल

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने विकास के पंचआयामी घटकों की सहभागी दृष्टिकोणों, जांची परखी विधियों और तकनीकियों पर आधारित यह परियोजना पश्चिमी बंगाल राज्य के हुगली जिले में दिसम्बर 2006 से मार्च 2008 की अवधि के लिए आरम्भ की है। यह परियोजना तीन गांवों पुर्वाहोली, कुल्ताघोड़ी और मुल्क में इफको की वित्तिय सहायता से क्रियान्वित की जा रही है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों का गठन, और उनका समितियों में संघीकरण, सरकार, पंचायत और वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क, उचित कृषि प्रणाली और तकनीकी का सभी तीनों गांवों में आवश्यकता आधारित आय जनित गतिविधियों का विकास, स्वयं सहायता समूहों का क्षमता विकास और जेंडर मुख्य धारा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण।

आयोजित मुख्य गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

संस्थागत विकास

परियोजना के प्रारम्भ से पहले समिति (सम्बया कृषि उन्नयन समिति) द्वारा अपने ही मॉडल पर आधारित कई स्वयं सहायता समूह चलाये जा रहे थे। इस परियोजना की मुख्य चुनौति विद्यमान समूह के साथ उनकी प्रणाली में विघ्न डाले बिना आई.एफ.एफ.डी.सी. को अपने मॉडल को शुरू और स्थापित करने की थी। समुदाय से विचार विमर्श से समूह विचार धारा से सम्बन्धित जागरूकता के प्रसार में मदद मिली। विद्यमान समूह के सदस्यों ने परियोजना का हिस्सा बनने में रुचि प्रदर्शित की।

4 Flour Mills and 80 vermicompost units have been established in Raghunathpur and Namana Villages.

Exposure visit of SHG members from Taparkela (IFFCO village) to Premnagar and vise-a-versa have been organised which was inagurated by the Collector, Sarguja.

XXIII. RURAL LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT (RLDP), WEST BENGAL

IFFDC has started its activities to implement this project in Hooghly district of West Bengal based on its participatory approaches and tested methodologies and technologies on pentagonal components of development during Dec. 2006. The project is being implemented in three villages i.e. Poorvahoulli, Kultaghori and Mulk with the support of IFFCO.

Main objectives of the project are formation and federation of SHGs into cooperative societies, linkages with Govt., Panchayati Raj & Financial Institutions; adoption of appropriate farming systems and technologies in all the three villages; developing need based income generation activities, capacity building of SHGs and women empowerment through mainstreaming gender.

Details of the important component wise activities conducted are given below:

Institutional Development

Before the initiation of the project, there were several Self Help Groups in the project area which were being run by the societies (Sambyay Krishi Unnayan Samiti) based on its own model. The main challenge of the project was to work with existing SHGs without disturbing their system as well as to cerate and establish the ongoing model of IFFDC. Interaction with the community helped to disseminate the awareness regarding SHGs concept. Members of already existing SHGs were interested to be part of the RLDP.

डॉ. डी.पी. पात्रा, संयुक्त महा प्रबंधक (विपणन), इफको, कोलकाता, स्वयं सहायता समूह प्रबन्धन पर प्रशिक्षण के दौरान तारकेश्वर जिला हुगली (पश्चिमी बंगाल) में समूह सदस्यों के साथ।

Dr. D.P. Patra, Joint General Manager(Mktg.), IFFCO, Kolkata with SHGs Members during training on "SHG Management" at Tarkeshwar, Dist. Hoogaly (West Bengal).

560 सहभागियों (380 महिलाएं और 180 पुरुष) के साथ 8 ग्राम स्तरीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

679 सदस्यता (642 महिलाएं और 37 पुरुष) के साथ 47 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है।

क्षमता विकास

समूहों हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समूह प्रबन्धन, जेंडर संवेदनशीलता और लघु उद्योग विकास पर क्षमता निर्माण के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 पुर्वाहोली, 3 कुल्ताघोड़ी और 3 मुल्क) आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे 360 सदस्य लाभान्वित हुए।

हैण्डपंप लगाना

परियोजना क्षेत्र में पीने के पानी की अत्यधिक समस्या है। इस समस्या से निजात पाने हेतु स्वच्छ जल प्रदान करने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए 5 हैण्ड पम्प (1 पुर्वाहोली, 2 कुल्ताघोड़ी और 2 मुल्क) लगाये गए जिससे 163 परिवारों (35 पुर्वाहोली, 85 कुल्ताघोड़ी और 43 मुल्क) को लाभ पहुंचा।

पशुधन विकास

किसान को अपने मवेशियों से बहुत लगाव होता है जाकि उससे पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता है। 9 पशु शिविर 4 हुगली जिला में तथा 5 बाकुरा जिले में आयोजित किए गये हैं जिनमें 4292 पशुओं का (2481 हुगली जिले में तथा 1811 बाकुरा जिले में) उपचार किया गया।

पशु पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक स्वयं सहायता समूह सदस्य लाभान्वित हुए, जिनको 129 बकरियां (64 हुगली जिले में तथा 75 बाकुरा जिलें में) तथा 13 बकरे (7 हुगली जिले में तथा 6 बाकुरा जिलें में) प्रदान किए गये हैं।

उन्नत कृषि पद्धतियां

92 कम्पोस्ट गड्ढ़े (52 पूर्वाहोली, 27 कुल्ताघोड़ी तथा 13 मुल्क में) तैयार किये गए हैं जिससे सम्बन्धित 92 सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

8 Village meetings involving 560 participants (380 female and 180 male) were organized.

47 SHGs have been formed with a total membership of 679 (642 female and 37 male).

Capacity Building

8 training programmes (2 in Poorvahoulli, 3 in Kultaghori and 3 in Mulk) have been organized for building the capacity of SHGs on important aspects like SHG management, gender sensitization and micro enterprises development which have benefited 360 members.

परियोजना गांव भाँजीपुर (पश्चिमी बंगाल) में लगाये गये हैण्डपंप के उद्घाटन का दृश्य।

View of inauguration of Hand-pump installed in project village Bhanjipur (West Bengal).

Installation of Hand Pumps

The project area have acute problem of drinking water. To overcome this problem 5 hand pumps (1 in Purbahaulli, 2 in Kultaghari and 2 in Mulluk village) have been installed benefiting 163 households (35 in Purbahaulli, 85 in Kultaghari and 43 in Mulluk) by providing safe water for drinking and other domestic purposes.

Animal Husbandry Development

The farmer holds a strong attachment with his cattle which is completely inseparable from him. 9 Veterinary camps (4 in Hooghly dist. and 5 in Bankura dist.) have been organized in which 4292 animals (2481 in Hooghly dist. and 1811 in Bankura dist.) were treated.

Many SHG members have benefited from animal husbandry programmes, who have been provided with 139 she goats (64 in Hooghly dist. and 75 in Bankura dist.) and 13 he buck (7 in Hooghly dist. and 6 in Bankura dist.).

Improved Agricultural Practices

92 compost pits (52 in Purbahauli, 27 in Kulateghari and 13 in Mulluk) have been prepared which have benefited the 92 concerned members.

सामाजिक एवं महिला विकास कार्यक्रम

12 स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविरों का (7 हुगली जिले में तथा 5 बाकुरा जिलें में) आयोजन किया गया जिसमें 1294 व्यक्ति (698 महिला तथा 596 पुरुष) 873 हुगली जिले में तथा 421 बाकुरा जिलें में लाभान्वित हुए।

आय संवर्द्धन गतिविधियां

परियोजना के प्रारम्भ से समूहों को आवश्यकता आधारित आय संवर्द्धन गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आय अर्जन हेतु 69 समूहों कें सदस्यों को कपड़ों की सिलाई के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 सिलाई मशीनें (28 हुगली जिले में तथा 5 बाकुरा जिलें में) प्रदान की गई हैं।

इफको की विशेष परियोजना "फल एवं सब्जी की खेती" जो कि जिला पुरुलिया (पश्चिमी बंगाल) के खण्ड झालदा–1 के 6 गांवों गुत्तीलोवा, अर्जुनडिही, बाघबिन्धा, चिरूताड़, पनरीही और बरुआकोचा में किसानों को चिरन्तरित आय के लिए घर के पिछवाड़े में, पड़त एवं ऊँची भूमि में उपयोग के लिए प्रदर्शन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी तकनीकी आदान और सहायता प्रदान कर रही है।

इसी तरह आसाम में आई.एफ.एफ.डी.सी., इफको अंगीकृत ग्राम बुराकुड़ी (जिला जोरहट) में ग्रामीण आजीविका सुधार की प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रही है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा समुदाय के साथ सहभागी योजना प्रक्रिया के दौरान सम्पन्न किये गये सहभागी ग्रामीण आंकलन के दौरान निर्मित की गई विभिन्न परियोजना गतिविधियां सम्पन्न की जा रही हैं।

XXIV. नाबार्ड जलग्रहण विकास परियोजना, निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश)

नाबार्ड, हैदराबाद द्वारा जलग्रहण विकास निधि (डब्ल्यू.डी. एल.) के अन्तर्गत निजामाबाद जिले में 3000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 वर्षों की समयावधि की स्वीकृत 3 जलग्रहण परियोजनाएँ क्रमशः धामबन्धा थान्डा, दम्मनपेट एवं गोविन्दपल्ली में आई.एफ.एफ. डी.सी. कार्यान्वित कर रही है।

क्षेत्रिय अलाभी ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत क्षेत्रीय स्त्रोत संगठन "वाटर सपोर्ट सर्विसेज एण्ड एक्टीविटीज नेटवर्क (वासान) संसाधन संस्था (आर. आर.ओ.) के साथ उनकी मदद से परियोजना क्रियान्वयन हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।

जलग्रहण विकास परियोजना, जिला निजामाबाद (आ.प्र.) के पूर्व क्षमता निर्माण चरण के दौरान ग्राम समुदाय द्वारा श्रमदान।

Shramdan by village community during pre-capacity building phase in Watershed Development Project, Dist. Nizamabad (A.P.)

Social Development

12 Health checkup camps (7 in Hooghly dist. and 5 in Bankura dist.) have been organized benefiting 1294 persons (698 female and 596 male) 873 in Hooghly dist and 421 in Bankura dist..

Income Generation Activity

Self Help Groups were encouraged to start need based Income Generation Activity. 33 sewing machines (28 in Hooghly dist. and 5 in Bankura dist.) have been provided to 69 SHGs for imparting training of sewing of cloths etc. to SHG members for income generation.

IFFDC is also providing technical inputs and facilitation services to the IFFCO's special project on "Fruit and Vegetable Cultivation" which is being implemented in 6 villages viz Gutilowa, Arjundihi, Baghbindha, Chirutarh, Panrihi and Baruakocha of block Jhalda-I, district Puruliya (West Bengal) to demonstrate the use of homestead, fallow and other uplands for sustainable income to the farmers.

Similarly in Assam state, IFFDC is facilitating the rural livelihood improvement process in IFFCO adopted village Burakuri (dist Jorhat). Various project interventions which are being undertaken in the village were prepared during the participatory planning process with the community through Participatory Rural Appraisal (PRA) conducted by IFFDC.

(XXIV) NABARD-WATERSHED DEVELOPMENT PROJECT, NIZAMABAD (A.P.)

With financial assistance of NABARD Hyderabad under its Watershed Development Fund (WDF) 3 watershed projects viz Dham Bandha Thanda, Dammanapet, and Govindpally with an area of 3000 hact in Nizamabad district are being implemented by IFFDC for 5 years duration.

Detailed discussions with the Regional Resource Organisation (RRO) "Water Support Services and Activities Network" (WASSAN) registered as non profitable trust were completed for implementation of the project under its facilitation.

286.37 हैक्टे. के लिए पूर्व क्षमता निर्माण चरण (सी.बी.बी.) प्रारम्भ कर दिया गया जिसमें सम्बन्धित समुदाय ने प्रत्येक जलग्रहण में 4 दिवसीय श्रमदान किया। ग्रामीण जल विकास समिति (वी.डब्ल्यू.डी.सी.) का निर्माण किया जा चुका है। वी.डब्ल्यू.डी.सी. सदस्यों की जल परियोजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया से ग्रामीण समुदाय की आजीविका पर इसके प्रभाव पर छमता निर्माण हेतु, करीमनगर में एक एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया जहां नाबार्ड द्वारा अनुदान जलग्रहण का पूर्ण क्रियान्वयन चरण (एफ.आई.पी.) का एक अन्य संस्था द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है।

XXV. समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आर.डी.पी.), अमरावती (महाराष्ट्र)

यह परियोजना जनवरी 2008 से इफको की सहायता से अमरावती, जिला (महाराष्ट्र) के चन्दुर रेलवे तालुका के 4 वर्षा आश्रित गांवों (मोगरा, धोत्रा, इकलारा तथा चन्दूर खेड़ा) में समग्र कृषि व जल स्त्रोत विकास की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की आजीविका उत्थान हेतु क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना 13 जनवरी, 2008 को समुदाय के लिए मोगरा गांव में एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन करके प्रारम्भ की गयी।

समुदाय लामबन्दी और प्रवेश बिन्दु गतिविधियां प्रारम्भ की जा चुकी हैं। सामुदायिक केन्द्र निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार, कुआं गहरीकरण आदि कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

1 तालाब का गहरीकरण पूरा किया जा चुका है तथा 19 किसानों को 14460 फीट सिंचन पाइप उपलब्ध कराये गये। एक आँखों की जांच शिविर का आयोजन (जिसमें 230 मरीजों का परीक्षण) किया गया। 3 महिलाओं को सिलाई मशीन तथा 6 किसानों को 12 बकरियां प्रदान कराई गयीं। एक मंदिर तथा एक स्कूल के पुनर्ननिर्माण में सहायता प्रदान की गयी।

डॉ. के. जी. वानखेडे, राज्य विपणन प्रबंधक, इफको, महाराष्ट्र, आई.एफ.एफ. डी.सी.–आई.आर.डी.पी. परियोजना उद्घाटन समारोह के दौरान गांव चंदूर रेल्वे, जिला अमरावती (महाराष्ट्र) में कृषक समुदाय को सम्बोधित करते हुए।

Dr. K. G. Wankhede, SMM, IFFCO, Maharashtra addressing the farming community during inaugural function of IFFDC-IRDP project at village Chandur Railway, Dist., Amravati (Maharashtra)

The pre Capacity Building Phase (CBP) has been started on 286.37 ha in which the concerned community undertook SHRAMDAN for four days in each watershed. Formation of Village Watershed Development Committees (VWDC) has been completed. To build the capacity of the members of the VWDCs on the implementation process of watershed project and its impact on livelihood of the rural community, an exposure visit has been organized to Karimnagar where Full Implementation Phase (FIP) of NABARD funded watershed project is being implemented by other organization.

XXV. INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT (IRDP), AMRAVATI (MAHARASHTRA)

The project is being implemented in 4 rainfed villages (Mogra, Dhotra, Eklara, and Chandur Kheda) of Chandur Railway Block in District Amravati (Maharashtra) with the support of IFFCO since Jan. 2008 to enhance livelihood of the rural community through integrated agriculture and water resources developmental activities. Project was launched on 13th January, 2008 at Mogra village by organizing an awareness seminar for the community.

Community mobilization and entry point activities have been undertaken. Construction of Community Center, renovation of pond, deepening of well have been started.

1 Pond deepening was completed and 14460 feet irrigation pipes were provided to 19 farmers. One eye check-up camp was organized (230 patients examined). Sewing machines were provided to 3 women and 12 goats were provided to 6 farmers. Renovation support was provided to one Temple and one School.

XXVI. समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना – शिवागंगई (तमिलनाडु)

यह परियोजना आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कराईकुडी, तालुका के सक्कोताई और कल्लल विकासखण्ड (जिला शिवागंगई) के सूखाग्रस्त 10 गांवों में जल स्त्रोत विकास के माध्यम से समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर गरीब ग्रामीण समुदाय के सामाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतू सितम्बर, 2007 से इफको की सहायता से क्रियान्वित की गयी। इस परियोजना का शुभारम्भ माननीय वित्तमन्त्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा नवम्बर, 2007 को आलमपट्टू गांव में किया गया। माननीय केन्द्रिय वित्त मन्त्री, श्री पी. चिदम्बरम ने परियोजना क्षेत्र का भ्रमण किया तथा वहाँ पर चल रही जल स्त्रोत विकास की गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने आई.एफ.एफ.डी.सी. अध्यक्ष श्री डी.के भट्ट को गांव आलमपट्टू में सम्मानित किया।

कराईकुड़ी में अभिमुखीकरण सह अनुभव आदान–प्रदान बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समानान्तर विभागों से परियोजना की अवधारण व पहुँचों पर अनुभवों का आदान–प्रदान किया।

प्रवेश बिन्दु गतिविधियाँ, समुदाय लामबन्दी प्रक्रिया तथा तालाब पुर्नोद्धार, सिंचाई सुविधा विकास, कृषि प्रणाली विकास, क्षमता निर्माण एवं सामजिक विकास पर परियोजना गतिविधियाँ प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

XXVI. INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT, SHIVAGANGAI (TAMILNADU)

The project is being implemented by IFFDC in drought prone 10 villages of Sakkottai and Kallal blocks of Karaikudi Taluka (Dist. Shivaganga) with the support of IFFCO since Sept. 2007 to improve the socio-economic status of the poor rural community by adopting integrated farming system approach through water resources development. It was inaugurated by Hon'ble Finance Minister Shri P.Chidambaram in Alampattu village in Nov. 2007. Hon'ble Minister visited the project area and appreciated the ongoing water resources development activities. He honoured Sh D. K. Bhatt, Chairman IFFDC at village Alampattu.

Convergence cum Expeerience sharing workshop was held at Karaikudi in which project concept and approaches have been shared with the line departments.

Entry point activities, community mobilization process and project interventions on renovation of ponds, development of irrigation facilities, farming system development, capacity building and social development have been started in the project villages.

As an entry point activity a pond at village Kandanur was deepend which with 12' deep water is now a scene of surprise. It is being utilized after a period of 70 years.

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम गांव आलमपट्टू, तालुका कराईकुड़ी, जिला शिवगंगई (तमिलनाडु) में "समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना" का उद्घाटन करते हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, श्री डी.के. भट्ट, अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी. तथा मंच पर आसीन श्री के. चिदम्बरम, श्री एन. सुन्दरम (विधायक) एवं श्री पी.के. बंसल, जिला कलेक्टर।

Hon'ble Union Finance Minister Sh. P. Chidambaram inaugurating "Integrated Rural Development Project" at village Alampattu, Taluka Karaikudi, District Sivagangai (Tamilnadu), Sh. D.K. Bhatt, Chairman IFFDC presided over the function, Sh. K. Chidambaram, Sh. N. Sundaram (MLA) and Sh. P.K. Bansal, District Collector are also on the dias.

आई.आर.डी.पी. परियोजना क्षेत्र कराईकुड़ी (तमिलनाडु) में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा गहरीकृत, पानी से लबालब भरे तालाब का दृश्य।

View of pond full of water, deepened by IFFDC in IRDP project area Karaikudi (Tamilnadu)

प्रवेश बिन्दु गतिविधि के तौर पर कण्डानूर गांव में एक तालाब का गहरीकरण किया गया जो अब 12 फुट गहरे पानी के साथ एक अद्भुद् दृश्य है। इसका उपयोग 70 साल बाद किया जा रहा है।

5 गांवों में 40 वर्ष बाद बड़े तालाबों का गहरीकरण 40 वर्षों के पश्चात् किया गया इसमें पानी होने से क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं। वे परम्परागत तरीके से साल में धान की एक फसल ही ले पाते थे और अब वे वर्ष में दूसरी फसल भी ले सकते हैं। कण्डानूर और पुदवायल जैसे गावों में एकत्रित पानी से 4 साल से पड़ी बंजर जमीन में खेती की गई। 7 तालाबों का पुर्नोद्धार किया जा चुका है। किसानों को 163 क्रान्तिक आदान किट और 599 कृषि उपकरण (फावड़ा, गैंती, उन्नत हांसिया) उपलब्ध कराये गये। परियोजना क्षेत्र में 11882 फलदार पौधे रोपित भी किये गये।

माननीय केन्द्रिय वित्त मन्त्री श्री पी. चिदम्बरम, आई.एफ.एफ.डी.सी. अध्यक्ष श्री दया कृष्ण भट्ट को गांव आलमपट्टू, तालुका कराईकुढ़ी, जिला शिवगंगई (तमिलनाडु) की सराहना के दौरान सम्मानित करते हुए।

Hon'ble Union Finance Minister Sh. P. Chidambaram honouring Sh. D.K. Bhatt, Chairman IFFDC at village Alampattu, Taluka Karaikudi, District Sivagangai (Tamilnadu)

5 village big ponds have been deepened after a period of 40 years much to the pleasure of people of the area because the water storage, is an assurance for traditional single crop of paddy and in some cases, paveway for raising 2nd crop also. With the harvested water, lands lying barren for the past 4 years have been cultivated in Kandanur & Pudduvayal villages. Renovation of 7 tanks has been completed. 163 Critical Input Package (CIP) kits and 599 agril implements (spade, Pick-axe, improved sickles) were provided to the farmers. 11882 fruit saplings have also been planted in project villages.

कृषक महिलाओं/पुरुषों के लिए 6 प्रशिक्षिण विभिन्न पहलुओं पर एवं पैरा प्रोफेशनल के लिए 2 प्रशिक्षण प्रदान किए गये। श्रम में कमी लाने के लिए 8 धूम्ररहित चूल्हा, एवं 3 धकेलकर चलाने वाले ठेले उपलब्ध कराये गये। स्वयं सहायता समूहों को सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए 12 सिलाई मशीनें उपलब्ध करायी गयी।

6 trainings for farm women/men on various aspects and 2 trainings for para professionals have been imparted. To reduce the drudgery, 8 smokeless chullas and 3 push carts were provided. 12 sewing machines were provided to SHGs to establish tailoring training centre.

घर के अहाते में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को उन्नत नस्ल के 780 चूजे वितरित किये गये। आयजनित गतिविधियों में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एच.एल.एल.) के उपभोक्ता उत्पादों की (होम डिलीवरी के आधार पर) एच.एल.एल. शक्ति परियोजना के अन्तर्गत इनके उत्पाद 4 गांवों में समूह सदस्यों द्वारा लिये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें 185 महिलाओं ने भाग लिया।

आई.एफ.एफ.डी.सी.–आई.आर.डी.पी. भ्रमण के दौरान गांव पुदुवायल, जिला शिवगंगई (तमिलनाडु) में समुदाय सदस्यों के साथ आई.एफ.एफ.डी.सी. अधिकारीगण।

IFFDC Officials alongwith community during visit to IFFDC - IRDP project at village Puduvuyal, Dist. Shivagangai (Tamilnadu).

To promote backyard poultry, 780 units of improved breed of chicks were provided to SHG members. Income generation activity by sale of Hindustan Lever Limited (HLL) consumer products (at home to home delivery basis) under HLL's Sakthi Project has been taken up by SHG members in 4 villages. International Women Day was celebrated in which 185 women participated.

XXVII. मेले एवं प्रदर्शनियाँ

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने भारत व्यापार संवर्द्धन संस्था (आई. टी.पी.ओ.) द्वारा नवम्बर 14–27, 2007 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित "भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई. आई.टी.एफ.)–2007" में इफको पण्डाल के अन्तर्गत एक स्टाल लगायी। इस स्टाल में आई.एफ.एफ.डी.सी. की विभिन्न ग्रामीण विकासात्मक गतिविधियों को चित्रपट्ट, नमूनों, मॉडलों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया जिसमें से मृदा–जल संरक्षण के विभिन्न उपायों के प्रभाव को संकेतिक युक्त जलग्रहण विकास का मॉडल आगन्तुकों के लिए मुख्य आकर्षण था। इससे संस्था वृहद प्रचार व छवि को उभारने में मदद मिली। इसके द्वारा संवर्द्धित विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ व हस्ताकला उत्पादों के विपणन को बढ़ाने हेतु विभन्न उत्पादों जैसे आंवला, मुरब्बा, अचार, अगरबत्ती, हस्तकला वस्तुऐं जैसे नारियल जटा के खिलौने, दीवार पर टांगने वाले शोभनीय उत्पाद, छतरियाँ, मूर्तियाँ, नक्काशी की वस्तुऐं आदि को बिक्री हेतु प्रदर्शित किया। इन उत्पादों की 0.50 लाख रु. की बिक्री की एवं विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं ने इनकी काफी सराहना की। भारत एवं विदेश के 2.5 लाख आगन्तुकों को आई. एफ.एफ.डी.सी. की सफल कहानियों पर आधारित फिल्में दिखाई एवं संचालित विभिन्न गतिविधियों से संबन्धित साहित्य का वितरण भी किया।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा "दक्षिण एशिया सम्मेलन 2008 – सार्क देशों में भूख एवं गरीबी निवारण के लिए विज्ञान आधारित कृषि रूपान्तरण" में मार्च 5–7, 2008 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कम्पलैक्स, पूसा परिसर, नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी

श्री डी.के भट्ट, अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी. "भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.)–2007" के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इफको पवेलियन के अन्तर्गत लगाये गये आई.एफ.एफ.डी.सी. प्रदर्शनी स्टाल का उद्घाटन करते हुए।

Sh. D.K. Bhatt, Chairman, IFFDC, inaugurating IFFDC Exhibition Stall put-up under IFFCO pavilion at Pratat Maidan, New Delhi during "India International Trade Fair (IITF)-2007"

XXVII. FAIRS AND EXHIBITIONS

IFFDC put up a stall under the pavilion of IFFCO in "India International Trade Fair (IITF) – 2007" at Pragati Maidan, New Delhi during Novemebr 14 – 27, 2007 organised by India Trade Promotion Organisation (ITPO). In the stall, various rural developmental activities of IFFDC were depicted through panels, samples, models etc in which watershed development model indicating impact of different SWC measures was the main attraction for the visitors. It helped in providing wider publicity to boost the image of the organization. To promote marketing of the food products & handicrafts items prepared by its promoted Self Help Groups from different states, various products viz Anola compote, pickles, Scent sticks, handicraft items like coir baubles, wall hangings, umbrellas, sculpture, carving items etc were exhibited for sale. These products worth Rs 0.50 lakhwere sold and highly liked and appreciated by different strata of consumers. Relevant literature on various ongoing activities was distributed and films of success stories of IFFDC were projected to about 2.5 lakh visitors from India and abroad.

An exhibition stall based on galaxy of activities in "South Asia Conference 2008 – Science based Agricultural Transformation towards Alleviation of Hunger and Poverty in SAARC Countries" was also put up by IFFDC at National Agriculture Science Complex, Pusa Campus, New Delhi during March 5

दक्षिण एशिया सम्मेलन–2008 के दौरान पूसा, नई दिल्ली में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का एक दृश्य।

A view of IFFDC Exhibition stall put up at Pusa, New Delhi during South Asia Conference 2008.

स्टाल लगाई गयी। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय श्री शरद पंवार, केन्द्रिय कृषि मन्त्री ने किया एवं इसमें अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के सम्मानित मंत्रियों सहित 350 उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। सार्क देशों से लगभग 500 आगन्तुकों ने इस प्रदर्शनी स्टाल का भ्रमण किया एवं देश में गरीबी निवारण हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से संचालित विविध गतिविधियों की प्रशंसा की।

इसी प्रकार आई.एफ.एफ.डी.सी. ने एमिटी इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल द्वारा फरवरी 20–22, 2008 को नोएडा (उ.प्र.) में आयोजित "लोग, अनुराग, धर्म एवं शान्ति – विश्व स्तरीय संस्थाओं के लिए चुनौतियां" पर आयोजित "दसवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन – इनबुस (इन्टरनेशनल बिजनेस होरिजोन)" में भी ग्रामीण समुदाय विकास की विभिन्न गतिविधियों की प्रदर्शनीयुक्त अपनी एक स्टाल लगायी। लगभग 500 प्रतिभागियों मय अधिशाषियों, निगमों के नेताओं तथा युवा प्रबन्धकों ने आई.एफ.एफ.डी.सी. प्रदर्शनी का भ्रमण किया तथा इसके प्रथक मिशन, अभिनवों, प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहभागी ग्रामीण विकास की चिरस्थायित्व की जानकारी प्राप्त की एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा गरीबी निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की।

XXVIII. कृषकों को गुणवत्तापूर्ण आदानों की आपूर्ति

आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषक सेवा केन्द्र

उत्तर प्रदेश राज्य के विशेषकर उन क्षेत्रों/जिलों में जहाँ सहकारी तंत्र/प्रणाली बहुत कमजोर है, वहाँ उत्कृष्ट कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषक सेवा केन्द्र खोलकर इफको उर्वरक, जैव उर्वरक तथा उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संचालित इस प्रकार के 1457 केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 3,46,569 मैट्रिक टन इफको उर्वरक (2,71,067 मैट्रिक टन यूरिया, 42,405 मैट्रिक टन डी.ए.पी. तथा 33,097 मैट्रिक टन एन.पी.के.) की आपूर्ति की गयी। कृषक सेवा केन्द्रों के प्रभारियों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सन्तुलित खाद के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु, मिट्टी की जांच के लिए सचल मृदा परीक्षण वाहन (एम.एस.टी.वी.) शुरू की है ताकि किसानों को मिट्टी जांच की सेवाऐं गांव में ही उपलब्ध करायी जा सकें।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में समितियों के आसपास के गांवों में गेहूँ बीज बहुलीकरण कार्यक्रम (एस.एम.पी.) भी आरम्भ किया है। क्षेत्र के किसानों को समितियों तथा किसान सेवा केद्रों के माध्यम से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

– 7, 2008. The conference was inaugurated by hon'ble Sh Sharad Panwar, Union Minister of Agriculture, India and about 350 dignitaries including hon'ble Ministers of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka participated in it. About 500 visitors from SAARC countries visited the exhibition stall and appreciated the diversified activities being undertaken by IFFDC through various projects to alleviate rural poverty in the country.

Similarly, IFFDC also put up its stall depicting various rural community developmental activities in "Tenth International Conference – INBUSH (International Business Horizon)" on "People, Passion, Patience and Peace – Challenges for Global Organisations" organized by Amity International Business School during February 20 – 22, 2008 at Noida (U.P.). About 500 participants including executives, corporate leaders and budding young managers visited IFFDC exhibition, acquainted with its distinct vision, innovations, competitiveness and sustenance of participatory rural development and highly appreciated the efforts being made by IFFDC towards poverty alleviation.

XXVIII. SUPPLY OF QUALITY INPUTS TO FARMERS

IFFDC Krishak Sewa Kendras

To provide quality agricultural inputs, IFFDC has also undertaken supply of IFFCO fertilizers, biofertilisers and quality seeds etc. by opening IFFDC Krishak Seva Kendras in Uttar Pradesh specially in the areas/ districts where cooperative network/ structure is very weak. 1457 such Centers operating in Uttar Pradesh during the year supplied 3,46,569 MT of IFFCO fertilizers ie 2,71,067 MT urea, 42,405 MT DAP and 33,097 MT NPK. Regular trainings are being organised for the incharges of the Krishak Sewa Kendras. Further, to popularize the balanced fertilizer use, IFFDC has pressed in to service a Mobile Soil Testing Van (MSTV) to provide soil testing services to the farmers in the villages itself.

IFFDC has also undertaken Seed Multiplication Programme (SMP) of Wheat in villages near by PFFCS and kisan sewa kendras in Sultanpur district (U.P.). The certified seed shall be made available to the farmers of the area through PFFCS and kisan sewa kendras.

XXIX. परामर्श सेवाऐं

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना, पश्चिमी भारत बारानी खेती परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के दौरान विविध क्षेत्रों जैसे– प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल ग्रहण विकास, आजीविका सुधार, संस्थागत विकास (स्वयं सहायता समूह तथा सहकारिता), सामुदायिक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, लघु उद्यम विकास, प्रभाव आंकलन एवं मूल्यांकन अध्ययन आदि में (सहभागिता को अपनाकर, महिलाओं को अग्रणी बनाकर तथा गरीबी को उजागर करने की पद्धतियों को अपनाकर) विशेषता एवं विशेषज्ञता प्राप्त की गई।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों जैसे सेव द चिल्ड्रन (यूके) यूनिसेफ, सिडा, प्रेगमेटीक्स, इफको, कोडरेट, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संधि (आई.सी.ए.) न्यू कॉन्सेप्ट इर्न्फोमेशन सिस्टम प्रा. लिमिटेड–नई दिल्ली, पेज परियेाजना (हरियाणा सरकार), इंडीकस इत्यादि को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा उड़ीसा राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे – सूखे से रक्षा, सामाजिक विकास, बाल विकास कार्यक्रम का मात्रात्मक सहभागीता मूल्यांकन, जलग्रहण विकास, संस्थागत विकास (स्वयं सहायता समूह का निर्माण) एवं ग्रामीण उद्यमिता आदि में अपने विशेषज्ञों द्वारा परामर्श सेवाऐं प्रदान की गईं।

XXIX. CONSULTANCY SERVICES

During the successful implementation of the Farm Forestry Projects, Western India Rainfed Farming Project (WIRFP), and other livelihoods projects. IFFDC has developed expertise and specialisation in diversified fields viz; Natural Resource Management, Watershed Development, Livelihood Improvement, Institutional Development (SHGs and Cooperatives), Community Health, Women Empowerment, Microenterprise development, Impact Assessment & Evaluation Studies etc. by adopting participatory, gender mainstreaming and poverty focused approaches and methodologies.

IFFDC has been providing consultancy inputs to important international and national organisations like Save the Children, (UK), UNICEF, SIDA, Pragmatix, IFFCO, Cordet, International Cooperative Alliance (ICA), New Concept Information System Ltd. New Delhi, PAGE project (Govt. of Haryana), INDICUS etc. in the states of U.P., Rajasthan, M.P., Haryana, Chattishgarh, Uttaranchal and Orissa through its team of professionals in the areas of drought proofing, social development, quantified participatory appraisal of child environment program, Watershed Development, Institutional Development (formation of SHGs) and Rural Entrepreneurship etc. Thus is a highly appreciable effort.

डॉ. पी.एस. मरवाहा, मुख्य कार्यकारी, आई.एफ.एफ.डी.सी. "सहकारिता के माध्यम से कृषकों की आय वृद्धि एवं गरीबी निवारण" विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी मैत्री (आई.सी.ए.) द्वारा एफ.एम.डी.आई., गुडगांव में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सहभागियों के साथ।

Dr. P.S. Marwaha, Chief Executive, IFFDC alongwith international participants during training programme on "Enhancement of Farmer's Income and Poverty Reduction through Cooperatives" organised by International Cooperative Alliance (ICA) at FMDI, Gurgaon.

XXX. आभार

आपका निदेशक मंडल आलोच्य वर्ष के दौरान सभी वर्गों के कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर किये गये सतत और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता है। कर्मचारियों के इन प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के बिना समिति इन उत्साहजनक परिणामों एवं उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाती।

आपके निदेशक, इफको के निदेशक मंडल एवं प्रबन्धन, सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों, स्टेट इनोवेशनस इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेज संस्थान (सिफ्पसा), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आई.डी.ए.), जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं वानस्पतिक तेल विकास बोर्ड, इफको–छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड (आई.सी.पी.एल.), गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं विशेषतः वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर, उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनसे निरन्तर सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन मिला।

निदेशक मंडल यू.एस.ए.आई.डी., विश्व बैंक, इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट (इफाड), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था (आई.एल.ओ.) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, राज्य सरकारों एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये गये सहयोग एवं आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद करता है।

आपके निदेशक, सदस्य समितियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किये गये निरन्तर सहयोग हेतु अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समिति के प्रबंधन में अपना विश्वास बनाए रखा।

निदेशक मंडल आश्वासन देना चाहता है कि आपकी समिति बहुमुखी प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करती रहेगी और आगामी वर्षों में नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(दया कृष्ण भट्ट)
अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी.

XXX. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedicated efforts made by the employees of the society at all levels during the year, but for whose unrelenting efforts and hard work, such encouraging results and achievements of the society would not have been possible.

Your Directors wish to acknowledge with gratitude the continued support and valuable guidance extended by IFFCO Board and Management, concerned Government Agencies, State Innovations in Family Planning Services Agency (SIFPSA), International Development Association (IDA), District Poverty Initiatives Program (DPIP), National Oil Seeds and Vegetable Oil Development Board (NOVOD), IFFCO-Chhattisgarh Power Limited (ICPL), National Afforestation and Eco-Development Board (NAEB) and various Research Institutes specially Forest Research Institute (FRI), Dehradun; Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur, Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, National Research Centre for Agroforestry, Jhansi and National Research Center for Soyabean (NRCS), Indore.

The Board of Directors also acknowledges with thanks the cooperation and financial support provided by USAID, World Bank, International Fund for Agriculture Development (IFAD), International Labor Organisation (ILO), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, State Governments and Govt. of India in implementation of project activities.

Your Directors express deep gratitude to the member societies for their continued support and reposing their trust in the management of the society.

The Board of Directors would like to assure that your society would continue to strive to achieve all-round progress and establish new records in the coming years.

For and on behalf of Board of Directors

(D.K.Bhatt)
Chairman, IFFDC